



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 1, 1980/कार्तिक 10, 1902

No. 44]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 1, 1980/KARTIKA 10, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़ कर)
केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the
Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 1980

का० घा० 2018.—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मे० माडर्न पैकेजिंग लिमिटेड का कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण के निरस्त-करण को अधिसूचित करती है। (पंजीकरण प्रमाण-पत्र सं० 24/1970)

2. यह भी अधिसूचित किया जाता है कि उपक्रम, जो पहले आवेदक कम्पनी के स्वामित्व में था, तथा जो धारिता कम्पनी को हस्तांतरित हुआ गया है (धारिता कम्पनी के साथ एकीकरण के उद्देश्य के लिये, आवेदक कम्पनी तथा इसके हिस्सेधारियों के मध्य व्यवस्था योजना के माध्यम से), अपनी कलर कार्टन्स लिमिटेड नामक धारिता कम्पनी के एक एकक के रूप में, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 20(क)(ii) के उपबन्धों द्वारा, यथापूर्व शासित रहेगा। यह भी अधिसूचित किया जाता है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्य आनुयागिक उपबन्ध भी कार्यम उपक्रम पर यथापूर्व लागू रहेंगे।

[सं० 16/29/80-एम० 3]

चन्द्रकान्त खुशालदास, निदेशक

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 13th October, 1980

S.O. 2018.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies & Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of Messrs Modern Packagings Limited under the said Act (Certificate of Registration No. 24/1970).

2. It is further notified that the undertaking which was formerly owned by applicant company and which has been transferred to holding company (through the scheme of arrangement between the applicant company and its shareholders for the purpose of amalgamation with the holding company), will continue to be governed by the provisions of the Section 20(a)(ii) of the MRTP Act, as a unit of the holding company, namely Colour Cartons Limited. It is also notified that the other consequential provisions of the MRTP Act will also continue to apply to the said undertaking.

[No. 16/29/80-M. III]

C. KHUSHALDAS, Director

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 1980

का० प्रा० 2919.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में यह निदेश देते हैं कि उनके नियंत्रण के अधीन रहते हुए और जब तक और आदेश नहीं किए जाएं, प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक, संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के समक्ष में, शपथ अधिनियम, 1969 (1969 का 44) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा।

[सं० यू-11030/2/80-यू टी एल]

सुदेश कुमार, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 14th October, 1980

S.O. 2919.—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that, subject to his control and until further orders, the Administrator of every Union territory, shall, in relation to the Union territory concerned, exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the provisions of clause (b) of sub-section (2) of section 3 of the Oaths Act, 1969 (44 of 1969).

[No. U-11030/2/80-UTL]

SUDESH KUMAR, Desk Officer

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 1980

का० प्रा० 2920.—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में गृह मंत्रालय के निम्नलिखित कार्यालय को, जिस के कर्मचारी वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है।

1. समन्वय निदेशालय पुलिस कम्प्यूटर प्रार० के० पुरम, नई दिल्ली।

[संख्या 12017/1/80-हिन्दी]

अशोक कुमार वर्मा, उप सचिव

New Delhi, the 15th October, 1980

S.O. 2920.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for the official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following office of the Ministry of Home Affairs, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi.

1. Office of the Director Coordination (Police Computers) R. K. Puram, New Delhi.

[No. 12017/1/80-Hindi]

ASHOK KUMAR VARMA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 19 जून, 1980

प्राय-कर

का० प्रा० 2921.—केन्द्रीय सरकार, प्राय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उप-धारा (23 ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "ब्रोच सोशल सर्विस सोसाइटी" को निर्धारण वर्ष 1980-81 के लिये उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 3488/का० सं० 197/73/79-प्रा० क० (ए 1)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 19th June, 1980

INCOME-TAX

S.O. 2921.—In exercise of the powers conferred by clause (V) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961, (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Broach Social Service Society" for the purpose of the said section for the assessment year 1980-81.

[No. 3488/F. No. 197/73/79-IT(AI)]

का० प्रा० 2922.—केन्द्रीय सरकार, प्राय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उप-धारा (23 ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "जे० एन० टाटा एंडोमेंट मुम्बई" को निर्धारण वर्ष 1977-78 से 1980-81 तक के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 3478/का० सं० 197/27/79-प्रा० क० (ए 1)]

S.O. 2922.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "J. N. Tata Endowment Bombay" for the purpose of the said section for the assessment year(s) 1977-78 to 1980-81.

[No. 3478/F. No. 197/27/79-IT(AI)]

का० प्रा० 2923.—केन्द्रीय सरकार, प्राय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उप-धारा (23 ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "कैंसर पेशेन्स एंड एसोसिएशन, मुम्बई" को निर्धारण वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 3484/का० सं० 197/157/79-प्रा० क० (ए 1)]

S.O. 2923.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Cancer Patients Aid Association, Bombay" for the purpose of the said section for the assessment year(s) 1978-79, 1979-80 and 1980-81.

[No. 3484/F. No. 197/157/79-IT(AI)]

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1980

का० प्रा० 2924.—केन्द्रीय सरकार, प्राय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उप-धारा (23 ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "दि चर्च ऑफ नॉर्थ इण्डिया काउंसिल फार बाइबल केयर" को निर्धारण वर्ष 1976-77 से 1980-81 तक के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 3507/का० सं० 197/101/78-प्रा० क० (ए 1)]

New Delhi, the 1st July, 1980

S.O. 2924.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Church of North India Council for Child Care" for the purpose of the said section for the assessment years 1976-77 to 1980-81.

[No. 3507/F. No. 197/101/78-IT(AI)]

का० प्रा० 2925.—केन्द्रीय सरकार, प्राय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उप-धारा (23 ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "सेण्ट मेरी नर्सिंग होम, गोमती-पुर, ब्रह्मदाबाद" को निर्धारित वर्ष 1977-78 से 1980-81 तक के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 3509/का० सं० 197/20/79-प्रा० क० (ए 1)]

S.O. 2925.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "St. Mary's Nursing Home, Gomtipur, Ahmedabad" for the purpose of the said section for the assessment year(s) 1977-78 to 1980-81.

[No. 3509/F. No. 197/20/79-IT(AI)]

का० प्रा० 2926.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23 ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "दि नासिक पंचवटी पंजरापोल" को निर्धारण वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 3510/का० सं० 197/193/78-प्रा० क० (ए 1)]

S.O. 2926.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies, "The Nasik Panchvati Panjrapole" for the purpose of the said section for the assessment years 1978-79, 1979-80 and 1980-81.

[No. 3510/F. No. 197/193/78-IT(AI)]

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1980

का० प्रा० 2927.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23 ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "भारतीय भाषा परिषद्" को निर्धारण वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 3513/का० सं० 197/15/80-प्रा० क० (ए 1)]

New Delhi, the 2nd July, 1980

S.O. 2927.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Bharatiya Bhasha Parishad" for the purpose of the said section for the assessment years 1978-79, 1979-80 and 1980-81.

[No. 3513/F. No. 197/15/80-IT(AI)]

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1980

का० प्रा० 2928.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23 ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "इण्डियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन" को निर्धारण वर्ष 1972-73 से 1980-81 तक के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 3515/का० सं० 197/27/80-प्रा० क० (ए 1)]

New Delhi, the 4th July, 1980

S.O. 2928.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Indian Standards Institution" for the purpose of the said section for the assessment years 1972-73 to 1980-81.

[No. 3515/F. No. 197/27/80-IT(AI)]

का० प्रा० 2929.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23 ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "पब्लिक एण्टरप्राइजेज सेंटर फॉर कंटीन्यूइंग एजुकेशन नई दिल्ली" को निर्धारण वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 3517/का० सं० 197/182/79-प्रा० क० (ए 1)]

S.O. 2929.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Public Enterprises Centre for Continuing Education,

New Delhi" for the purpose of the said section for the assessment years 1978-79, 1979-80 and 1980-81.

[No. 3517/F. No. 197/182/79-IT(AI)]

का० प्रा० 2930.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23 ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "आंध्र प्रदेश ललित कला एकादमी" को निर्धारण वर्ष 1975-76 से 1980-81 तक के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 3518/का० सं० 197/37/78-प्रा० क० (ए 1)]

S.O. 2930.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Andhra Pradesh Lalit Kala Akademi" for the purpose of the said section for the assessment years 1975-76 to 1980-81.

[No. 3518/F. No. 197/37/78-IT(AI)]

का० प्रा० 2931.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23 ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अस्सिस्टेंस" को निर्धारण वर्ष 1963-64 से 1980-81 तक के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 3519/का० सं० 197/100/78-प्रा० क० (ए 1)]

S.O. 2931.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Institute of Public Assistance" for the purpose of the said section for the assessment years 1963-64 to 1980-81.

[No. 3519/F. No. 197/100/78-IT(AI)]

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1980

का० प्रा० 2932.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23 ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "ग्रेटर विसाखा लेप्रोसी ट्रीटमेंट एण्ड हेल्थ एजुकेशन स्कीम" को निर्धारण वर्ष 1975-76 से 1980-81 तक के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 3591/का० सं० 197/105/80-प्रा० क० (ए 1)]

New Delhi, the 16th July, 1980

S.O. 2932.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Greater Visakha Leprosy Treatment and Health Education Scheme" for the purpose of the said section for the assessment years 1975-76 to 1980-81.

[No. 3591/F. No. 197/105/80-IT(AI)]

का० प्रा० 2933.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23 ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री सत्या साई सेंट्रल ट्रस्ट मुम्बई" को निर्धारण वर्ष 1977-78 से 1980-81 तक के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 3592/का० सं० 197/50/79-प्रा० क० (ए 1)]

S.O. 2933.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Sathya Sai Central Trust Bombay" for the purpose of the said section for the assessment years 1977-78 to 1980-81.

[No. 3592/F. No. 197/50/79-IT(AI)]

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1980

कां.प्रा. 2934—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "राजस्थान गो-सेवा संघ जयपुर" को निर्धारण वर्ष 1977-78 से 1980-81 तक के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं. 3620/फा.सं. 197/187/79-प्रा.कं. (ए 1)]

New Delhi, the 7th August, 1980

S.O. 2934.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Rajasthan Go-Seva Sangh Jaipur" for the purpose of the said section for the assessment year(s) 1977-78 to 1980-81.

[No. 3620/F. No. 197/187/79-IT(AI)]

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1980

कां.प्रा. 2935—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "एन ए बी लाइन्स होम फॉर एजिंग प्लाइड" को निर्धारण वर्ष 1976-77 से 1980-81 तक के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं. 3622/फा.सं. 197/165/78 प्रा.कं. (ए 1)]

New Delhi, the 10th August, 1980

S.O. 2935.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "NAB Lions Home for Aging Blind" for the purpose of the said section for the assessment year(s) 1976-77 to 1980-81.

[No. 3622/F. No. 197/165/78-IT(AI)]

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1980

कां.प्रा. 2936—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23 ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "त्रिपुरा रिलीफ कमिटी" को निर्धारण वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं. 3642/फा.सं. 197/129/80-प्रा.कं. (ए 1)]

New Delhi, the 30th August, 1980

S.O. 2936.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Tripura Relief Committee" for the purpose of the said section for the assessment year(s) 1980-81 to 1982-83.

[No. 3642/F. No. 197/129/80-IT(AI)]

कां.प्रा. 2937—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "सेंट जोसेफ एजुकेशन एण्ड मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, मुम्बई" को निर्धारण वर्ष 1978-79 से 1981-82 तक के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं. 3643/फा.सं. 197/193/79 प्रा.कं. (ए 1)]

S.O. 2937.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "St. Joseph's Education and Medical Relief Society, Bombay" for the purpose of the said section for the assessment year(s) 1978-79 to 1981-82.

[No. 3643/F. No. 197/193/79-IT(AI)]

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1980

कां.प्रा. 2938—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "दि एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री

ग्रुप इंडिया" को निर्धारण वर्ष 1974-75 से 1981-82 तक के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं. 3652/फा.सं. 197/179/77-प्रा.कं. (ए 1)]

New Delhi, the 10th September, 1980

S.O. 2938.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Associated Chambers of Commerce and Industry of India" for the purpose of the said section for the assessment years 1974-75 to 1981-82.

[No. 3652/F. No. 197/179/77-IT(AI)]

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1980

कां.प्रा. 2939—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23 ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "लिटिल सिस्टर्स आफ दि पुर, मद्रास" को निर्धारण वर्ष 1978-79 से 1980-81 तक के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं. 3665/फा.सं. 197/58/80-प्रा.कं. (ए 1)]

New Delhi, the 18th September, 1980

S.O. 2939.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Little Sisters of the Poor, Madras" for the purpose of the said section for the assessment years 1978-79 to 1980-81.

[No. 3665/F. No. 197/58/80-IT(AI)]

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1980

कां.प्रा. 2940—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23 ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "दी लक्ष्मणमूल्ला डिस्पेंसरी एण्ड रीहैबिलिटेशन सेन्टर, तपोवन" को निर्धारण वर्ष 1978-79 से 1981-82 तक के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं. 3678/फा.सं. 197/151/79-प्रा.कं. (ए 1)]

New Delhi, the 29th September, 1980

S.O. 2940.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Lakshmanjula Dispensary and Rehabilitation Centre, Tapovan" for the purpose of the said section for the assessment year(s) 1978-79 to 1981-82.

[No. 3678/F. No. 197/151/79-IT(AI)]

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 1980

कां.प्रा. 2941—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23 ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "पंजाब एमलगाटेड फंड फार दि वेलफेयर आफ एक्स सर्विसमैन" को निर्धारण वर्ष 1978-79 के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं. 3682/फा.सं. 197/110/79-प्रा.कं. (ए 1)]

New Delhi, the 1st October, 1980

S.O. 2941.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Punjab Amalgamated Fund for the Welfare of Ex-servicemen" for the purpose of the said section for and from the assessment year(s) 1978-79.

[No. 3682/F. No. 197/110/79-IT(AI)]

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 1980

कां.प्रा. 2942—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23 ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "केसर पेशेन्ट्स एंड गर्सिएशन, मुम्बई" को निर्धारण वर्ष 1981-82 के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं. 3704/फा.सं. 197/169/80-प्रा.कं. (ए 1)]

S.O. 2942.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Cancer Patients Aid Association, Bombay" for the purpose of the said section for the assessment year 1981-82.

[No. 3704/F. No. 197/169/80-IT(AI)]

कां.प्रा. 2943.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23 ग) के खण्ड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "सर सासून डेविड ट्रस्ट फण्ड" को निर्धारण वर्ष 1972-73 से 1981-82 तक के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं. 3705/कां.सं. 197/151/78-आं.कं. (एI)]

S.O. 2943.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sir Sasoon David Trust Fund" for the assessment year(s) 1972-73 to 1981-82.

[No. 3705/F. No. 197/151/78-IT(AI)]

कां.प्रा. 2944.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23 ग) के खण्ड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि नासिक पंचवटी पंजरा-पोल" को निर्धारण वर्ष 1981-82 के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं. 3706/कां.सं. 197/193/78-आं.कं. (एI)]

बी०एम० सिंह, प्रवर सचिव

S.O. 2944.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Nasik Panchvati Panjrapole" for the purpose of the said section for the assessment year 1981-82.

[No. 3706/F. No. 197/193/78-IT(AI)]

B. M. SINGH, Under Secy.

प्रवेश

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 1980

स्टाम्प

कां.प्रा. 2945.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (i) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उस शुल्क को माफ करती है, जो कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले ऋण-पत्रों के रूप में बन्ध-पत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रसार्य है।

[सं. 20/80/स्टाम्प. कां.सं. 33/33/80-बि०क]

जी० एस० मेहरा, प्रवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 13th October, 1980

STAMP

S.O. 2945.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty chargeable under the said Act in respect of bonds in the form of debentures to be issued from time to time by the Agricultural Refinance and Development Corporation.

[No. 20/80-Stamp. F. No. 33/33/80-ST]

G. S. MEHRA, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1980

(आय-कर)

कां.प्रा. 2946.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और हम बाबत सभी पूर्व अधि-सूचनाओं को अधिकारित करते हुए, निवेदन देता है कि इसने उपाखण्ड अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट आय-कर प्रायुक्त, उसके स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट मुख्यालय सहित, ऐसे क्षेत्रों या ऐसे व्यक्तियों या ऐसे वगैरे के व्यक्तियों या ऐसे प्राय या ऐसे वगैरे की आय या ऐसे मामलों या ऐसे वगैरे के मामलों की बाबत, जो उक्त स्तम्भ 3 में निविष्ट आय-कर सँकल, बाडों या जिलों के अन्तर्गत आते हैं, अपने कृत्यों का पालन करेंगे।

परन्तु यह कि आय-कर प्रायुक्त ऐसे व्यक्तियों या ऐसे मामलों की बाबत भी, जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा उनके अधीनस्थ किसी आय-कर प्राधिकारी को समनुविष्ट किए गए हों या किए जाए, अपने कृत्यों का पालन करेंगे।

परन्तु यह और कि प्रायुक्त ऐसे व्यक्तियों या ऐसे मामलों की बाबत, जो उसकी अधिकारिता के बाहर किसी आय-कर प्राधिकारी को समनुविष्ट किए गए हैं या किए जाए, अपने कृत्यों का पालन नहीं करेंगे।

अनुसूची

आय-कर प्रायुक्त	मुख्यालय	अधिकारिता
1	2	3
15 भोपाल	भोपाल	1. भोपाल जिला 2. बेतूल जिला 3. भिड जिला 4. बतिया जिला 5. देवास जिला 6. धार जिला 7. खालियर जिला 8. गुना जिला 9. होशंगाबाद जिला 10. इन्दौर जिला 11. खण्डवा जिला 12. अरगोन जिला 13. मन्दासौर जिला 14. सुरेता जिला 15. रायसेन जिला 16. राजगढ़ जिला 17. रतलाम जिला 18. सीहोर जिला 19. राजापुर जिला 20. शिवपुरी जिला 21. उज्जैन जिला 22. विदिशा जिला 23. माधुषा जिला
15-क० जबलपुर	जबलपुर	1. अम्बिकपुर जिला 2. बालाघाट जिला 3. बस्तर जिला 4. बिलासपुर जिला 5. छतरपुर जिला 6. छिन्दवाड़ा जिला 7. दमोढ़ जिला 8. दुर्ग जिला

1	2	3
		9. जबलपुर जिला
		10. मंडला जिला
		11. नरसिंहपुर जिला
		12. पन्ना जिला
		13. रायगढ़ जिला
		14. रायपुर जिला
		15. राजनन्दगांव जिला
		16. रीवा जिला
		17. सागर जिला
		18. सतना जिला
		19. सिवनी जिला
		20. शाहदोल जिला
		21. सीधी जिला
		22. टीकमगढ़ जिला

यह अधिसूचना 28-8-1980 से प्रभावी होगी।

[सं 3638/फा० सं 187/33/79-आईटीएन]

बी० एक० सिंह, सचिव

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 27th August, 1980

(INCOME-TAX)

S.O. 2946.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of all previous notifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Commissioners of Income-tax specified in column 1 of the Schedule hereto annexed with headquarters specified in column 2 thereof shall perform their functions in respect of such areas or of such persons or classes of persons or of such incomes or classes of income or of such cases or classes of cases as are comprised in the Income-tax Circle, Wards or Districts referred to in the said column 3 :

Provided that a Commissioner of Income-tax shall also perform his functions in respect of such persons or of such cases as have been or may be assigned by the Central Board of Direct Taxes to any Income-tax authority subordinate to him :

Provided further that a Commissioner shall not perform his functions in respect of such persons or such cases as have been or may be assigned to any Income-tax authority outside his jurisdiction.

SCHEDULE

Commissioner of Income-tax	Headquarters	Jurisdiction
1	2	3
15. Bhopal	Bhopal	1. District of Bhopal 2. District of Betul 3. District of Bhind 4. District of Datia 5. District of Dewas 6. District of Dhar 7. District of Gwalior 8. District of Guna 9. District of Hoshangabad 10. District of Indore

1	2	3
		11. District of Khandwa 12. District of Khargone 13. District of Mandsaur 14. District of Morena 15. District of Raisen 16. District of Rajgarh 17. District of Ratlam 18. District of Sehore 19. District of Shajapur 20. District of Shivpuri 21. District of Ujjain 22. District of Vidisha 23. District of Zabua.
15A. Jabalpur.	Jabalpur.	1. District of Ambilkapur 2. District of Balughat 3. District of Bastar 4. District of Bilaspur 5. District of Chhatarpur 6. District of Chhindwara 7. District of Damoh 8. District of Durg 9. District of Jabalpur 10. District of Mandla 11. District of Narsinghpur 12. District of Panna 13. District of Raigarh 14. District of Raipur 15. District of Rajnandgaon 16. District of Rewa 17. District of Sagar 18. District of Satna 19. District of Seoni 20. District of Shahdol 21. District of Sidhi 22. District of Tikamgarh

This notification shall have effect from 28-8-1980.

[No. 3638/F.No.187/33/79-ITAI]
B.M. SINGH, Under Secy.

आयकर आयुक्त का कार्यालय, कोचीन

कोचीन, 14 अक्टूबर, 1980

का०सा० 2947.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 287 की उपधारा (1) और भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) के आदेश एक० सं० 83/108/69-एटी० (बी), दिनांक 26-12-1970 के अनुसरण में, मैं एतद्वारा ऐसे करदाताओं का नाम प्रकाशन करता हूँ जिनके वित्तीय वर्ष 1979-80 में एक लाख रुपये से अधिक प्रमाण कर बढ़े जाते में लिखा गया है, उनका नाम निम्नलिखित अनुसूची-1 में दिया गया है :—

अनुसूची-1

आयकर आयुक्त, केरल प्रभार I और II के करदाताओं का नाम जिनसे वित्तीय वर्ष 1979-80 में एक लाख रुपये से अधिक आय बढ़े जाते में लिखा गया है।

क्रम सं०	करदाताओं का नाम व पता	स्थिति निर्धारण वर्ष	बढ़े जाते में डाले हुए रकम	अपसेशन का कारण संक्षेप में	
1	2	3	4	5	6
केरल-I					
1.	मे० कोचिन मेरेस प्राइड गलवानिसेस (पी)	कंपनी से 1966-67 तक	1962-63 से 2,47,070	र० निष्क्रिय कंपनी है और इन के वित्त वर्ष के वार्ड करने के	

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
लिमिटेड, एराकुलम।					लिये इनके पास कोई चल या अचल संपत्ति नहीं है।	3	श्री ए० पी० एम० सोहृम्मद, जकीना मंजिल, कारपंबा, कालिकट	व्यक्ति से 1971-72 तक	1965-66 से 1971-72 तक	रु० 1,81,974	करदाता के विरुद्ध कारवाई करने, इनके पास कोई चल या अचल संपत्ति नहीं है।
केरल-II				रु० 106,782		टिप्पणी :—“एक व्यक्ति से प्राप्य कर बड़े खाते में डाला गया है, इसका अर्थ सिर्फ यह है कि आयकर विभाग की राय में इस प्रकाशन की तारीख तक करदाता के विहित भास्तियों से बसूल नहीं किया जा सकता है। प्रकाशन का यह आशय नहीं है कि कानून के अनुसार यह रकम अशोध्य है या करदाता को उक्त रकम चुकाने के उत्तरदायित्व से उनमुक्त किया गया है।”					
2. श्री बी० जे मास्सू, फातिमा कालेज, तलपाया, कण्णूर	व्यक्ति	1948-49 1952-53 और 1953-54		रु० 1,06,782	करदाता के विरुद्ध कारवाई करने, इनके, पास कोई चल या अचल संपत्ति नहीं है।	[सी० स० 42/80-81/प्रार०] एम० एस० उण्णिनायर, आयकर आयुक्त, कोचिन।					

Office of the Commissioner of Income-Tax Cochin

Cochin, the 14th October, 1980

S.O. 2947.—In pursuance of Sub-section (1) of Section 287 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in pursuance of Order F.No.83/108/69-IT(B) dated 26th December, 1970 of the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), Government of India, I, hereby publish the names of assesseees in whose cases tax dues exceeding Rs. 1 lakh have been written off during the financial year 1979-80 as per Schedule I appended hereto :—

SCHEDULE I

Names of Assesseees in whose cases tax dues over Rs. 1 lakh have been written off during the Financial year 1979-80 in the Erst-while Charges of the Commissioners of Income-tax, Kerala I and Kerala II.

Sl. No.	Name and address of the assessee	Status	Asst. year	Amount written	Brief reasons for written off
KERALA I					
1.	M/s. Cochin Metals and Galvanisers (P) Limited, Ernakulam.	Company	1962-63 to 1966-67	Rs.2,47,070	The Company is defunct and does not own any movable or immovable properties which could be proceeded against.
KERALA II					
2.	Sri. V.J. Mathew, Fathima College, Talapaya, Cannanore.	Individual	1948-49, 1952-53 and 1953-54	Rs.1,06,782	The assessee does not own any movable or immovable property which could be proceeded against.
3.	Sri. E.P.M. Mohammed, Zakeena Manzil, Karaparamba, Calicut.	Individual	1965-66 to 1971-72	Rs.1,81,974	The assessee does not own any movable or immovable properties which could be proceeded against.

Note : The statement that the tax dues from a person has been written off only mean that in the opinion of the Income-tax Department it cannot on the date of publication be realised from the known assets of the assessee. The publication does not imply that the amount is irrecoverable in law or that the assessee is discharged from his liability to pay the amount in question.

[C. No. 42/80-81/R]

M.S. UNNINAYAR, Commissioner of Income-tax, Cochin.

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 1980

(रबर नियंत्रण)

का० प्रा० 2948—रबर नियम, 1955 के नियम 4 के उप-नियम (1) के साथ पठित रबर अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को श्रमिक हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए रबर बोर्ड के सदस्य मनोनीत करती है और निदेश देती है कि वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं० का० प्रा० 13(ई) दिनांक 11 जनवरी, 1978 में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में क्रमांक 16 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नोक्त क्रमांक तथा प्रविष्टियाँ जोड़ दी जाएँगी, अर्थात्:—

- 17 श्री पी० डी० जार्ज,
महासचिव,
केरल प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन,
मुन्दाकायम, केरल।
- 18 श्री आर० रविन्द्रन,
सचिव,
केरल स्टेट ट्रेड यूनियन कांसिल,
मुगातन मैमोरियल बिल्डिंग,
वाझुत्तक्कड, त्रिवेन्द्रम, केरल।
- 19 श्री के० पद्मनाभन,
मीटु हाऊस, मालदोर रोड,
त्रिवेन्द्रम-695001 केरल।
- 20 श्री एन० श्रीकान्त नायर, जलकी सदन,
अम्बालापुड़ा पो० प्रा०,
अल्लुप्पी, डिस्ट्रिक्ट केरल।

श्रमिक हित का प्रति-
निधित्व करने के लिये
केन्द्रीय सरकार द्वारा
मनोनीत।

2 केन्द्रीय सरकार ब्रानचिण्ट करती है कि क्रमांक 17 से 20 तक के सामने दिये गये सदस्य सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 10 जनवरी, 1981 को समाप्त होने वाली तारीख तक, जिनमें यह तारीख भी शामिल है पर पर धन रहेगे।

[का० सं० 15(2)/77-प्लांट (बॉ.)]

एम० महादेव अय्यर, उप निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 8th October, 1980

(RUBBER CONTROL)

S.O. 2948.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (3) of section 4 of the Rubber Act, 1947 (24 of 1947) read with sub-rule (1) of rule 4 of the Rubber Rules, 1955, the Central Government hereby nominates the following persons to be the members of the Rubber Board to represent labour interests and directs that the following amendment shall be made to the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce N.S.O. 13 (E) dated the 11th January, 1978, namely:—

In the said notification, after Serial No. 16 and the entry relating thereto, the following Serial Nos. and entries shall be inserted namely:—

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 17. Shri P.D. George,
General Secretary,
Kerala Plantation Workers
Federation,
Mundakayam,
Kerala. 18. Shri R. Ravindran,
Secretary,
Kerala State Trade Union Council,
Sugathan Memorial Building,
Vazhuthakkad,
Trivandrum,
Kerala. 19. Shri K. Padmanabhan,
CITU House,
Mallod Road,
Trivandrum—695001
Kerala. 20. Shri N. Sreekantan Nair,
Janaki Sadanam,
Ambalapuzha P.O.,
Alleppey District.
Kerala. | Nominated by the
Central Govern-
ment to represent
the interest of
labour. |
|---|--|

2. The Central Government specifies that the members at Serial Nos. 17 to 20 shall hold office for a period commencing from the date of publication of this notification in the Official Gazette and ending with and inclusive of the 10th January, 1981.

[File No. 15(2)/77-Plant(B)]

S. MAHADEVA IYER, Deputy Director

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1980

का० प्रा० 2949.—केन्द्रीय सरकार, काजू की गिरियों के निर्वाह (स्वानिर्वाह नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1966 के नियम 8 के अनु-सरण में और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 1050 तारीख 1 अप्रैल, 1966, सं० का० प्रा० 1694 तारीख 6 जून, 1966 सं० का० प्रा० 2705 तारीख 5 सितम्बर, 1966 और सं० का० प्रा० 2781 तारीख, 14 अगस्त, 1967 को अधिकांश करते हुए, इस अधिसूचना के साथ उपावृद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित व्यक्तियों को निर्वाह निरीक्षण अधिकरण के विनिश्चयों के विरुद्ध उक्त नियमों के अन्तर्गत अपील सुनने के प्रयोजन के लिए विशेषज्ञों के पैनल के रूप में नियुक्त करती है:—

परन्तु निर्वाह निरीक्षण अधिकरण द्वारा किए गए विनिश्चय के विरुद्ध उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में उपर्युक्त स्थानों पर जो स्तम्भ (2) में दृष्टि किए गए हैं, उस स्थान के लिए गठित विशेषज्ञों के पैनल द्वारा अपील सुनी जाएगी।

परन्तु यह और कि यदि उक्त पैनल का कोई सदस्य किसी अपील के विषय वस्तु में व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध है तो वह उस अपील से संबंधित कार्यवाहियों में भाग नहीं लेगा।

सारणी

अपील का सुनवाई का स्थान	विशेषज्ञों का पैनल गठित करने वाले व्यक्ति जिनसे अपील हो सकती है
-------------------------	---

1

2

कुशीघार (तमिलनाडु राज्य के कन्या-कुमारी, तिरुनेलैली तथा रामनव जिलों को सम्मिलित करते हुए)

1 श्री पी० गोपीनाथ पिल्लै
श्री सी० लक्ष्मी के श्या
कापीरेशन, किल्लान।

1	2	3	1	2	3
		2. श्री के कारमाकरण, मै० करुना कैशयू का० क्विलान ।			उप-निदेशक, नि० नि० प्र०-कोचीन, क्विलान । गैर सदस्य, संयोजक
		3. श्री पी० गोपीनाथन नायर, यूनिटर कैशयू का० क्विलान ।			
		4. श्री पी० भाराधन् पिल्लै, मै० ऐशियाटिक एक्स- पोर्ट इन्टरप्राइज, क्विलान,	कोचीन (केरल राज्य के एनक्विलम तथा त्रिचुर जिला को सम्मिलित करते हुए)	1. श्री के० पी० जॉन, मै० डिलीसियस कैशयू का० हरजलाकुडा	
		5. श्री के० रविश्रीनाथन नायर, मै० विजय लक्ष्मी कैशयू का०, क्विलान ।		2. श्री के० गोपीनाथान् नायर, मै० गोपीनाथननायर एण्ड का०, क्विलान ।	
		6. जिला कृषि अधिकारी, जिला कन्याकुमारी, तमिलनाडु । (पदेन)		3. श्री थामस पन्डो, मै० पैरस लेजली इडिया लि०, कोचीन- 18	
		7. उप-निदेशक भारतीय मानक संस्था, त्रिवेन्द्रम (पदेन) उप-निदेशक नि० नि० प्र० कोचीन क्विलान । गैर सदस्य		4. श्री पी० सी० प्रबुहम, मै० स्टेटन्डर्स कैशयू इन्डस्ट्रीज, कोचीन-18	
				5. श्री जी० यशोधरन, मै० जालिमिया इन्टर- नेशनल, कुन्वरा ।	
				6. उप ज्येष्ठ विपणन अधिकारी, विपणन और निरीक्षण निवे- शालय, (भारत सर- कार) प०/द्वीप, कोचीन-3 (पदेन)	
				7. जिल्ला कृषि अधि- कारी, एनक्विलम (पदेश) संयुक्त निदेशक, नि० नि० प्र०-कोचीन, कोचीन-11 गैर सदस्य, संयोजक	
क्विलान (केरल राज्य के क्विलान, त्रिवेन्द्रम, मलप्पी घोर कोट्टयम जिलों को सम्मिलित करते हुए)		1. श्री ए० सुन्दरास्वरन, काजू निर्यात कर्ता क्विलान			
		2. श्री सुजीर गणेशना- यक, मै० सुजीर गणेश नायक एण्ड का, क्विलान ।			
		3. श्री के० भाराधन, प्रबंध निदेशक, केरल राज्य काजू विकास निगम, क्वि- लान ।			
		4. श्री के० जनार्थन पिल्लै, मै० राजमोहन कैशयू खाद्य लि० क्विलान ।			
		5. श्री पी० गंगाधरन पिल्लै, मै० केरल गिरी खाद्य का०, क्विलान ।			
		6. जिला कृषि अधि- कारी, क्विलान । (पदेन)			
		7. डा० ऐ०जी० मैथ्यू, प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला श्रीलोकेश्वर इस्टेट, पापनमकोडे, त्रिवेन्द्रम । (पदेन)	कालीकट, गोवा तथा मंगलूर (राज्य, संघ क्षेत्र के राज्य के कालीकट, पलघाट और कैनूर जिलों गोवा, दमण और द्विप संघ राज्य क्षेत्र तथा मैसूर राज्य को सम्मिलित करते हुए)	1. श्री मिजार सवामन्दन पी० मै० मिजार गोविन्दा प्रभपा पी० एण्ड सन्स, मंगलूर ।	
				2. श्री पी० लक्ष्मन पिल्लै, मै० लक्ष्मन एण्ड का०, क्विलान -691004	
				3. श्री आर० ए० डी० मैकालिक, मै० पैरस लेजली इडिया लि०, मंगलूर ।	
				4. श्री के० मुबरेया प्रभपा कामथ,	

मै० के मुखिया प्रमथ
कामथ,
एण्ड मन्त,
कासर गोडे ।

5. श्री सुरेश नारायण
प्रभु जैन्टे,
मुख्य कार्यपालक
मै० नारायण गणेश-
प्रभु जैन्टे,
गोवा ।

6. सहायक विपणन
अधिकारी, विपणन और
निरीक्षण विदेशालय,
(भारत सरकार)
भंसारी रोड, बुंदवर,
मैंगलूर-1

(पदेन)

7. जिला कृषि अधि-
कारी,
जिला-दक्षिण कैनरा,
मैंगलूर-1
(मैंगलूर राज्य)
उप-निदेशक,
नि०नि० प्र० -कोचीन
मैंगलूर

(पदेन)

गैर
सदस्य
संयोजक

मै० भारत

(मद्रास राज्य तथा अन्य क्षेत्रों की सम्मि-
लित करते हुए जो अन्य पैकलों द्वारा
सम्मिलित नहीं किए गए हैं)

1. श्री विनयबास लीला
राम,
मै० लीला राम सेवा राम
मद्रास ।

2. श्री टी० के० शाहल
हैसीन मुजालियर,
मै० बैस्टनट कार्पो-
रेशन,
मद्रास ।

3. श्री डी० भास्करा-
मण्यम,
अध्यक्ष,
काजू निर्यात संवर्धन
परिषद,
कोचीन-16---

4. श्री धरम पिल्लै :
मै० विजयलक्ष्मी कैशू
को०,
मिचलान,

5. ज्येष्ठ विपणन अधि-
कारी,
विपणन और निदे-
शालय,
(भारत सरकार)

35, हैडहोरोड,
मद्रास-6 (पदेन)
उप-मुख्य कार्यपालक,
नि०नि० प्र०-मद्रास,
मद्रास

गैर सदस्य
संयोजक

2 पैसल की गणपूर्ति तीन की होगी ।

[सं० 6(1)/77-नि०नि० तथा नि० उ०]

सी०बी० कुकरेती, संयुक्त निदेशक

(Department of Commerce)

New Delhi, the 1st November, 1980

S.O.2949—In pursuance of rule 8 of the Export of Cashew Kernels (Quality Control and Inspection) Rules, 1966 and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 1050, dated the 1st April 1966, No. S.O. 1694 dated the 6th June 1966, No. S.O. 2705, dated the 5th September, 1966 and No. S.O. 2781, dated the 14th August 1967, the Central Government hereby appoint the persons mentioned in the column (2) of the Table annexed to this notification, as the panel of experts for the purpose of hearing appeals under the said rules against the decision of the Export Inspection Agency.

Provided that an appeal against a decision made by the Export Inspection Agency at places indicated in column (1) of the said Table shall be heard by the Panel of Experts constituted for that place as shown in column (2) thereof:

Provided further that when a member of any of the said panel is personally interested in the subject matter of any appeal he shall not take part in the proceedings relating to that appeal.

TABLE

Place of hearing of appeal	Persons constituting the Panel of Experts to which appeal list
KUZHITHURAI (cover- ing the districts of Kanya- kumari, Tirunelveli and Ramanad of Tamilnadu).	1. Shri P. Gopinatha Pillai, M/s. Laxmi Cashew Corpn., QUILON. 2. Shri K. Karunakaran, M/s. Karuna Cashew Co., QUILON. 3. Shri P. Gopinathan Nair, The Jupiter Cashew Co., QUILON. 4. Shri P. Bharathan Pillai, M/s. Asiatic Export Enter- prises, QUILON. 5. Shri K. Ravindranathan Nair, M/s. Vijayalaxmi Cashew Co., QUILON.

1	2
	<p>6. The District Agricultural Officer, Kanyakumari District, Tamilnadu. (Ex-officio)</p> <p>7. Dy. Director ISI, TRIVANDRUM. (Ex-officio). Dy. Director, EIA-Cochin, QUILON. Non-member, Convener.</p>
<p>QUILON, (covering the districts of Quilon, Trivandrum & Alleppey, Kottayam of Kerala State).</p>	<p>1. Shri N. Sundaraswami, Cashew Exporter, QUILON.</p> <p>2. Shri Sujit Ganesh Nayak, M/s. Sujit Ganesh Nayak & Co., QUILON.</p> <p>3. Shri K. Bhuvanathan, Managing Director, Kerala State Cashew Dev. Corp., QUILON.</p> <p>4. Shri K. Janardhanan Pillai, M/s. Rajmohan Cashews Ltd., QUILON.</p> <p>5. Shri P. Gangadharan Pillai, M/s. Kerala Nut Food Co., QUILON.</p> <p>6. Dist. Agricultural Officer, QUILON. (Ex-officio).</p> <p>7. Dr. A.G. Mathew, Regional Research Laboratory, Industrial Estate, Pappanamkode, TRIVANDRUM. (Ex-officio). Dy. Director, EIA Cochin, QUILON. Non-member, Convener.</p>
<p>COCHIN, (covering the districts of Ernakulam and Trichur of Kerala State).</p>	<p>1. Shri K.P. John, M/s. Delicious Cashew Co., Irinjalakuda.</p> <p>2. Shri K. Gopinathan Nair, M/s. K. Gopinathan Nair & Co., QUILON.</p> <p>3. Shri Thomas Chandy, M/s. Pairce Leslie India Ltd., COCHIN.</p> <p>4. Shri P.C. Abraham, M/s. Standard Cashew Indus., COCHIN-18.</p>

1	2
	<p>5. Shri G. Yesodharan, M/s. Dalmia International, KUNDARA.</p> <p>6. Dy. Senior Marketing Officer, Directorate of Marketing and Inspection, (Govt. of India), W/Island, COCHIN-3. (Ex-officio).</p> <p>7. District Agricultural Officer, ERNAKULAM. (Ex-officio). The Joint Director, EIA—Cochin, COCHIN-11. Non-member, Convener.</p>
<p>CALICUT, GOA & MANGALORE (covering the districts of Calicut, Palghat and Cannanore of Kerala State, Union Territory of Goa, Daman & Diu and the State of Mysore).</p>	<p>1. Shri Mizar Sadanada Pai, M/s. Mizar Gouinda Annappa Pai & Sons, MANGALORE.</p> <p>2. Shri P. Lekshamanan Pillai, M/s. Lkshman & Co., QUILON-691 004.</p> <p>3. Shri R.A.D. McAuliffe, M/s. Pairce Leslie India Ltd., MANAGALORE.</p> <p>4. Shri K. Subraya Anantha Kamath, M/s. K. Subraya Ananth Kamath & Sons, KASARGODE.</p> <p>5. Shri Suresh Narayan Prabhu Zantya Chief Executive, M/s. Narayan Ganesh Prabhu Zantye, GOA.</p> <p>6. Asst. Marketing Officer, Directorate of Marketing & Inspection, (Govt. of India), Aswari Road, Bunder, MANAGALORE-1. (Ex-officio).</p> <p>7. District Agricultural Officer, South Kanara District. MANAGALORE. (MYSORE STATE) (Ex-officio). Dy. Director, EIA-Cochin. MANGALORE. Non-member, Convener.</p>

1

2

REST OF INDIA (covering the state of Madras and any other area not covered by the other panels).

1. Shri Vishindes Leelaram, M/s. Leelaram Shewaram (P) Ltd., MADRAS.
2. Shri T.K. Shahai Haseen Musaliar, M/s. Bestnut Corporation, MADRAS.
3. Shri D. Balasubramaniam, Chairman, Cashew Export Promotion Council, COCHIN-16.
4. Shri Sreedharan Pillai, M/s. Vijayalaxmi Cashew Co., QUILON.
5. Senior Marketing Officer, Directorate of Marketing & Inspection, (Govt. of India), 35, Haddows Road, MADRAS-6. (Ex-officio). The Deputy Chief Executive, EIA-Madras, MADRAS. Non-member, ~~Convenor~~.

2. The quorum of the Panel shall be three.

[No. 6(1)/77—E I & E P]
C.B. KUKRETI, Joint Director

(संयुक्त मुख्य निर्यातक आयात तथा निर्यात का कार्यालय)

आवेश

मद्रास, 14 अक्टूबर, 1980

का० प्रा० 2950 सर्वोच्च एक्सप्रेस म्यूजियम लिमिटेड, मोन्टरोड, मद्रास-2 को रुपये 34,000 तक, वेब आफसेट प्लेट्स के डिबेलिंग के लिए आवश्यक केमिक्स का आयात करने के लिए लाइसेंस संख्या पी-डी-1438072-सी-एक्स एक्स-71-एम-78 दिनांक 21-4-1979 जारी किया गया था। उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति जा जाने के कारण, उसकी अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए लाइसेंसधारी ने आवेदन किया है। उनसे यह भी कहा गया है कि उपर्युक्त लाइसेंस की मूल्य में रुपये 23,380.13 को छोड़कर रुपये 10619.87 का उपयोग कर लिया गया है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि लाइसेंस संख्या पी-डी-1438072-सी-एक्स एक्स-71-एम-78 दिनांक 21-4-79 की मुद्रा विनियम नियंत्रण की मूल प्रति खो दी गयी है और आवेदक वेता है कि आवेदक को उपर्युक्त लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण की अनुलिपि प्रति जारी किया जाय। लाइसेंस की मूल प्रति एतद्वारा रद्द किया जाता है।

मुद्रा विनियम नियंत्रण की अनुलिपि प्रति संख्या पी-डी-1438072 दिनांक 21-4-79 अलग जारी किया जाता है।

[संख्या . ऐटीसी-डीजीटीडी-328-एम 79-एयु-1]

के० रामन

उप मुख्य निर्यातक, आयात तथा निर्यात,
उत्ते संयुक्त मुख्य निर्यातक, आयात तथा निर्यात।

(Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports)
ORDER

Madras, the 15th October, 1980

S.O.2950.—M/s. Express Newspapers Limited, Express Estates, Mount Road, Madras 2, were granted licence No. P/D/1438072/C/XX/71/M/78 dated 21-4-1979, for import of necessary chemicals for developing of Web Offset Plates for Rs. 34,000. They have requested for the issue of duplicate copy of the above licence (Exchange Control Copy) which has been lost by them. Further it has been stated by them that the above licence has been lost by them and having been utilised a sum of Rs. 10,619.87 only leaving a balance of Rs. 23,380.13P.

In support of their contention the applicant have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the original copy of the licence No. P/D/1438072/C/XX/71/M/78 dated 21-4-79 (Exchange Control copy) has been lost and directs that a duplicate copy of the said licence (Exchange Control copy) should be issued to them. The original copy of the licence is hereby cancelled.

A duplicate licence (Exchange Control copy) No. P/D/1438072 dated 21-4-79 has been issued separately.

[No. ITC/DGTD/329/AM-79/AU-1]

K. RAMAN, Dy. Chief Controller of Imports and Exports
For Joint Chief Controller of Imports and Exports

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 1980

का० प्रा० 2951.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का प्रश्न) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० प्रा० सं० 1313 तारीख 11-4-80 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सख्त अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिर्णय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निश्चित होगा।

अनुसूची					Village	Survey No.	Hec- tare	Are centiare	Cen- tiare
बी० आर० सी० से जी० जी० एस० विराज तक पाइप लाइन बिछाने ।						141	0	10	50
राज्य : गुजरात					जिला : मेहसाणा	138/1	0	25	65
					तहसील : कडी	154	0	07	80
गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	एअरार्ड	सेन्टोयर		136	0	03	50
नानी कडी	114/ए	0	07	50					
	117/ए	0	10	80					
	128/ए	0	16	80					
	133	0	13	29					
	134	0	06	75					
	142/3	0	08	25					
	142/1	0	08	25					
	141	0	10	50					
	138/1	0	25	65					
	154	0	07	80					
	136	0	03	50					

[सं० 12016/13/80 प्रो० I]

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 7th October, 1980

S.O. 2951.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 1313 dated 11-4-80 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from VRC to GGS Viraj

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hec- tare	Are centiare	Cen- tiare
Nani Kadi	114/A	0	07	50
	117/A	0	10	80
	128/A	0	16	80
	133	0	13	20
	134	0	06	75
	142/3	0	08	25
	142/1	0	08	25

[No. 12016/13/80-Part-I]

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 1980

का० आ० 2952—यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० एम० ६० सी० से सोभासन जी० जी० एस० ए० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एम्प्लायड अनुसूची वर्गित भूमि में उपयोग का अधिकार प्रजित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार प्रजित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है ।

वर्तते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप संभव अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस, आयोग, निर्माण और वेखमाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बबोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: वह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

कूप नं० एम० ६० सी० से सोभासन जी० जी० एस० II तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य	गुजरात	जिला : मेहसाणा	ताल्लुका : मेहसाणा	
गाँव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	एअरार्ड	सेन्टोयर
जगुदण	464	0	09	84
	465	0	12	96
	466	0	06	48
	470	0	07	80
	472	0	11	67
	473	0	00	60

[सं० 12016/54/80-प्रो० I]

New Delhi, the 8th October, 1980

S.O. 2952.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from S.E.C. to Sobhasan GGs II in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra-390009.

And every reason making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

R.O.U. for Well No. S.E.C. to Sobhasan GGS II

State : Gujarat	Distt. & Taluka : Mehsana			
Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Centiare
Jagudan	464	0	09	84
	465	0	12	96
	466	0	06	48
	470	0	07	80
	472	0	11	67
	473	0	00	60

[No. 12016/54/80-Prod.-II]

कां० 2953.—यत् केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० एम० ई० जे० 54 से 49 (एस० सी० जी०) तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत् यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अथ पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

वर्षों कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सख्त अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, मिनिंग और खेजभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी बिधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

कूप नं० 54 (एस० ई० जे०) से 49 (एस० सी० जी०)
राज्य : गुजरात जिला : मेहसाणा तालुका-मेहसाणा

गाँव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	एअरर्ई	सेन्टीयर
जगुदण	859	0	79	80
	711	0	24	96
	710	0	07	00
कार्ट ट्रैक्ट	0	00	50	
708	0	01	00	
705	0	30	60	
703	0	12	60	
702	0	04	80	
कार्ट ट्रैक्ट	0	00	50	
875	0	06	95	
कार्ट ट्रैक्ट	0	00	50	

1	2	3	4	5
	874	0	24	96
	कार्ट ट्रैक्ट	0	00	50
	674	0	27	99
	रोड	0	01	00
	663	0	03	60

[सं० 12016/54/80-प्रो०-II]

S.O. 2953.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from 54(S.E.J.) to 49 (SCG) in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra-390009.

And every reason making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

R.O.U. for Well No. 54 (SEJ) to No. 49 (SCG)

State : Gujarat	District : Mehsana Taluka : Mehsana			
Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Centiare
Jagudan	859	0	79	80
	711	0	24	96
	710	0	07	00
Cart tract	0	00	50	
708	0	01	00	
705	0	30	60	
703	0	12	60	
702	0	04	80	
Cart tract	0	00	50	
875	0	06	95	
Cart tract	0	00	50	
874	0	24	96	
Cart tract	0	00	50	
674	0	27	99	
Road	0	01	00	
663	0	03	60	

[No. 12016/54/80-Prod. II]

कां० 2954.—यत् पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना कां० प्रा० सं० 1242 तारीख 10-4-80 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिश्चित भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत् सख्त प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जे०एल०जेड० से झलोरा जी०जी०एस० तक पाइपलाइन बिछाने के लिए
राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कडी

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर ए०प्रार०	सेंटीयर	है०
लखमनपुरा	242	0	34	45
	241	0	18	25
	243	0	03	90
मेरडा	250	0	07	73
	238	0	11	10
	253/2	0	06	30
	253/1	0	07	12
	230	0	10	20
	227/2	0	05	70
	227/1	0	04	95
	काटे ट्रैक	0	04	35
	226/2	0	10	50
	226/1	0	12	00
	217	0	13	95
	216	0	01	50
	59	0	01	50
	214	0	13	20
	213	0	02	55
	212	0	09	45
	209	0	01	00
	68	0	06	60
	70/2	0	05	40
	81	0	05	40
	72	0	08	55
	73	0	07	80
	195	0	09	00
	194	0	05	65

[सं० 12016/4/80-प्रोड०]

S.O. 2954. Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 1242 dated 10-4-80 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from JLZ to Jhalora GGS

State : Gujarat	District : Mehsana	Taluka : Kadi		
Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cent-tiare
Laxmanpura	242	0	34	45
	241	0	18	25
	243	0	03	90
Merda	250	0	07	73
	238	0	11	10
	253/2	0	06	30
	253/1	0	07	12
	230	0	10	20
	227/2	0	05	70
	227/1	0	04	35
	Cart track	0	01	95
	226/2	0	10	50
	226/1	0	12	00
	217	0	13	95
	216	0	01	50
	59	0	01	50
	214	0	13	20
	213	0	02	55
	212	0	09	45
	209	0	01	00
	68	0	06	60
	70/2	0	05	40
	71	0	05	40
72	0	08	55	
73	0	07	80	
195	0	09	00	
194	0	05	65	

[No. 12016/4/80-Prod.]

का० आ० 2955.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में रूप नं० के-126 से जी०जी०एस० VI तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

वर्णित कि उक्त भूमि में हितवश कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग,

मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चित यह भी कहेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

के-126 से जी०जी०एस० VI तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात	जिला : मेहसाना	तालुका : कडी			
गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	ए०आर०ई०	सेटीयर	
झुलासन	642	0	01	50	
	641	0	19	05	
	654	0	15	60	
	655	0	17	55	
	657/2	0	04	50	

[सं० 12016/52/80-प्रोड०]

S.O. 2955—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from K-126 to GOS VI in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land of the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline From K-126 to GGS VI

State : Gujarat	District : Mehsana	Taluka : Kadi			
Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Centi-are	
Zulasan	642	0	01	50	
	641	0	19	05	
	654	0	15	60	
	655	0	17	55	
	657/2	0	04	50	

[No. 12016/52/80-Prod.]

का० जा० 2956.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 1243 तारीख 10-4-80 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिश्चित भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और चाहे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिश्चित भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिश्चित उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और चाहे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से, सभी बाधाओं से मुक्त रूप से घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को विहित होगा।

अनुसूची

एस०जी०आर० से जी०जी०एम० एम सी०टी०एफ० सोसायन तक पाइप-लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात	जिला और तालुका : मेहसाना				
गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टेयर	ए०आर०ई०	सेटीयर	
धुतासन	407	00	11	28	
	428	00	03	24	
	401	00	00	50	
	400	00	14	40	
	429	00	30	00	
	11	00	08	88	
	10	00	01	92	
	6	00	01	20	
	9	00	07	20	
	65	00	04	32	
	64	00	04	68	
	63	00	04	80	
	62	00	03	60	
	92	00	11	00	
	93/1	00	02	88	
	93/2	00	09	96	
	94	00	19	20	
	440	00	14	40	
	रोड	00	00	75	
	441	00	05	28	
	132	00	05	40	
	133	00	06	84	
	126	00	04	80	

[सं० 12016/9/80-II]

S.O. 2956—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 1243 dated 10-4-80 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

ROU for SDR to GGS GUM CFT SOB

State : Gujarat	District : Mehsana	Taluka : Mehsana		
Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Punasan	407	00	11	28
	428	00	03	24
	401	00	00	50
	400	00	14	40
	429	00	30	00
	11	00	08	88
	10	00	01	92
	6	00	01	20
	9	00	07	20
	65	00	04	32
	64	00	04	68
	63	00	04	80
	62	00	03	60
	92	00	11	00
	93/1	00	02	88
	93/2	00	09	96
	94	00	19	20
	440	00	14	40
	ROAD	00	00	75
	441	00	05	28
	132	00	05	40
	133	00	06	84
	126	00	04	80

[No. 12016/9/80-Prod-III]

का० आ० 2957.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 1169 तारीख 3-4-80 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना प्राव्य घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट देनी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेदन देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 827 GI/80—3

का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

मानन्द-- 42 से मानन्द 15 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।				
राज्य : गुजरात	जिला : मेहसाणा	तालुका : कलोल		
गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	ए०	सैंटीयर
जेठलज	9/1	0	08	22
	9/2	0	03	15
	544	0	01	86
	373/1	0	11	16
	373/2	0	09	77

[सं० 12016/1/80-प्र०]

S.O. 2957.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 1169 dated 3-4-80 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by such, section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Sanand—42 to Sanan 15

State : Gujarat	District : Mehsana	Taluka : Kalol		
Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Jethalaj	9/1	0	08	22
	9/2	0	03	15
	544	0	01	86
	373/1	0	11	16
	373/P	0	09	77

[No. 12016/1/80-Prod.]

का० आ० 2958.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० के-83 से के-5 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी स्थितियों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3

की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

यहाँ कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप मजूम अधिकारी, सेल तथा प्राकृतिक गैस तथा आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकारपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुतबाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

कूप नं० के-83 से के-5 तक पाईप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात	जिला : तामुका	गांधी नगर			
गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर ए०आर०ई० सेंटीयर			
सेरथा	21/1	0 01 00			
	80	0 07 15			
	81/6	0 08 25			
	81/5	0 08 40			
	कार्ट ट्रैक	0 01 50			
	1362	0 06 90			
	1361/2	0 06 90			
	1360/1	0 01 50			
	1357	0 04 50			

[सं० 12016/1/80-प्रो०]

S.O. 2958.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from K-83 to K-5 in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land of the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara 390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Well No. K—83 to K—5

State : Gujarat	District & Taluka : Gandhinagar			
Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Sertha	21/2	0	01	00
	80	0	07	15
	81/6	0	08	25
	81/5	0	08	40
	Cart track	0	01	50
	1362	0	06	90
	1361/2	0	06	60
	1360/1	0	01	50
	1357	0	04	50

[No. 12016/1/80 Prod.]

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 1980

का० प्रा० 2959—पेट्रोलियम और खनिज पायपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) के अन्तर्गत भारत सरकार पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना का० प्रा० सं० 1461 संख्या 12020/10/80 प्रोट्ट दिनांक 8-5-80 के संलग्न अनुसूची में भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) दिनांक 24-5-80 में प्रकाशित तहसील गुडगांव जिला गुडगांव राज्य हरियाणा के लिये :

के स्थान पर			पक्षे							
ग्राम	खसरा		क्षेत्रफल			खसरा		क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	ऐयर	वर्ग मी०			हेक्टेयर	ऐयर	वर्ग मी०
1	2		3	4	5	6		7	8	9
सैलानी ह०नं० 207	101/1/3	मिन	0	02	20	101/1/3	मिन	0	02	28
	24/13/1	"	0	08	05	24/13/1	"	0	08	10
	24/14/1	"	0	04	10	24/14/1	"	0	04	05
	38/10	"	0	10	88	37/10	"	0	10	88
	57/11/1	"	0	02	28	58/11/1	"	0	02	28
	57/11/2	"	0	10	88	58/11/2	"	0	10	88
	57/19	"	0	10	37	58/19	"	0	10	37
	57/20	"	0	02	78	58/20	"	0	02	78
दमधसा ह०नं० 174	34/16/2	"	0	00	00	33/16/2	"	0	00	00
खोरसा ह०नं० 177	39/22	"	0	10	37	30/22	"	0	10	37
भोईसी ह० नं० 168	6/6	"	0	01	01	16/6	"	0	01	01
	145/5/2	"	0	08	86	145/6/2	"	0	08	86
मेदासा ह०नं० 85	74/25	"	0	10	12	73/25	"	0	10	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
तिगरा ह०न० 51	8/16 मिन	0	08	60	4/16 मिन	0	08	60
	15/5/2 "	0	05	51	15/5/2 "	0	05	51
बन्दापुर ह०न० 93	8/11 "	0	07	84	5/11 "	0	07	84
मुलाहेडा ह०न० 65	9/1/2 "	0	01	01	16/1/2 "	0	01	01
	9/10 "	0	10	12	16/10 "	0	10	12
	9/11 "	0	10	12	16/11 "	0	10	12
	9/20 "	0	09	61	16/20 "	0	09	61
	9/21 "	0	10	12	16/21 "	0	10	12
कार्टर पुगे ह०न० 63	12/14/2 "	0	10	12	12/19/2 "	0	10	12

[क्रम संख्या 12020/10/80-प्रोड०]

ERRATUM

New Delhi, 9th October, 1980

S.O. 2959 --In the Schedule appended to the notification of the Government of India, Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Petroleum S.O.No. 1461 (No. 12020 10/80 Prod) dated. 8th May, 1980 issued under Sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in Land) Act, 1962 (50 of 1962) published at pages 1495-1503 dated 24th May 1980 of the Gazette of India Part II Section 3, Sub-section (ii) for T hsil Gurgaon Distt. Gurgaon State of Haryana.

Name of Village	For	Read							
	Khasra No.	H	A	Sq.Mtrs	Khasra No.	H	A	Sq. Mtrs.	
Selani H.No. 207	17/105 Min	0	01	01	105 Min	0	01	01	
Karanki H.No. 206	3/4 Min	0	11	13	7/4 Min	0	11	13	
	3/6 Min	0	03	29	7/6 Min	0	03	29	
	3/7 Min	0	08	86	7/7 Min	0	08	86	
	3/15 Min	0	12	14	7/15 Min	0	12	14	
	3/16 Min	0	04	81	7/16 Min	0	04	81	
	3/21 Min	0	11	89	6/21 Min	0	11	89	
	3/22 Min	0	00	25	6/22 Min	0	00	25	
	21/15 Min	0	11	51	21/15 Min	0	00	51	
Choharpur H.No. 203	8/15 Min	0	09	36	18/15 Min	0	09	36	
Abhepur H.No. 173	73/24 Min	0	08	61	73/24 Min	0	09	61	
Damdama H.No. 174	33/52 Min	0	00	76	52 Min	0	00	76	
Kherla H.No. 177	6/78 Min	0	02	78	78/Min	0	02	78	
	16/19/1 Min	0	07	84	61/19/1 Min	0	07	84	
Madawas H.No. 85	990 Min	0	00	76	90 Min	0	00	76	
Tigra H.No.51	8/9 Min	0	10	12	28/9 Min	0	10	12	
	13/5/2 Min	0	05	51	15/5/2 Min	0	05	51	
Sirhol H.No. 70	14/1 Min	0	02	82	25/14/1 Min	0	05	82	
	43/20 Min	0	06	58	42/20 Min	0	06	58	
Mulahera H.No. 65	10/21/2 Min	0	06	58	20/21/ Min	0	06	58	
Cartar pur H.No. 63	12/14/2 Min	0	10	12	12 /19/2 Min	0	10	12	

[No. 12020/10/80-Prod.]

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 1980

श्रीरयत: सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

श्रीर आगे, यत. केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियां में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का निश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार एतद्द्वारा विधान विधान के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ?

का०आ० 2960 --यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 1246 दिनांक 3-5-80 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को विद्युत के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अतः आशय घोषित कर दिया था।

और आगे उस छाया की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय इंडियन आयल कारपोरेशन लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

प्रमुखी

तहसील : छाता जिला : मथुरा राज्य : उत्तर प्रदेश

ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल		
		हेक्टर	ऐयर	वर्ग-मीटर
1	2	3	4	5
आमई खुर्द	92 मिन	0	00	81
	94 "	0	03	24
	95 "	0	03	24
	96 "	0	00	81
	98 "	0	27	52
	115 "	0	16	19
	116 "	0	25	90
	117 "	0	00	81
	127 "	0	12	95
	128 "	0	04	45
	133 "	0	20	23
	136 "	0	00	81
	137 "	0	00	40
	139 "	0	19	42
	140 "	0	17	81
	141 "	0	07	28
	142 "	0	01	21
	198 "	0	17	40
	199 "	0	44	92
	225 "	0	00	81
	226 "	0	00	81
	231 "	0	27	52
	233 "	0	20	23
	234 "	0	00	81
	235 "	0	21	04
	248 "	0	15	38
	251 "	0	16	19
	253 "	0	01	62
	254 "	0	08	50
	255 "	0	00	81
	256 "	0	05	26
	258 "	0	11	33
	259 "	0	23	47
	261 "	0	06	48
	264 "	0	00	40
	262 "	0	15	38
	886 "	0	11	33
	889 "	0	00	81
	890 "	0	10	52
	891 "	0	11	33
	892 "	0	14	57
	896 "	0	06	88
	897 "	0	33	59

1	2	3	4	5
	912 मिन	0	00	81
	1267 "	0	02	43
	1277 "	0	21	04
	1279 "	0	00	81
	1281 "	0	01	62
	1283 "	0	21	85
	1284 "	0	11	74
	1288 "	0	17	40
	1289 "	0	20	23
	1311 "	0	20	23
	1313 "	0	25	50
	1315 "	0	00	40
	1316 "	0	00	40
	1318 "	0	25	90
	1320 "	0	18	62
चौमुहा	770 "	0	10	12
	771 "	0	46	54
	774 "	0	00	40
	775 "	0	00	81
	777 "	0	16	59
	778 "	0	12	95
	828 "	0	01	62
	829 "	0	10	93
	830 "	0	31	16
	874 "	0	12	55
	875 "	0	00	81
	876 "	0	24	69
	879 "	0	01	21
	880 "	0	05	26
	881 "	0	14	57
	882 "	0	14	97
	884 "	0	01	62
	889 "	0	33	59
	890 "	0	00	40
	891 "	0	19	83
	894 "	0	02	83
	895 "	0	23	47
	964 "	0	15	78
	965 "	0	01	21
सिहाना	85 "	0	12	14
	86 "	0	11	74
	87 "	0	41	68
	88 "	0	01	62
	194 "	0	00	40
	197 "	0	41	28
	207 "	0	00	81
	209 "	0	00	81
	223 "	0	00	81
	242 "	0	08	90
	243 "	0	00	81
	244 "	0	17	00
	245 "	0	00	81
	247 "	0	25	50
	248 "	0	03	64
	322 "	0	03	24

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
सिहाना	338 मिन	0	14	16	नरी	608 मिन	0	34	40
	339 „	0	00	40		615 मिन	0	00	40
	340 „	0	11	33		616 मिन	0	00	81
	341 „	0	01	21		632 मिन	0	00	81
	342 „	0	10	52		634 मिन	0	08	09
	362 „	0	03	24		635 मिन	0	02	39
	364 „	0	01	21		638 मिन	0	01	21
	368 „	0	00	81		646 मिन	0	00	40
	369 „	0	00	40		654 मिन	0	20	23
	370 „	0	00	81		655 मिन	0	05	26
	371 „	0	05	67		656 मिन	0	00	40
	377 „	0	04	45		659 मिन	0	08	90
	378 „	0	04	86		660 मिन	0	03	24
	379 „	0	00	40		661 मिन	0	08	50
	380 „	0	12	95		662 मिन	0	17	81
	381 „	0	00	81		665 मिन	0	17	81
	382 „	0	03	64		683 मिन	0	42	49
	423 „	0	18	62	सेमरी	15 मिन	0	03	24
	424 „	0	53	42		16 मिन	0	00	81
	426 „	0	23	88		17 मिन	0	38	04
	429 „	0	31	97		25 मिन	0	00	81
कोक्रेरा	2 „	0	20	23		26 मिन	0	21	85
	4 „	0	18	21		30 मिन	0	00	81
	5 „	0	00	40		36 मिन	0	23	47
	6 „	0	00	81		37 मिन	0	12	55
	8 „	0	09	31		76 मिन	0	01	21
	9 „	0	12	95		79 मिन	0	60	70
	10 मिन	0	32	37		609 मिन	0	28	33
	58 मिन	0	33	59		610 मिन	0	25	50
	59 मिन	0	00	81		619 मिन	0	00	81
	60 मिन	0	00	40		620 मिन	0	57	06
	62 मिन	0	17	81		622 मिन	0	01	21
	106 मिन	0	00	81		628 मिन	0	04	45
	107 मिन	0	23	47		629 मिन	0	40	87
	108 मिन	0	26	71		631 मिन	0	03	24
	110 मिन	0	00	81		639 मिन	0	04	05
	115 मिन	0	14	57		640 मिन	0	21	45
नरी	73 मिन	0	47	75		641 मिन	0	17	00
	74 मिन	0	00	81		642 मिन	0	04	45
	92 मिन	0	00	81		643 मिन	0	26	30
	94 मिन	0	37	64	रतबारी	376 मिन	0	43	30
	95 मिन	0	00	40		377 मिन	0	00	40
	96 मिन	0	00	81		380 मिन	0	04	86
	97 मिन	0	07	28		381 मिन	0	01	21
	104 मिन	0	03	24		382 मिन	0	31	57
	113 मिन	0	00	40		383 मिन	0	00	81
	114 मिन	0	18	21		384 मिन	0	19	02
	115 मिन	0	00	81		385 मिन	0	14	16
	116 मिन	0	10	12		386 मिन	0	02	02
	120 मिन	0	21	45		388 मिन	0	00	81
	124 मिन	0	00	40		389 मिन	0	14	16
	603 मिन	0	53	02		397 मिन	0	10	12
	604 मिन	0	12	14		398 मिन	0	00	81
	606 मिन	0	00	81		399 मिन	0	01	62

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
सबारी	403 मिन	0	00	81	दूमीला	326 मिन	0	00	81
	411 मिन	0	31	16		336 मिन	0	06	88
	413 मिन	0	02	02		337 मिन	0	25	50
	414 मिन	0	20	64		338 मिन	0	02	83
	415 मिन	0	21	04		342 मिन	0	23	88
	416 मिन	0	00	81		343 मिन	0	10	52
	417 मिन	0	18	21		346 मिन	0	00	81
	420 मिन	0	00	81		347 मिन	0	02	83
	421 मिन	0	16	59		348 मिन	0	10	52
	422 मिन	0	01	21		349 मिन	0	25	50
	423 मिन	0	42	09		350 मिन	0	43	71
गोहारी	11 मिन	0	41	28		351 मिन	0	02	43
	13 मिन	0	06	47		358 मिन	0	02	02
	26 मिन	0	06	07		359 मिन	0	00	81
	27 मिन	0	36	42		400 मिन	0	00	81
	28 मिन	0	10	93		401 मिन	0	10	52
	29 मिन	0	04	05		403 मिन	0	00	81
	31 मिन	0	01	21		415 मिन	0	59	89
	32 मिन	0	01	21		416 मिन	0	01	21
						418 मिन	0	05	26
	40 मिन	0	05	26		419 मिन	0	11	74
	41 मिन	0	01	21		421 मिन	0	19	02
	42 मिन	0	01	21		422 मिन	0	08	90
	43 मिन	0	02	83		429 मिन	0	00	81
	44 मिन	0	13	76		430 मिन	0	01	21
	45 मिन	0	13	76		431 मिन	0	41	68
	46 मिन	0	05	26		435 मिन	0	05	67
	62 मिन	0	01	21	बरहामा	161 मिन	0	00	81
	63 मिन	0	25	90		162 मिन	0	37	64
	65 मिन	0	01	21		163 मिन	0	17	00
	66 मिन	0	01	21		174 मिन	0	26	30
	67 मिन	0	11	74		175 मिन	0	01	21
	76 मिन	0	12	14		176 मिन	0	09	31
	78 मिन	0	42	90		177 मिन	0	09	31
	80 मिन	0	10	93		178 मिन	0	01	21
	81 मिन	0	16	19		181 मिन	0	10	12
बीताना	530 मिन	0	05	67		182 मिन	0	00	81
	541 मिन	0	00	81		187 मिन	0	02	02
	542 मिन	0	42	09		188 मिन	0	19	42
	543 मिन	0	00	81		189 मिन	0	00	81
	544 मिन	0	21	85		190 मिन	0	01	21
	545 मिन	0	00	40		198 मिन	0	29	54
	549 मिन	0	07	69		551 मिन	0	32	78
	550 मिन	0	33	99		552 मिन	0	15	38
	551 मिन	0	00	81		553 मिन	0	25	09
	554 मिन	0	00	81		558 मिन	0	01	21
	583 मिन	0	00	81		572 मिन	0	02	02
	586 मिन	0	07	69		573 मिन	0	14	16
	588 मिन	0	06	07		576 मिन	0	17	40
	589 मिन	0	10	93		577 मिन	0	01	62
	590 मिन	0	00	81		578 मिन	0	01	21
	591 मिन	0	25	90		579 मिन	0	01	62
						598 मिन	0	31	04
						653 मिन	0	00	40

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
बरहाना	654 मिन	0	00	40	उमराला	89 मिन	0	26	30
	655 मिन	0	33	59		90 मिन	0	02	02
	656 मिन	0	09	31		91 मिन	0	01	21
	659 मिन	0	01	21		93 मिन	0	00	81
	661 मिन	0	36	83	कोट बल	57 मिन	0	06	88
	662 मिन	0	01	21		73 मिन	0	15	78
	665 मिन	0	02	02		74 मिन	0	08	09
नवीपुर	4 मिन	0	15	78		75 मिन	0	06	88
	5 मिन	0	33	18		76 मिन	0	17	81
	6 मिन	0	09	31		77 मिन	0	08	09
	98 मिन	0	37	23		78 मिन	0	08	50
	101 मिन	0	00	40		80 मिन	0	17	81
	102 मिन	0	15	78		82 मिन	0	00	81
	104 मिन	0	02	02		83 मिन	0	25	90
	105 मिन	0	08	50		84 मिन	0	18	21
	106 मिन	0	04	86		117 मिन	0	00	81
	110 मिन	0	03	24		119 मिन	0	34	40
	136 मिन	0	03	24		123 मिन	0	00	81
	137 मिन	0	01	21		595 मिन	0	00	81
	150 मिन	0	01	21		605 मिन	0	59	08
	155 मिन	0	14	57		608 मिन	0	23	07
	156 मिन	0	50	99		609 मिन	0	21	45
	157 मिन	0	44	11		659/14 मिन	0	07	28
	188 मिन	0	04	86		659/13 मिन	0	16	19
	191 मिन	0	21	45		667 मिन	0	02	43
	192 मिन	0	00	40		684 मिन	0	04	05
	193 मिन	0	01	21		686 मिन	0	04	86
	194 मिन	0	34	40		686 मिन	0	29	14
	195 मिन	0	30	76		689 मिन	0	38	04
	198 मिन	0	02	02	छाता	130 मिन	0	10	93
	199 मिन	0	14	57		131 मिन	0	36	83
	200 मिन	0	34	80		132 मिन	0	21	45
	205 मिन	0	00	81		145 मिन	0	15	38
	240 मिन	0	25	50		165 मिन	0	01	62
	250 मिन	0	22	26		166 मिन	0	01	21
	251 मिन	0	01	21		167 मिन	0	02	43
	252 मिन	0	17	40		168 मिन	0	09	31
	258 मिन	0	00	81		169 मिन	0	00	40
	259 मिन	0	07	69		170 मिन	0	11	74
	260 मिन	0	12	14		171 मिन	0	01	62
	199/2 मिन	0	06	48		175 मिन	0	26	71
उमराला	2 मिन	0	64	75		176 मिन	0	19	42
	13 मिन	0	02	02		177 मिन	0	07	28
	15 मिन	0	09	31		178 मिन	0	09	71
	33 मिन	0	00	81		181 मिन	0	09	31
	34 मिन	0	26	30		182 मिन	0	37	23
	34 मिन	0	34	80		1382 मिन	0	14	16
	36 मिन	0	17	00		1383 मिन	0	03	24
	37 मिन	0	00	81		1384 मिन	0	02	83
	38 मिन	0	33	59		1385 मिन	0	01	21
	39 मिन	0	50	18		1392 मिन	0	04	45
	80 मिन	0	31	97		1393 मिन	0	13	76
	85 मिन	0	21	85		1394 मिन	0	00	40
	87 मिन	0	00	81		1395 मिन	0	12	95
						1508 मिन	0	12	55

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
छाता	1509 मिन	0	01	62	कोसी कलां	148 मिन	0	29	14
	1528 मिन	0	00	40		149 मिन	0	00	81
	1529 मिन	0	02	43		150 मिन	0	13	76
	1530 मिन	0	01	21		151 मिन	0	08	90
	1532 मिन	0	00	81		152 मिन	0	08	09
	1933 मिन	0	16	19		181 मिन	0	09	31
	1536 मिन	0	57	47		222 मिन	0	39	66
	1537 मिन	0	20	64		224 मिन	0	10	52
	1538 मिन	0	00	81		471 मिन	0	01	21
	1541 मिन	0	24	28		472 मिन	0	00	81
	1542 मिन	0	02	83		473 मिन	0	10	52
	1543 मिन	0	02	02		478 मिन	0	06	48
	1557 मिन	0	01	62		480 मिन	0	01	21
	1559 मिन	0	25	09		486 मिन	0	01	62
	1562 मिन	0	34	40		487 मिन	0	23	88
	1565 मिन	0	02	02		611 मिन	0	15	78
	1568 मिन	0	29	14		618 मिन	0	04	86
	1570 मिन	0	12	55		619 मिन	0	00	40
	1637 मिन	0	10	12		620 मिन	0	06	07
	1658 मिन	0	48	56		621 मिन	0	02	02
	1659 मिन	0	07	28		651 मिन	0	00	40
	1661 मिन	0	00	81		652 मिन	0	01	62
	1664 मिन	0	00	40		650 मिन	0	21	45
	1665 मिन	0	05	67		654 मिन	0	03	64
	1666 मिन	0	02	43		655 मिन	0	04	45
	1667 मिन	0	02	43		663 मिन	0	04	05
	1668 मिन	0	06	88		665 मिन	0	00	81
	1672 मिन	0	15	78		676 मिन	0	00	81
	1673 मिन	0	04	05		677 मिन	0	26	71
	1674 मिन	0	06	48		678 मिन	0	14	16
	1691 मिन	0	27	92		684 मिन	0	01	21
	1692 मिन	0	00	81		702 मिन	0	12	55
कोसी कलां	14 मिन	0	04	86		703 मिन	0	12	14
	19 मिन	0	02	02		705 मिन	0	27	92
	20 मिन	0	01	21		708 मिन	0	08	50
	27 मिन	0	19	02		709 मिन	0	17	81
	30 मिन	0	02	83		711 मिन	0	02	02
	31 मिन	0	12	55		712 मिन	0	00	81
	34 मिन	0	10	52		713 मिन	0	00	81
	35 मिन	0	00	81		714 मिन	0	00	40
	36 मिन	0	00	40		1650 मिन	0	02	02
	37 मिन	0	19	42		1666 मिन	0	00	40
	39 मिन	0	04	45		1881/481 मिन	0	02	02
	40 मिन	0	00	40					
	128 मिन	0	17	81					
	130 मिन	0	02	83					
	131 मिन	0	06	88					
	133 मिन	0	17	40					
	140 मिन	0	06	07					
	142 मिन	0	01	21					
	143 मिन	0	12	14					
	144 मिन	0	05	67					
	145 मिन	0	01	21					
	147 मिन	0	04	05					

[सं० 12020/9 -प्रोड०]

S.O. 2960.—Whereas by a notification Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizer (Department of Petroleum) S.O. 1246 dated 3-5-80 under Sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances

SCHEDULE

Tehsil : Chhata		District : Mathura		State : Uttar Pradesh	
Name of Village		Khasra No.		Area	
				H.	A. Sq. M.
1	2	3	4	5	
Ajhai Khurd	92 Min	0	00	81	
	94 Min	0	03	24	
	95 Min	0	03	24	
	96 Min	0	00	81	
	98 Min	0	27	52	
	115 Min	0	16	19	
	116 Min	0	25	90	
	117 Min	0	00	81	
	127 Min	0	12	95	
	128 Min	0	04	45	
	133 Min	0	20	23	
	136 Min	0	00	81	
	137 Min	0	00	40	
	139 Min	0	19	42	
	140 Min	0	17	81	
	141 Min	0	07	28	
	142 Min	0	01	21	
	198 Min	0	17	40	
	199 Min	0	44	92	
	225 Min	0	00	81	
	226 Min	0	00	81	
	231 Min	0	27	52	
	233 Min	0	20	23	
	234 Min	0	00	81	
	235 Min	0	21	04	
	248 Min	0	15	38	
	251 Min	0	16	19	
	253 Min	0	01	62	
	254 Min	0	08	50	
	255 Min	0	00	81	
	256 Min	0	05	26	
	258 Min	0	11	33	
	259 Min	0	23	47	
	261 Min	0	06	48	
	264 Min	0	00	40	
	262 Min	0	15	38	
	886 Min	0	11	33	
	889 Min	0	00	81	
	890 Min	0	10	52	
	891 Min	0	11	33	

1	2	3	4	5
Ajhai Khurd—Contd.	892 Min	0	14	57
	896 Min	0	06	88
	897 Min	0	33	59
	912 Min	0	00	81
	1267 Min	0	02	43
	1277 Min	0	21	04
	1279 Min	0	00	81
	1281 Min	0	01	62
	1283 Min	0	21	85
	1284 Min	0	11	74
	1288 Min	0	17	40
	1289 Min	0	20	23
	1311 Min	0	20	23
	1313 Min	0	25	50
	1315 Min	0	00	40
	1316 Min	0	00	40
	1318 Min	0	25	90
	1320 Min	0	18	62
Chomouhan	770 Min	0	10	12
	771 Min	0	46	54
	774 Min	0	00	40
	775 Min	0	00	81
	777 Min	0	16	59
	778 Min	0	12	95
	828 Min	0	01	62
	829 Min	0	10	93
	830 Min	0	31	16
	874 Min	0	12	55
	875 Min	0	00	81
	876 Min	0	24	69
	879 Min	0	01	21
	880 Min	0	05	26
	881 Min	0	14	57
	882 Min	0	14	97
	884 Min	0	01	62
Sihana	889 Min	0	33	59
	890 Min	0	00	40
	891 Min	0	19	83
	894 Min	0	02	83
	895 Min	0	23	47
	964 Min	0	15	78
	965 Min	0	01	21
	85 Min	0	12	14
	86 Min	0	11	74
	87 Min	0	41	68
	88 Min	0	01	62
	194 Min	0	00	40
	197 Min	0	41	28
	207 Min	0	00	81
	209 Min	0	00	81
	223 Min	0	00	81
	242 Min	0	08	90
	243 Min	0	00	81
	244 Min	0	17	00
	245 Min	0	00	81
	247 Min	0	25	50
	248 Min	0	03	64
	322 Min	0	03	24
	338 Min	0	14	16
	339 Min	0	00	40
	340 Min	0	11	33
	341 Min	0	01	21
	342 Min	0	10	52
	362 Min	0	03	24
	364 Min	0	01	21
	368 Min	0	00	81

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Sihana—Contd.	369 Min	0	00	40	Nari—Contd	662 Min	0	17	81
	370 Min	0	00	81		665 Min	0	17	81
	371 Min	0	05	67		683 Min	0	42	49
	377 Min	0	04	45	Semri	15 Min	0	03	24
	378 Min	0	04	86		16 Min	0	00	81
	379 Min	0	00	40		17 Min	0	38	04
	380 Min	0	12	95		25 Min	0	00	81
	381 Min	0	00	81		26 Min	0	21	85
	382 Min	0	03	64		30 Min	0	00	81
	423 Min	0	18	62		36 Min	0	23	47
	424 Min	0	53	42		37 Min	0	12	55
	426 Min	0	23	88		76 Min	0	01	21
	429 Min	0	31	97		79 Min	0	60	70
						609 Min	0	28	33
						610 Min	0	25	50
Konkara	2 Min	0	20	23		619 Min	0	00	81
	4 Min	0	18	21		620 Min	0	57	06
	5 Min	0	00	40		622 Min	0	01	21
	6 Min	0	00	81		628 Min	0	04	45
	8 Min	0	09	31		629 Min	0	40	87
	9 Min	0	12	95		631 Min	0	03	24
	10 Min	0	32	37		639 Min	0	04	05
	58 Min	0	33	59		640 Min	0	21	45
	59 Min	0	00	81		641 Min	0	17	00
	60 Min	0	00	40		642 Min	0	04	45
	62 Min	0	17	81		643 Min	0	26	30
	106 Min	0	00	81	Ranwari	376 Min	0	43	30
	107 Min	0	23	47		377 Min	0	00	40
	108 Min	0	26	71		380 Min	0	04	86
	110 Min	0	00	81		381 Min	0	01	21
	115 Min	0	14	57		382 Min	0	31	57
						383 Min	0	00	81
						384 Min	0	19	02
Nari	73 Min	0	47	75		385 Min	0	14	16
	74 Min	0	00	81		386 Min	0	02	02
	92 Min	0	00	81		388 Min	0	00	81
	94 Min	0	37	64		389 Min	0	14	16
	95 Min	0	00	40		397 Min	0	10	12
	96 Min	0	00	81		398 Min	0	00	81
	97 Min	0	07	28		399 Min	0	01	62
	104 Min	0	03	24		403 Min	0	00	81
	113 Min	0	00	40		411 Min	0	31	16
	114 Min	0	18	21		413 Min	6	02	02
	115 Min	0	00	81		414 Min	0	20	64
	116 Min	0	10	12		415 Min	0	21	04
	120 Min	0	21	45		416 Min	0	00	81
	124 Min	0	00	40		417 Min	0	18	21
	603 Min	0	53	02		420 Min	0	00	81
	604 Min	0	12	14		421 Min	0	16	59
	606 Min	0	00	81		422 Min	0	01	21
	608 Min	0	34	40	Gohari	423 Min	0	42	09
	615 Min	0	00	40		11 Min	0	41	28
	616 Min	0	00	81		13 Min	0	06	47
	632 Min	0	00	81		26 Min	0	06	07
	634 Min	0	08	09		27 Min	0	36	42
	635 Min	0	02	39		28 Min	0	10	93
	636 Min	0	01	21		29 Min	0	04	05
	646 Min	0	00	40		31 Min	0	01	21
	654 Min	0	20	23		32 Min	0	01	21
	655 Min	0	05	26		40 Min	0	05	26
	656 Min	0	00	40		41 Min	0	01	21
	659 Min	0	08	90		42 Min	0	01	21
	660 Min	0	03	24		43 Min	0	02	83
	661 Min	0	08	50		44 Min	0	13	76
						45 Min	0	13	76
						46 Min	0	05	26

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Navipur	4 Min	0	15	78	Kotban—Contd.	605 Min	0	59	08
	5 Min	0	33	18		608 Min	0	23	07
	6 Min	0	09	31		609 Min	0	21	45
	98 Min	0	37	23		659/14 Min	0	07	28
	101 Min	0	00	40		659/13 Min	0	16	19
	102 Min	0	15	78		667 Min	0	02	43
	104 Min	0	02	02		684 Min	0	04	05
	105 Min	0	08	50		686 Min	0	04	86
	106 Min	0	04	86		688 Min	0	29	14
	110 Min	0	03	24		689 Min	0	38	04
	136 Min	0	03	24	Chhata	130 Min	0	10	93
	137 Min	0	01	21		131 Min	0	36	83
	150 Min	0	01	21		132 Min	0	21	45
	155 Min	0	14	57		145 Min	0	15	38
	156 Min	0	50	96		165 Min	0	01	62
	157 Min	0	44	11		166 Min	0	01	21
	188 Min	0	04	86		167 Min	0	02	43
	191 Min	0	21	45		168 Min	0	09	31
	192 Min	0	00	40		169 Min	0	00	40
	193 Min	0	01	21		170 Min	0	11	74
	194 Min	0	34	40		171 Min	0	01	62
	195 Min	0	30	76		175 Min	0	26	71
	198 Min	0	02	02		176 Min	0	19	42
	199/1 min	0	14	57		177 Min	0	07	28
	200 Min	0	34	80		178 Min	0	09	71
	205 Min	0	00	81		181 Min	0	09	31
	240 Min	0	25	50		182 Min	0	37	23
	250 Min	0	22	26		1382 Min	0	14	16
	251 Min	0	01	21		1383 Min	0	03	24
	252 Min	0	17	40		1384 Min	0	02	83
	258 Min	0	00	81		1385 Min	0	01	21
	259 Min	0	07	69		1392 Min	0	04	45
	260 Min	0	12	14		1393 Min	0	13	76
	199/2 Min	0	06	48		1394 Min	0	00	40
Umrala	2 Min	0	64	75		1395 Min	0	12	95
	13 Min	0	02	02		1508 Min	0	12	55
	15 Min	0	09	31		1509 Min	0	01	62
	33 Min	0	00	81		1528 Min	0	00	40
	34 Min	0	26	30		1529 Min	0	02	43
	35 Min	0	34	80		1530 Min	0	01	21
	36 Min	0	17	00		1532 Min	0	00	81
	37 Min	0	00	81		1533 Min	0	16	19
	38 Min	0	33	59		1536 Min	0	57	47
	39 Min	0	50	18		1537 Min	0	20	64
	80 Min	0	31	97		1538 Min	0	00	81
	85 Min	0	21	85		1541 Min	0	24	28
	87 Min	0	00	81		1542 Min	0	02	83
	89 Min	0	26	30		1543 Min	0	02	02
	90 Min	0	02	02		1557 Min	0	01	62
	91 Min	0	01	21		1559 Min	0	25	09
	93 Min	0	00	81		1562 Min	0	34	40
Kotban	57 Min	0	06	88		1565 Min	0	02	02
	73 Min	0	15	78		1568 Min	0	29	14
	74 Min	0	08	09		1570 Min	0	12	55
	75 Min	0	06	88		1657 Min	0	10	12
	76 Min	0	17	81		1658 Min	0	48	56
	77 Min	0	08	09		1659 Min	0	07	28
	78 Min	0	08	50		1661 Min	0	00	81
	80 Min	0	17	81		1664 Min	0	00	40
	82 Min	0	00	81		1665 Min	0	05	67
	83 Min	0	25	90		1666 Min	0	02	43
	84 Min	0	18	21		1667 Min	0	02	43
	117 Min	0	00	81		1668 Min	0	06	88
	119 Min	0	34	40		1672 Min	0	15	78
	123 Min	0	00	81		1673 Min	0	04	05
	595 Min	0	00	81		1674 Min	0	06	48

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Chhata—Contd.	1691 Min	0	27	92	Kosi Kalan—Contd.	472 Min	0	00	81
	1692 Min	0	08	81		473 Min	0	10	52
Kosi Kalan	14 Min	0	04	86		478 Min	0	06	48
	19 Min	0	02	02		480 Min	0	01	21
	20 Min	0	01	21		486 Min	0	01	62
	27 Min	0	19	02		487 Min	0	23	88
	30 Min	0	02	83		611 Min	0	15	78
	31 Min	0	12	55		618 Min	0	04	86
	34 Min	0	10	52		619 Min	0	00	40
	35 Min	0	00	81		620 Min	0	06	07
	36 Min	0	00	40		621 Min	0	02	02
	37 Min	0	19	42		651 Min	0	00	40
	39 Min	0	04	45		652 Min	0	01	62
	40 Min	0	00	40		650 Min	0	21	45
	128 Min	0	17	81		654 Min	0	03	64
	130 Min	0	02	83		655 Min	0	04	45
	131 Min	0	06	88		663 Min	0	04	05
	133 Min	0	17	40		665 Min	0	00	81
	140 Min	0	06	07		676 Min	0	00	81
	142 Min	0	01	21		677 Min	0	26	71
	143 Min	0	12	14		678 Min	0	14	16
	144 Min	0	05	67		684 Min	0	01	21
	145 Min	0	01	21		702 Min	0	12	55
	147 Min	0	04	05		703 Min	0	12	14
	148 Min	0	29	14		705 Min	0	27	92
	149 Min	0	00	81		708 Min	0	08	50
	150 Min	0	13	76		709 Min	0	17	81
	151 Min	0	08	90		711 Min	0	02	02
	152 Min	0	08	09		712 Min	0	00	81
	181 Min	0	09	31		713 Min	0	00	81
	222 Min	0	39	66		714 Min	0	00	40
	224 Min	0	10	52		1650 Min	0	02	02
	471 Min	0	01	21		1666 Min	0	00	40
						1888/481 Min	0	02	02

[No. 12020/9/80-Prod]

गुडि पत्र

का० ३१० 2961.—पेट्रोलियम और खनिज पदार्थों (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के अन्तर्गत भारत सरकार पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना का० प्रा० सं० 1461 संख्या 12020/10/80 प्रोड दिनांक 8-5-80 से संलग्न अनुसूची में भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) दिनांक 24-5-80 में प्रकाशित सहस्रील गुडगांव जिला गुडगांव राज्य हरियाणा के लिये :

के स्थान पर					पट्टे				
ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल			खसरा नं०	क्षेत्रफल			
		हेक्टर	ऐयर	वर्ग मी०		हेक्टर	ऐयर	वर्ग मी०	
1	2	3	4	5	7	8	9		
सीलामी ह० न० 207	16/2/2 भिन	0	06	07	16/6/5 भिन	0	06	07	
	24/9/1 "	0	00	51	24/9/1/1 "	0	00	51	
	47/25/1 "	0	03	80	42/25 "	0	03	80	
	57/5 "	0	12	14	57/5 "	0	16	19	
	77/17/1/2 "	0	02	02	77/17/1/1 "	0	02	02	
	58/19 "	0	10	37	{ 58/19/1 "	0	09	61	
					{ 58/19/2 "	0	00	78	
	77/17/2 "	0	02	78	77/17/2 "	0	08	35	
	77/17/3 "	0	02	78					
	77/17/4 "	0	02	78					
58/22/1 "	0	06	58	58/22/1/1 "	0	06	58		
करनकी ह० न० 206	3/10 "	0	05	06	2/10 "	0	05	06	
	3/9 "	0	05	57	2/9 "	0	05	57	
	3/12 "	0	12	14	2/12 "	0	12	14	
	3/18 "	0	08	60	2/18 "	0	08	60	
	3/19 "	0	03	54	2/19 "	0	03	54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
करमकी ह०न० 206—जारी	3/23	मिन	0	11	64	2/23	मिन	0	11	64
	3/24	"	0	00	51	2/24	"	0	00	51
	—	"	0	00	00	20/20	"	0	07	84
	22	"	0	12	14	20/22	"	0	12	14
	30/13/3	"	0	01	01	30/13/1/1	"	0	01	01
	13/17	"	0	05	31	13/17/2	"	0	05	31
	30/8/1	"	0	02	28	30/8/1/2	"	0	02	28
	30/8/3	"	0	03	54	30/8/3/2	"	0	03	54
साँहड़पुर ह०न० 203	18/6/1 2	"	0	06	07	18/6/1	"	0	00	25
						18/6/2	"	0	05	82
हरचन्दपुर ह०न० 199	617/49	"	0	15	18	49	"	0	15	18
	621/622/52	"	0	16	45	52	"	0	16	45
	—	"	0	00	00	55	"	0	00	00
	621/622/56	"	0	03	80	56	"	0	03	80
	621/622/60	"	0	97	59	60	"	0	07	59
	621/622/58	"	0	07	59	58	"	0	07	59
	621/622/59	"	0	10	12	59	"	0	10	12
	621/622/66	"	0	03	80	66	"	0	03	80
	621/622/70	"	0	11	39	70	"	0	11	39
	621/622/71	"	0	05	06	71	"	0	05	06
	621/622/72	"	0	12	65	72	"	0	12	65
	621/622/73	"	0	02	53	73	"	0	02	53
	621/622/80	"	0	16	45	80	"	0	16	45
	621/622/75	"	0	18	98	75	"	0	18	98
	621/622/76	"	0	11	39	76	"	0	11	39
	621/622/77	"	0	06	33	77	"	0	06	33
	621/622/78	"	0	07	59	78	"	0	07	59
	621/622/232	"	0	03	80	232	"	0	03	80
	621/622/239	"	0	15	18	239	"	0	15	18
	621/622/238	"	0	20	24	238	"	0	20	24
	621/622/240	"	0	01	27	240	"	0	01	27
	621/622/469	"	0	01	27	469	"	0	01	27
	621/622/470	"	0	11	39	470	"	0	11	39
	621/622/471	"	0	02	53	471	"	0	02	53
	621/622/472	"	0	00	00	472	"	0	00	00
	621/622/475	"	0	06	33	475/2	"	0	06	33
	621/622/477	"	0	10	12	477	"	0	10	12
	621/622/478	"	0	03	80	478	"	0	03	80
	621/622/479	"	0	00	00	479	"	0	00	00
	621/622/438/3	"	0	07	59	438/3	"	0	07	59
	621/632/435	"	0	01	27	435	"	0	01	27
	621/622/437	"	0	02	53	437	"	0	02	53
	621/622/434	"	0	00	00	434	"	0	00	00
	621/622/436	"	0	06	33	436	"	0	06	36
	621/622/431	"	0	01	27	431	"	0	01	27
	621/622/432	"	0	07	59	432	"	0	07	59
	698/429	"	0	02	53	429	"	0	02	53
	693/425	"	0	03	80	425	"	0	03	80
	693/424	"	0	02	53	424	"	0	02	53
	693/423	"	0	06	33	423	"	0	06	33
	693/422	"	0	06	33	422	"	0	06	33
	693/405	"	0	17	71	405	"	0	17	71
	693/410	"	0	08	86	410	"	0	08	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
हस्वन्वपुर ह०न० 199-जारी	693/409	मिन	०	02	53	409	मिन	0	02	53
	693/406	"	0	06	33	406	"	0	06	33
	693/407	"	0	02	53	407	"	0	02	53
	693/408	"	0	01	27	408	"	0	01	27
	693/400	"	0	11	39	400	"	0	11	39
	693/399	"	0	12	65	399	"	0	12	65
	693/398	"	0	12	65	398	"	0	12	65
	693/474	"	0	03	80	474/1	"	0	03	80
	693/474/3	"	0	03	80	474/3	"	0	03	80
						55	"	0	00	00
बोवरी ह०न० 196	60	"	0	05	30	60	"	0	25	30
	175/87	"	0	12	65	87	"	0	12	65
	175/86	"	0	15	18	86	"	0	15	18
ग्रामपुर ह०न० 173	117	"	0	01	01	117/3	"	0	01	01
वमरमा ह०न० 174	11/15	"	0	05	06	11/15/1	"	0	00	25
						11/15/2	"	0	04	80
	11/16	"	0	02	53	11/16/1	"	0	01	61
						11/16/2	"	0	01	01
	33/10/1	"	0	12	14	33/10	"	0	12	14
बेडला ह०न० 177	18/3/1	"	0	09	10	18/3/2	"	0	09	10
	18/3/2	"	0	02	02	18/3/1	"	0	02	02
	52/82	"	0	00	50	82	"	0	00	50
	30/19	"	0	00	76	30/19/2	"	0	00	76
	39/18	"	0	08	85	39/18/1	"	0	08	85
						39/18/2	"	0	00	00
	52/4	"	0	09	35	52/4/1	"	0	09	35
बहेलपा ह०न० 171	28/102	"	0	00	50	102	"	0	00	50
	38/53	"	0	00	76	53	"	0	00	76
	28/22	"	0	02	78	28/22/2	"	0	02	78
सहजावास ह०न० 170	24/12/2	"	0	00	25	24/12/2	"	0	00	50
	27/4	"	0	10	12	27/4	"	0	10	88
	28/20/3	"	0	06	57	28/20/2/2	"	0	06	57
	52/24/12/2	"	0	00	50	---	"	---	---	---
	52/98	"	0	00	50	---	"	---	---	---
	52/99	"	0	00	50	99	"	0	00	76
	52/100	"	0	00	50	100	"	0	00	50
	52/104	"	0	00	50	104	"	0	00	50
	24/23	"	0	00	25	24/23/2	"	0	00	25
	28/20/3	"	0	06	57	28/20/2/2	"	0	06	57
रिडोज ह०न० 169	---	"	---	---	---	54/23/2	"	0	00	00
						55/9/1	"	0	00	00
भोंडसी ह०न० 168	16/6	"	0	01	01	16/6/1	"	0	01	01
						16/6/2	"	0	00	00
	---	"	0	---	---	35/21	"	0	00	00
						79/9/1	"	0	00	00
मेवावास ह०न० 85	45/1	"	0	03	04	45/1	"	0	04	05
	45/2	"	0	07	08	45/2	"	0	06	07
	61/24	"	0	00	51	61/24/1	"	0	00	51
	---	"	---	---	---	45/10	"	0	00	00
	---	"	---	---	---	73/24	"	0	00	00
नवली कमरपुर ह०न० 82	---	"	---	---	---	8/9	"	0	00	00
	---	"	---	---	---	13/7	"	0	00	0

1	2		3	4	5	6		7	8	9
विगग ह०न० 51	88	मिन	0	00	51	88/1	मिन	0	00	51
	15/6/1/1	"	0	01	01	15/6/1/1/1	"	0	01	01
	23/12	"	0	01	10	23/12	"	0	01	01
	—	"	—	—	—	4/17/2	"	0	00	00
बजीगाबाद ह०न० 75	848	"	0	08	86	848/1	"	0	06	32
	—	"	—	—	—	848/2	"	0	02	53
	—	"	—	—	—	671	"	0	00	00
	—	"	—	—	—	795/1	"	0	00	00
	—	"	—	—	—	869	"	0	00	00
	—	"	—	—	—	879	"	0	00	00
	—	"	—	—	—	846	"	0	00	00
	—	"	—	—	—	852	"	0	00	00
कासई ह०न० 73	40/12	"	0	10	12	40/12/1	"	0	09	61
	—	"	—	—	—	40/12/2	"	0	00	51
सीखोखरा ह०न० 72	—	"	—	—	—	18/17	"	0	00	00
सुखराही ह०न० 71	14/17	"	0	00	76	14/17/1	"	0	00	76
सीरहाल ह०न० 70	43/3/1	"	0	00	25	43/3/1/2	"	0	00	25
	—	"	—	—	—	29/7/2	"	0	00	00
	—	"	—	—	—	29/9/2/1	"	0	00	00
	—	"	—	—	—	43/1	"	0	00	00
हनायन पुर ह०न० 64	13/23/1	"	0	03	54	13/23/2	"	0	03	54
	16/19/1	"	0	02	78	—	—	—	—	—
	16/18	"	0	03	04	—	—	—	—	—
	16/23	"	0	10	63	—	—	—	—	—
	16/24	"	0	06	93	—	—	—	—	—
	13/14/2	"	0	00	25	13/14/2/2	"	0	00	25
	—	"	—	—	—	13/16/3	"	0	00	00
	—	"	—	—	—	16/13/1	"	0	00	00
	—	"	—	—	—	27/1	"	0	00	—

[क्रम सं. 12020/10/90-प्रोड०]

CORRIGENDUM

S.O. 2961 —In the Schedule appended to the notification of the Government of India, Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Petroleum) S.O. No. 1461 (No. 12020/10/80 (Prod) dated 8th May, 1980 issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in Land) Act, 1962 (50 of 1962) published at pages 1495—1503 dated 24th May, 1980 of the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (ii) for Tahsil Gurgaon Distt, Gurgaon State of Haryana

Name of Village	For				Read			
	Khasra No	H	A	Sq Mtrs	Khasra No	H	A	Sq Mtrs
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Selani H No. 207	16/6/2 Min	0	06	07	16/6/5 Min	0	06	07
	24/91/1 Min	0	00	51	24/91/1/1 Min	0	00	51
	47/25/1 Min	0	03	80	47/25 Min	0	03	80
	57/5 Min	0	12	14	57/5 Min	0	16	19
	77/17/1/2 Min	0	02	02	77/17/1/1 Min	0	02	02
	58/19 Min	0	10	37	58/19/1	0	09	61
					58/19/2 Min	0	00	76
	77/17/2 Min	0	02	78	77/17/2 Min	0	08	35
	77/17/3 Min	0	02	78				
	77/17/4 Min	0	02	78				
	58/22/1 Min	0	06	58	58/22/1/1 Min	0	06	58
	3/10 Min	0	05	06	2/10 Min	0	05	06
	3/9 Min	0	05	57	2/9 Min	0	05	57
	3/12 Min	0	12	14	2/12 Min	0	12	14
Karanki H No 206	3/18 Min	0	08	60	2/18 Min	0	08	60
	3/19 Min	0	03	54	2/19 Min	0	03	54
	3/23 Min	0	11	64	2/23 Min	0	11	64
	3/24 Min	0	00	51	2/24 Min	0	00	51
	—	0	00	00	20/20 Min	0	07	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Karanki H. No. 206 (contd)	22 Min	0	12	14	20/22 Min	0	12	14
	30/13/3 Min	0	01	01	30/13/1/3 Min	0	01	01
	13/17 Min	0	05	31	13/17/2 Min	0	05	31
	30/8/1 Min	0	02	28	30/8/1/2 Min	0	02	28
	30/8/3 Min	0	03	54	30/8/3/2 Min	0	03	54
Choharpur H.No. 203	18/6/1/2 Min	0	06	07	18/6/1 Min	0	00	25
					18/6/2 Min	0	05	82
Harchandpur H.No. 199	617/49 Min	0	15	18	49 Min	0	15	18
	621/622/52 Min	0	16	45	52 Min	0	16	45
	—	0	00	00	55 Min	0	00	00
	621/622/56 Min	0	03	80	56 Min	0	03	80
	621/622/60 Min	0	97	59	60 Min	0	07	59
	621/622/58 Min	0	07	59	58 Min	0	07	59
	621/622/59 Min	0	10	12	59 Min	0	10	12
	621/622/66 Min	0	03	80	66 Min	0	03	80
	621/622/70 Min	0	11	39	70 Min	0	11	39
	621/622/71 Min	0	05	06	71 Min	0	05	06
	621/622/72 Min	0	12	65	72 Min	0	12	56
	621/622/73 Min	0	02	53	73 Min	0	02	53
	621/622/80 Min	0	16	45	80 Min	0	16	45
	621/622/75 Min	0	18	98	75 Min	0	18	98
	621/622/76 Min	0	11	39	76 Min	0	11	39
	621/622/77 Min	0	06	33	77 Min	0	06	33
	621/622/78 Min	0	07	59	78 Min	0	07	59
	621/622 232 Min	0	03	80	232 Min	0	03	80
	621/622/239 Min	0	15	18	239 Min	0	15	18
	621/622 238 Min	0	20	24	238 Min	0	20	24
	621/622/240 Min	0	01	27	240 Min	0	01	27
	621/622/469 Min	0	01	27	469 Min	0	01	27
	621/622/470 Min	0	11	39	470 Min	0	11	39
	621/262/471 Min	0	02	53	471 Min	0	02	53
	621/622/472 Min	0	00	00	472 Min	0	00	00
	621/622/475 Min	0	06	33	475/2 Min	0	06	33
	621/622/477 Min	0	10	12	477 Min	0	10	12
	621/622/478 Min	0	03	80	478 Min	0	03	80
	621/622/479 Min	0	00	00	479 Min	0	00	00
	621/622/438/3 Min	0	07	59	438/3 Min	0	07	59
	621/622/435 Min	0	01	27	435 Min	0	01	27
	621/622/437 Min	0	02	53	437 Min	0	02	53
	621/622/434 Min	0	00	00	434 Min	0	00	00
	621/622/436 Min	0	06	33	436 Min	0	06	33
	621/622/431 Min	0	01	27	431 Min	0	01	27
	621/622/432 Min	0	07	59	432 Min	0	07	59
	698/429 Min	0	02	53	429 Min	0	02	53
	693/425 Min	0	03	80	425 Min	0	03	80
	693/424 Min	0	02	53	424 Min	0	02	53
	693/423 Min	0	06	33	423 Min	0	06	33
	693/422 Min	0	06	33	422 Min	0	06	33
	693/405 Min	0	17	71	405 Min	0	17	71
	693/410 Min	0	08	86	410 Min	0	08	86
	693/409 Min	0	02	53	409 Min	0	02	53
	693/406 Min	0	06	33	406 Min	0	06	33
	693/407 Min	0	02	53	407 Min	0	02	53
	693/408 Min	0	01	27	408 Min	0	01	27
	693/400 Min	0	11	39	400 Min	0	11	39
	693/399 Min	0	12	65	399 Min	0	12	65
	693/398 Min	0	12	65	398 Min	0	12	65
	693/474 Min	0	03	80	474/1 Min	0	03	80
	693/474/3 Min	0	03	80	474/3 Min	0	03	80
					55 Min.	0	00	00
Khobri H. No. 196	60 Min	0	05	30	60 Min	0	25	30
	175/87 Min	0	12	65	87 Min	0	12	65
	175/86 Min	0	15	18	86 Min	0	15	18
Abhepur H. No. 173	117 Min	0	01	01	117/3 Min	0	01	01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dandama H. No. 174	11/15 Min	0	05	06	11/15/1 Min 11/15/2 Min	0	00 04	25 80
	11/16 Min	0	02	53	11/16/1 Min 11/16/2 Min	0	01 01	51 01
Kherla H. No. 177	33/10/1 Min	0	12	14	33/10 Min	0	12	14
	18/3/1 Min	0	09	10	18/3/2 Min	0	09	10
	18/3/2 Min	0	02	02	18/3/1 Min	0	02	02
	52/82 Min	0	00	50	82 Min	0	00	50
	30/19 Min	0	00	76	30/19/2 Min	0	00	76
	39/18 Min	0	08	85	39/18/1 Min 39/18/2 Min	0	08 00	85 00
	52/4 Min	0	09	35	52/4/1 Min	0	09	35
Behlpa H. No. 171	28/102 Min	0	00	50	102 Min	0	00	50
	38/53 Min	0	00	76	*3 Min	0	00	76
	28/22 Min	0	02	78	28/22/2 Min	0	02	78
Schjawas H. No. 170	24/12/2 Min	0	00	25	24/12/2 Min	0	00	50
	27/4 Min	0	10	12	27/4 Min	0	10	88
	28/20/3 Min	0	06	57	28/20/2/2 Min	0	06	57
	52/24/12/2 Min	0	00	50	.. Min
	52/98 Min	0	00	50	.. Min
	52/99 Min	0	00	50	99 Min	0	00	76
	52/100 Min	0	00	50	100 Min	0	00	50
	52/104 Min	0	00	50	104 Min	0	00	50
	24/23 Min	0	00	25	24/23/2 Min	0	00	25
	28/20/3 Min	0	06	57	28/20/2/2 Min	0	06	57
Rethoj H. No. 169	.. Min	54/23/2 Min 55/9/1 Min	0	00 00	00 00
Bhondai H. No. 168	16/6 Min	0	01	01	16/6/1 Min 16/6/2 Min	0	01 00	01 00
	.. Min	35/21 Min 79/9/1 Min	0	00 00	00 00
Medawas H. No. 85	45/1 Min	0	03	04	45/1 Min	0	04	05
	45/2 Min	0	07	08	45/2 Min	0	06	07
	61/24 Min	0	00	51	61/24/1 Min	0	00	51
	.. Min	45/10 Min	0	00	00
	.. Min	73/24 Min	0	00	00
Nangli Umarpur H. No. 82	.. Min	8/9 Min	0	00	00
	.. Min	13/7 Min	0	00	00
Tigra H. No. 51	88 Min	0	00	51	88/1 Min	0	00	51
	15/6/1/1 Min	0	01	01	15/6/1/1/1 Min	0	01	01
	23/12 Min	0	01	10	23/12 Min	0	01	01
	.. Min	4/17/2 Min	0	00	00
Wazirabad H. No. 75	848 Min	0	08	86	848/1 Min 848/2 Min	0	06 02	32 53
	.. Min	671 Min	0	00	00
	.. Min	795/1 Min	0	00	00
	.. Min	869 Min	0	00	00
	.. Min	879 Min	0	00	00
	.. Min	846 Min	0	00	00
	.. Min	852 Min	0	00	00
Kanai H. No. 73	40/12 Min	0	10	12	40/12/1 Min 40/12/2 Min	0	09 00	61 51
Silokhra Ho. No. 72	.. Min	18/17 Min	0	00	00
Sukhrali H. No. 71	14/17 Min	0	00	76	14/17/1 Min	0	00	76
Sirhole H. No. 70	43/3/1 Min	0	00	25	43/3/1/2 Min	0	00	25
	.. Min	29/7/2 Min	0	00	00
	.. Min	29/9/2/1 Min 43/1 Min	0	00 00	00 00
Inayatpur H. No. 64	13/23/1 Min	0	03	54	13/23/2 Min	0	03	54
	16/19/1 Min	0	02	78	.. Min
	16/18 Min	0	03	04	.. Min
	16/23 Min	0	10	63	.. Min
	16/24 Min	0	06	83	.. Min
	13/14/2 Min	0	00	25	13/14/2/2 Min	0	00	25
	.. Min	13/16/3 Min 16/13/1 Min 27/1 Min	0 0 0	00 00 00	00 00 00

नई दिल्ली 10 अक्टूबर 1980

का० प्रा० सं० 2962.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पदार्थों (भूमि के उपयोग के अधिकार का अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० प्रा० सं० 1616 तारीख 26-5-80 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को प्राप्त लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना अधिकार घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और प्राये, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और प्राये उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग में, सभी संयंत्रों से मुक्त रूप से, बोझों के प्रकाशन की इस शारीर को निहित होगा।

अनुसूची

पानसर—2 से जी० जी० एम पानसर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य: गुजरात	जिला: मेहसाना	तालुका: कलोल			
गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टेयर	गुनार्ड	सेन्टीयर	
पानसर	1652	0	07	50	
	1313	0	10	50	
	1312	0	06	90	
	1309	0	12	00	
	1308	0	12	30	
	1306	0	01	00	
	कार्टट्रेक	0	00	90	
	1270	0	11	40	
	1273	0	10	05	
	1263	0	09	00	
	कार्ट ट्रेक	0	01	50	
	1086	0	16	80	
	1087	0	16	95	
	1079	0	08	85	
	1078	0	34	65	
	948	0	15	00	
	939	0	16	05	
	935	0	13	50	
	934	0	05	10	
	933	0	01	80	
	932	0	19	80	
	925	0	10	55	
	924	0	14	55	
	923	0	08	70	

New Delhi, the 10th October, 1980

S.O. 2962.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 1616 dated 26-5-80 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Pansar—2 to GGS Pansar

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Block No.	Hectare	Acres	Centiare
1	2	3	4	5
Pansar	1652	0	07	50
	1313	0	10	50
	1312	0	06	90
	1309	0	12	00
	1308	0	12	30
	1306	0	01	00
	Cart track	0	00	90
	1270	0	11	40
	1273	0	10	05
	1263	0	09	00
	Cart track	0	01	50
	1086	0	16	80
	1087	0	16	95
	1079	0	08	85
	1078	0	34	65
	948	0	15	00
	939	0	16	05
	935	0	13	50
	934	0	05	10
	933	0	01	80
	932	0	19	80
	925	0	10	55
	924	0	14	55
	923	0	08	70

[No. 12016/25/80-Pro.-II]

का० प्रा० 2963.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पदार्थों (भूमि के उपयोग के अधिकार का अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० प्रा० सं० 1615 तारीख 26-5-80 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को प्राप्त लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना अधिकार घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाश्चात्त्य विज्ञान के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संयंत्रों से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कूप नं० के० जे० एक्स० से जी० जी० ए० तक पाश्चात्त्य विज्ञान के लिए।

राज्य : गुजरात	जिला : मेहसाणा	तालुका : कलोल			
गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टेयर	एकराई	सेण्टीयर	
पानसर	925	0	03	00	
	924	0	11	40	
	924	0	01	80	
	923	0	09	45	

[नं० 12016/25/80—प्रो० I]

किरण चट्टा, सचिव

S.O. 2963.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 1615 dated 20-5-80 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report of the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Well No. KJX to GGS

State : Gujarat	District : Mehsana	Taluka : Kalol			
Village	Block No.	Hec- tare	Are	Centi- me	
Pansar	925	0	03	00	
	924	0	11	40	
	924	0	01	80	
	923	0	09	45	

[No. 12016/25/80—Pro. I]

KIRAN CHADHA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1980

का० खा० 2964.—स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम, 1966 (1966 का 51) की धारा 5 के खण्ड (ड) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री आई० सी० पुरी, मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को श्री के० एस० नारंग के स्थान पर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ का सदस्य मनोनीत करती है और भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 30 जून, 1977 की अधिसूचना संख्या बी० 17013/1/77-एम० ई० (पी० जी०) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में अब संख्या 3 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात् :—

“3. श्री आई० सी० पुरी, मुख्य सचिव,
पंजाब सरकार, चंडीगढ़।”

[संख्या बी० 17011/3/80-एम० ई० (पी० जी०)
पी० सी० जैन, सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Health Department)

New Delhi, the 15th September, 1980

S.O. 2964.—In pursuance of clause (d) of section 5 of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Act, 1966 (No. 51 of 1966), the Central Government hereby nominates Shri I. C. Puri, Chief Secretary to the Government of Punjab, Chandigarh to be a Member of the Post-Graduate Institute of Medication Education and Research, Chandigarh vice Shri K. S. Narang and makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare Notification No. V. 17013/1/77-ME(PG) dated the 30th June, 1977 namely :—

In the said notification, for item number 3 and the entries relating thereto the following shall be substituted namely :—

“3 Shri I. C. Puri, Chief Secretary, Government of Punjab, Chandigarh.”

[No. V. 17011/3/80-ME(PG)]

P. C. JAIN, Under Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 1980

का० खा० 2965—कोयला खान भविष्य निधि योजना के पैरा 9 के साथ पठित कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 3ए उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत

सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सां. प्रा. 2151, दिनांक 10 जलाई, 1978 में निम्नलिखित संशोधित करती है, यथा:—

उपर्युक्त अधिसूचना में, "सदस्य" शीर्षक के अधीन क्रम संख्या 12 और 17 के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, यथा:—

"12. श्री राजेन्द्र सिंह, निवेशक (कामिक), सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि., बरभंगा हाउस, रांची

17. श्री डी. वी. परांजपे, महा प्रबंधक, सिंगरेनी कोलियरीज कं. लिमिटेड, डाकघर—कोठागुडम कोलियरीज, (आंध्र प्रदेश)।"

[सं. 7 (3)/80-प्रशा. I (पी. एफ.)

ए. एस. देशपांडे, उप सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 13th October, 1980

S.O. 2965.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948), read with paragraph 9 of the Coal Mines Provident Fund Scheme, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, No. S.O. 2151, dated the 10th July, 1978, namely:—

In the said notification, under the heading 'Members', against serial numbers 12 and 17, for the entries, the following entries shall respectively be substituted, namely:—

"12. Shri Rajindra Singh, Director (Personnel), Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi.

17. Shri D. V. Paranjpe, General Manager, Singareni Collieries Company Limited, Post Office, Kolhagudem Collieries (Andhra Pradesh).

[No. 7(3)/80-Adm-I(PF)]

A. S. DESHPANDE, Dy. Secy.

हस्तात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 1980

सां. प्रा. 2965.—केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 9 के उप-नियम (2), नियम 12 के उप-नियम (2) की धारा (ख) तथा नियम 24 के उप-नियम (1) द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, हस्तात और खान मंत्रालय (खान विभाग) के दिनांक 27 अक्टूबर 1977 के आदेश संख्या सां. प्रा. 3495 का अधिग्रहण करते हुए, राष्ट्रपति एतद्वारा निदेश देते हैं कि:—

- (1) इस आदेश की अनुसूची के भाग-1 के कालम (1) में उल्लिखित सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'क' पदों के बारे में कालम (2) की समकक्ष प्रविष्टि में उल्लिखित प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी होगा, तथा कालम (3) और (5) की समकक्ष प्रविष्टियों में उल्लिखित प्राधिकारी कालम (4) में उल्लिखित शास्तियों के संबंध में क्रमशः अनुशासन प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी होंगे।
- (2) कथित अनुसूची के भाग-II के कालम (1) में उल्लिखित सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ब' के पदों के संबंध में, कालम (2) की समकक्ष प्रविष्टि में उल्लिखित प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी होगा तथा कालम (3) और (5) की समकक्ष प्रविष्टियों में उल्लिखित प्राधिकारी, कालम (4)

में उल्लिखित शास्तियों के संबंध में क्रमशः अनुशासन प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी होंगे।

अनुसूची

पद का नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 11 की मर संख्याओं के संदर्भ में शास्तियां लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी और शास्तियां प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	
1	2	3	4	5

भाग-I—सामान्य केन्द्रीय सेवाएं—वर्ग 'ग'

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय के विशेषीकृत प्रभागों, सकल कार्यालय, कोयला प्रभाग तथा हवाई खनिज सर्वेक्षण और गवेषण स्कंध सहित प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के पद।	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का वरिष्ठ उप महानिदेशक (आपरेशन) या जहां क्षेत्रीय कार्यालय के विशेषीकृत प्रभागों, सकल कार्यालय कोयला प्रभाग तथा हवाई खनिज सर्वेक्षण और गवेषण स्कंध सहित संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में वरिष्ठ उप-महानिदेशक (आपरेशन) नहीं है वहां क्षेत्रीय कार्यालय के विशेषीकृत प्रभागों, सकल कार्यालय कोयला प्रभाग तथा हवाई खनिज सर्वेक्षण और गवेषण स्कंध सहित संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के लिए उप महानिदेशक (भूविज्ञान)।	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का वरिष्ठ उप महानिदेशक (आपरेशन) या जहां क्षेत्रीय कार्यालय के विशेषीकृत प्रभागों, सकल कार्यालय कोयला प्रभाग तथा हवाई खनिज सर्वेक्षण और गवेषण स्कंध सहित संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में वरिष्ठ उप-महानिदेशक (आपरेशन) नहीं है वहां क्षेत्रीय कार्यालय के विशेषीकृत प्रभागों, सकल कार्यालय कोयला प्रभाग तथा हवाई खनिज सर्वेक्षण और गवेषण स्कंध सहित संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के लिए उप महानिदेशक (भूविज्ञान)।	सभी	महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण।
---	---	---	-----	--

1	2	3	4	5
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के केंद्रीय मुख्यालय के पद।	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का क्षेत्रीय प्रशासन अधिकारी या, जहाँ क्षेत्रीय कार्यालय के विशेषीकृत प्रभागों, कोयला प्रभाग या हवाई खनिज सर्वेक्षण और गवेषण स्कंध सहित संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के लिए कोई क्षेत्रीय प्रशासन अधिकारी नहीं है, वहाँ क्षेत्रीय कार्यालय के विशेषीकृत प्रभागों, कोयला प्रभाग या हवाई खनिज सर्वेक्षण और गवेषण स्कंध सहित संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय हेतु वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी।	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का क्षेत्रीय प्रशासन अधिकारी या, जहाँ क्षेत्रीय कार्यालय के विशेषीकृत प्रभागों, कोयला प्रभाग या हवाई खनिज सर्वेक्षण और गवेषण स्कंध सहित संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के लिए कोई क्षेत्रीय प्रशासन अधिकारी नहीं है, वहाँ क्षेत्रीय कार्यालय के विशेषीकृत प्रभागों, कोयला प्रभाग या हवाई खनिज सर्वेक्षण और गवेषण स्कंध सहित संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय हेतु वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी।	सभी	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का वरिष्ठ उपमहानिदेशक (आप-रेशन) या, जहाँ वरिष्ठ उपमहानिदेशक (आप-रेशन) नहीं है वहाँ संबंधित क्षेत्र, प्रभाग या स्कंध का उपमहानिदेशक (भूविज्ञान)।
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रत्येक सकल कार्यालय के पद।	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के संबंधित सकल कार्यालय का निदेशक (भूविज्ञान)।	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के संबंधित सकल कार्यालय का निदेशक (भूविज्ञान)।	सभी	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का वरिष्ठ उपमहानिदेशक (आप-रेशन) या, जहाँ वरिष्ठ उपमहानिदेशक (भूविज्ञान) नहीं है तो वहाँ संबंधित क्षेत्र, प्रभाग या स्कंध का उपमहानिदेशक (भूविज्ञान)।
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के केंद्रीय मुख्यालय के पद।	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का निदेशक (कामिक)	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का निदेशक (कामिक)।	सभी	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का वरिष्ठ उपमहानिदेशक (कामिक)।

[सं० सी-11012/1/77-आप्त-2]

एच०एच० अली, अक्षर सचिव

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

ORDER

New Delhi, the 13th October, 1980

S.O. 2966.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, and supersession of the order of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. S.O. 3495, dated the 27th October, 1977, the President hereby directs that —

- (1) In respect of the posts in the General Central Service, Group C, specified in column (1) of Part I of the

Schedule to this order, the authority specified in the corresponding entry in column (2) shall be the appointing authority, and the authorities specified in the corresponding entries in columns (3) and (5) shall be the disciplinary authority and the appellate authority respectively in regard to the penalties specified in column (4);

- (2) in respect of the posts in the General Central Service, Group D, specified in column (1) of Part II of the said Schedule, the authority specified in the corresponding entry in column (2) shall be the appointing authority, and the authorities specified in the corresponding entries in columns (3) and (5) shall be the disciplinary authority and the appellate authority respectively in regard to the penalties specified in column (4).

SCHEDULE

Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose with reference to items numbers in rule 11 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal Rules, 1965)	Appellate Authority	Authority
1	2	3	4	5
Part I—General Central Services—Group C				
Posts in each Regional Office including Specialised Divisions of a Regional	Senior Deputy Director General (Operations) or where there is no Senior Deputy Director	Senior Deputy Director General (Operations) or where there is no Senior Deputy Director	All	Director General, Geological Survey of India.

1	2	3	4	5
Office, Circle Office, Coal Division and Airborne Mineral Surveys and Exploration Wing of Geological Survey of India.	General (Operations) for the respective Regional Office including Specialised Divisions of a Regional Office, Circle Office, Coal Division and Airborne Mineral Surveys and Exploration Wing, Deputy Director General (Geology) for the respective Regional Office including Specialised Divisions of a Regional Office, Circle Office, Coal Division and Airborne Mineral Survey, and Exploration Wing of Geological Survey of India.	General (Operations) for the respective Regional Office including Specialised Divisions of a Regional Office, Circle Office Coal Division and Airborne Mineral Surveys and Exploration Wing, Deputy Director General (Geology) for the respective Regional Office including Specialised Divisions of a Regional Office, Circle Office, Coal Division and Airborne Mineral Surveys and Exploration Wing of Geological Survey of India.		
Posts in Central Headquarters of the Geological Survey of India.	Senior Deputy Director General (Personnel)	Senior Deputy Director General All (Personnel).		Director General Geological Survey of India.

PART —II GENERAL CENTRAL SERVICE—GROUP D

Post in each Regional Office including Specialised Divisions of a Regional Office, Coal Division and Airborne Mineral Surveys and Exploration Wing of Geological Survey of India.	Regional Administrative Officer or, where there is no Regional Administrative Officer for the respective Regional Office including Specialised Divisions of a Regional Office, Coal Division or Airborne Mineral Surveys and Exploration Wing, the Senior Administrative Officer for the respective Regional Office including Specialised Divisions of a Regional Office, Coal Division or Airborne Mineral Surveys and Exploration Wing of Geological Survey of India.	Regional Administrative Officer or, where there is no Regional Administrative Officer for the respective Regional Office including Specialised Divisions of a Regional Office, Coal Division or Airborne Mineral Surveys and Exploration Wing, the Senior Administrative Officer for the respective Regional Office including specialised Divisions of a Regional Office, Coal Division or Airborne Mineral Surveys and Exploration Wing of Geological Survey of India.	All	Senior Deputy Director General (Operations) or, where there is no Senior Deputy Director General (Operations), Deputy Director General (Geology) of respective Region, Division or Wing in the Geological Survey of India.
Posts in each Circle Office of the Geological Survey of India.	Director (Geology) of the respective Circle Office in the Geological Survey of India.	Director (Geology) of the respective Circle Office of Geological Survey of India.	All	Senior Deputy Director General (Operations) or, where there is no Senior Deputy Director General (Geology), Deputy Director General (Geology) of respective Region, Division or Wing in the Geological Survey of India.
Posts in Central Headquarters of Geological Survey of India.	Director (Personnel), Geological Survey of India.	Director (Personnel) Geological Survey of India.	All	Senior Deputy Director General (Personnel), Geological Survey of India

[No. C-11012/1/77-M-II]

H.L. ATTRI, Under Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(हिन्दी अनुभाग)

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 1980

क्र० प्र० 2967—राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 8 (4) और 10 (4) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा नौवहन और परिवहन मंत्रालय के निम्नलिखित संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों प्रावि की अधिसूचित करती है, जहाँ के 80 प्रतिशत और उससे अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है :—

1. इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली।
2. सेवा नियंत्रक कार्यालय, नई दिल्ली।
3. अधीक्षक इंजीनियर कार्यालय (सड़क पक्ष), जयपुर।
4. इंजीनियर सम्पर्क अधिकारी कार्यालय (सड़क पक्ष), भोपाल।
5. नौवहन महानिदेशालय, बम्बई।
6. कप्तान अधीक्षक का कार्यालय प्रशिक्षण पोत, 'राजेन्द्र', बम्बई।
7. मुख्य नाविक कल्याण कार्यालय, बम्बई।
8. समुद्री इंजीनियरिंग और प्रशिक्षण कालेज विदेहालय, बम्बई।
9. दीपनर दीपपोत निदेशक कार्यालय, बम्बई।
10. नौवहन शुल्क अनुसंधान ब्यूरो, गांधीघाट।
11. नौवहन शुल्क अनुसंधान ब्यूरो, कांडला।
12. कांडला गोदी श्रम बोर्ड, कायला।
13. कप्तान अधीक्षक का कार्यालय, प्रशिक्षण पोत, 'नवलक्षी' नवलक्षी।
14. क्षेत्रीय कार्यालय (सड़क पक्ष), चण्डीगढ़।
15. इंजीनियर सम्पर्क अधिकारी कार्यालय (सड़क पक्ष), जम्मू।

[फाईल संख्या : एच पी यू/147/80]

बी० शंकरलिंगम, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Hindi Section)

New Delhi, the 16th October, 1980

S.O. 2967.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 8 and sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Government of India hereby notifies the following Attached the Subordinate Offices of the Ministry of Shipping and Transport, 80 per cent staff whereof have been reported to have acquired working knowledge of Hindi :—

1. Indian Roads Construction Corporation Ltd., New Delhi.
2. Office of the Controller of Accounts, New Delhi.
3. Office of the Superintending Engineer (Roads Wing), Jaipur.
4. Office of Engineer Liaison Officer (Roads Wing), Bhopal.
5. Directorate General of Shipping, Bombay.
6. Office of the Captain Superintendent, Training Ship 'Rajendra', Bombay.
7. Principal Seamen's Welfare Office, Bombay.
8. Directorate Marine Engineering and Training College, Bombay.
9. Lighthouses Lightship Director's Office, Bombay.
10. Freight Investigation Bureau, Gandhidham.
11. Freight Investigation Bureau, Kandla.

12. Kandla Dock Labour Board, Kandla.
13. Office of the Captain Superintendent, Training Ship 'Naulakshi', Naulakshi.
14. Regional Office (Roads Wing), Chandigarh.
15. Office of the Engineer Liaison Officer, (Roads Wing), Jammu.

(F. No. PU/147/80)

V. SANKARALINGAM, Dy. Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली 14 अक्टूबर

(महं एंड सेटलमेंट यूनिट-1)

क्र० प्र० 2968—दिल्ली विकास अधिनियम 1957 (1957 की सं०-61) की धारा 22 की उपधारा (4) की व्यवस्थाओं के अनुसरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नीचे लिखी अनुसूची में उल्लिखित भूमि धागे डाकखाना बनाने हेतु शक व सार विभाग को हस्तान्तरित करने के लिये भूमि एवं विकास कार्यालय निर्माण धोरण/धाराध मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निपटान पर देने हेतु केन्द्रीय सरकार के निपटान पर छोटा हो है :—

अनुसूची

खगमग 1787 बर्ग गज (लगभग 1494 वर्ग मीटर) माप का भूमि खण्ड जो रामा कृष्णा पुरम सैक्टर घाट पर स्थित है, जिसका प्लॉट नं० स्थल 89 है और जो अधिसूचना सं० एस प्रो. 4719 'विनांक' 21-8-75 का प्राथमिक/समस्त भाग है।

उपयुक्त भूमि खण्ड की सोमाएं निम्नलिखित हैं :—

उत्तर में:—	सड़क और पार्क
दक्षिण में:—	सरकारी भूमि
पूर्व में:—	नाला
पश्चिम में:—	सड़क

[स० एस० एच एस 339 (42)/79 एस० प्रो० आई० 1169-71]

बिशन कुमार मल्होत्रा, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Survey and Settlement Unit. I)

S.O. 2968.—In pursuance of the provisions of Sub-section (4) of Section 22 of the Delhi Development Authority Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority has replaced at the disposal of the Central Government the land described in the schedule below for placing it at the disposal of the Land and Development Office, Ministry of Works and Housing, Government of India, New Delhi for further transfer to the Post and Telegraph Department for construction of Post Office.

SCHEDULE

Piece of land measuring about 1787 sq. yds. (about 1494 sq. m.) situated at R. K. Puram, Sector-VIII—bearing Plot No. Site No. 89 partly/full of Notification No. S. O. 4719 Dated 21-8-75.

The above piece of land is bounded as follows :—

North—Road and (Park).
South—Government Land.
East—Nalla
West—Road.

[No. 5&S 33(42)/79/ASO(I)/1169-71]

B. K. MALHOTRA, Secy.

पूति और पुनर्वासि मंत्रालय

(पुनर्वासि विभाग)

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 1980

क्र० आ० 2969.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वासि अधिनियम, 1954 की धारा 34 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, गोविन्द जी० मिश्र, मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त, इसके द्वारा महाराष्ट्र सरकार, राजस्व व वन विभाग की अधिसूचना संख्या ई० बी० पी०-1079/182598 (i)/आर० 9 दिनांक 26-9-1980 और ई० बी० पी०-1079/182598 (ii)/आर० 9 दिनांक 26-9-1980 द्वारा, क्रमशः बन्दोबस्त आयुक्त और अधिरक्षक निष्कास्त सम्पत्ति महाराष्ट्र राज्य, बम्बई के रूप में नियुक्त किए गए श्री बी० पी० पाण्डे/सेलेक्शन ग्रेड उपकलक्टर को उक्त अधिनियम की धारा 23, 24 तथा 28 के अधीन या उसके द्वारा, मुझे प्रदत्त शक्तियाँ सौंपता हूँ। इसके साथ शर्त यह होगी कि महाराष्ट्र राज्य के लिए नियुक्त उक्त बन्दोबस्त आयुक्त, मुद्राबजा पूल की ऐसी सम्पत्तियों, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं हैं, के संबंध में किसी भी ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे।

2. इससे पूति और पुनर्वासि मंत्रालय (पुनर्वासि विभाग) की अधिसूचना संख्या-1 (ii)/वि० स०/77 एस० एस-11 दिनांक 25 जुलाई, 1978 का अधिष्ठापन कर दिया जाता है।

[संख्या-1(11)/वि० स०/77-एस० एस-11]

गोविन्द जी० मिश्र, मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 7th October, 1980

S.O. 2969.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954, I, G. J. Misra, Chief Settlement Commissioner, hereby delegate to Shri B. P. Pande, Selection Grade Deputy Collector, appointed by the Government of Maharashtra under Revenue and Forests Department's Notifications No. EVP-1079/182598(i)/R-9, dated 26-9-80, and EVP-1079/182598(ii)/R-9, dated 26-9-80, as Settlement Commissioner and Custodian of Evacuee Property, Maharashtra State, Bombay, respectively the powers conferred on me by or under Sections 23, 24 and 28 of the said Act, subject to the conditions that the said Settlement Commissioner for the State of Maharashtra shall not exercise any such powers in relation to the compensation pool properties not situated in Maharashtra State.

2. This supersedes Notification No. 1(11)/Spl. Cell/77-SS. II., dated the 25th July, 1978, issued by the Ministry of Supply and Rehabilitation (Department of Rehabilitation), New Delhi.

[No. 1(11)/Spl. Cell/77-SS. II.]

G. J. MISRA, Chief Settlement Commissioner.

भारतीय डाक तार विभाग

(डाक महाअध्यक्ष/महाप्रबंधक का कार्यालय)

शिलोंग, 10 जून, 1980

क्र० आ० 2970.—यतः भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 1 दिसम्बर, 1979 में पृष्ठ 3426 पर प्रकाशित

संचार मंत्रालय (डाक तार बोर्ड) सं० एस० आ० 3901 दिनांक 18 मई, 1976 की भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा केन्द्र सरकार में विभागीय जांच (साक्षियों को उपस्थिति तथा वस्तावेज प्रस्तुतीकरण का प्रवर्तन) अधिनियम 1972 (1972 का 18) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उस सरकार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रत्येक के साथ साथ अधोहस्ताक्षरी को भी विनिश्चित किया है।

और यतः अधोहस्ताक्षरी के यह राय है कि श्री (1) अशित रंजन दे, कैश ओवरसीयर, हिलकांडी, वर्तमान सेंटिंग पोस्टमैन सिलचर हेड-प्रांतीय के विरुद्ध विभागीय जांच के प्रयोजन से (2) श्रीमती रुबी दे पुत्री श्री अशित रंजन दे की, श्रीमती गौरी भट्टाचार्यी, प्रधान अध्यापिका, नेताजी विद्या भवन, बालिका उच्च विद्यालय सिलचर की, साक्षी (साक्षियों के जतोर अथवा वस्तावेज भंगाने के लिये समय किया जाना आवश्यक है।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा (2) श्री आर० भट्टाचार्यी, सहायक निदेशक (सेलस) कार्यालय, निदेशक डाक (विभाग) गौहाटी, रीजन, के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 5 में विनिश्चित शक्तियों का प्रयोग करने के लिये साक्षी की उपस्थिति तथा वस्तावेज प्रस्तुतीकरण का प्रवर्तन (1) श्री अशित रंजन दे की जांच प्राधिकारी प्राधिकृत किया जाता है।

[सं० बी० आई० जी/14/17/79]

जी० बी० एस० राय, डाक महाअध्यक्ष/महाप्रबंधक

INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT

(Office of the Postmaster-General)

Shillong, the 10th June, 1980

S.O. 2970.—Whereas by the notification of the Govt. of India in the Ministry of Communication (Posts and Telegraphs Board) No. S.O. 3901 dated the 18th May, 1976 published in the Gazette of India Part II section 3 Sub-section (ii) dated the 1st December, 1979 at page 3426, the Central Govt. has specified among others, the undersigned to exercise the powers of that Government under Sub-section (i) of Section 4 of the Departmental Enquiries (enforcement of attendance of witnesses and production of documents) Act, 1972 (18 of 1972).

And whereas the undersigned is of opinion that for the purposes of departmental enquiry against Shri Ashit Ranjan Dey, Cash Overseer Hallakandi and now officiating Sorting postman, Silchar H.O., it is necessary to summon as witness and call for Attendance Register and Admission Register along with application for admission of Shrimati Rubi Dey d/o. Shri Ashit Ranjan Dey from Shrimati Gouri Bhattacharjee, Headmistress of Netaji Vidya Bhawan Girls' High School, Silchar.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of section 4 of the said Act, the undersigned hereby authorises Shri R. Bhattacharjee, A.D. (Mails) office of the D.P.S., Gauhati Region, Gauhati, the inquiring authority to exercise the powers specified in section 5 of the said Act in relation to enforcement of attendance of witness and production of documents.

[No. Vig/14/17/79]

G. V. S. Rao, Postmaster-General

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 5th September, 1980

S.O. 2971.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal New Delhi, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Bank of India, and their workmen, which was received by the Central Government on the 28-8-1980.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI.

I.D. No. 105 of 1977

In re :

The General Secretary,

U.P. Bank Workers' Organisation :

2, Navin Market, Parada, Kanpur . . . Petitioner

Versus

The Divisional Manager :

Central Bank of India, Karachi Khana,

Kanpur. . . Respondent.

AWARD

The Central Govt. as appropriate Govt. vide its order No. L-12012/90/74-LR.III dated the 17th February, 1975 referred an Industrial Dispute u/s 10 of the I.D. Act, 1947 to Industrial Tribunal, Kanpur in the following term, .

"Whether the action of the management of the Central Bank of India in denying the promotion and special allowance of Assistant Head cashier to Shri R.S. Kapoor w.e.f. the 9th October, 1973 is justified? If not, to what relief is he entitled?"

2. On receipt of the reference used notices were sent to the parties and the parties filed their respective statements of claim but before written statement could be filed the matter was transferred vide order No. L-12025/22/74/D.II(A) dated 3-6-1976 to Industrial Tribunal, Delhi at the Industrial Tribunal, Delhi after registering the matter issued fresh notices to the parties but before any further action could be taken in the matter the term of Central Industrial Tribunal, Delhi came to an end and in consequence this case was transferred to this Tribunal in May, 1977. Upon receipt of this case it was ordered to be registered and notices were issued to the parties and a written statement was filed by the Bank and replication was filed by the workman and after admission and denial following one issue was framed for trial :

Issue :

As in the order of reference.

3. Thereafter it was found that the order of transfer date May, 1977 was defective and as such a fresh order of transfer was passed in May, 1978 by the appropriate Govt. Thereafter evidence of the parties was recorded and arguments were heard. I have gone through the pleadings of the parties and after giving my considered thought to the matter before me I have come to the following findings upon this issue.

4. The contention of the workman as evidenced by his statement of claim is that he was appointed as Asstt. Cashier at Naya Ganj Branch at Kanpur on 2-1-1946 and that at that time there was a post of Head Cashier, two posts of Asstt. Head Cashier and other posts of Asstt. Cashiers in that Branch and senior most Asstt. Cashier was called upon to officiate as Asstt. Head Cashier but when the post of Asstt. Head Cashier fell vacant on the transfer of Shri R. C. Avasthy it was not filled by the Bank and rather Sri R. S. Kapoor's representation dated 20-10-73 and reminders dated 4-12-73 and 10-12-73 also did not get him any promotion. Thereupon the workman is stated to have approached the ALC and hence this reference.

5. The contention of the Bank inter-alia is that on the transfer of Shri R. S. Avasthy one post of Asstt. Head Cashier was abolished in the Naya Ganj Branch of the Bank and as 827 GT/80—6

such Shri Kapur was not given any officiating chance. Even otherwise in the alternative it is contended by the Bank that Shri R.S. Kapoor was offered the post of Head cashier vide negotiations letter No. DM/staff/41/160 dated 9-5-73 but the said offer was not accepted by the workman and as such the Management vide their letter No. DM/staff/41/2026 dated 27-9-73 debarred the workman from the post of Head Cashier which inter-alia included debarring the workman from officiating chance also and hence it is urged by the Bank that the workman be not entitled to any relief what-so-ever. It may be mentioned here that the fact that the workman had been offered the post of a Head Cashier vide letter dated 9-5-73 and he had refused is not denied by the workman. It is also not denied by the workman that he had been deprived vide letter dated 27-9-73 from the post of Head Cashier. In the face thereof it would be difficult to accept that the workman was entitled to any officiating chance as claimed by him. The evidence of the workman consists of his own statement as W.W. 1 in which he has only reiterated what he has stated in his statement of claim but during cross examination it is admitted by him that no person was appointed to the vacancy arising out of the transfer of Shri Avasthy. It is further stated by him that he could not say if the post had been abolished and therefore no officiating was made as second Asstt. Head Cashier. He has also not been able to deny that this was the reason why had not been promoted. Strangely enough even though admitted in para No. 10 of his statement of claim that he had been deprived from the post of Head Cashier he has denied this fact in his cross examination. The Management in support of its contention has examined M.W. 1, Shri Shradoker, Chief Manager, State Bank of India, Kanpur, M.W. 2, Shri B. N. Chaturvedi, Divisional Manager of the Bank and M.W. 3, Shri K. C. Arora, the Branch Manager, M.W. 1 has proved documents Ex. M/1 to Ex. M/6. M.W. 2 has stated that it was thought necessary to abolish one post of Asstt. Head Cashier for administrative reasons and it was done then Mr. Avasthy was transferred. He has not been challenged on this aspect of the matter during cross examination. M.W. 3 Shri K. C. Arora has stated that to avoid duplication of workman one post of Asstt. Head Cashier was abolished on transfer of Mr. Avasthy. It is also stated by him that Shri R. S. Kapoor, workman was granted an opportunity by way of promotion but he refused to go out of Kanpur and as the post was out of Kanpur he did not afford the opportunity. During cross examination he has stated that the first offer to Mr. Kapoor was made in December, 1969 and thereafter again in May, 1973 but he declined both and this has resulted in his depriving from promotion as Head Cashier. In the face of the statement of M.W. 2 and M.W. 3 read with the admission in para No. 10 of the statement of claim of the workman and Ex. M/5 it is established that the workman had been rightly deprived for promotion to the post of Head Cashier and in accordance with the note to the settlement Ex. M/5 it would follow that the refusal by the workman to accept the post carrying a special allowance resulted in forfeiture of any claim of special allowance of any nature. In view of my discussions above, I hold that the Bank was justified in not offering the post of Asstt. Head Cashier on the transfer of Shri Avasthy.

6. Let us consider the matter from yet another angle. M.W. 2 and M.W. 3 have categorically stated that for administrative reasons one post of Asstt. Head Cashier was abolished in the Naya Ganj Branch of the Bank at Kanpur which fact has not been challenged anywhere. That being the position it would mean that there was no post of Asstt. Head Cashier to which this workman could have promoted after Shri Avasthy was transferred and as such also it cannot be said that the action of the Management of Central Bank of India in denying promotion and special allowance of Asstt. Head Cashier to Shri R. S. Kapoor w.e.f. 9th October, 1973 is not justified.

7. It is urged that no notice u/s 9 of the Act was served before the post was abolished. However the decision not to fill the post does not mean that the post is formally abolished. There is no formal order abolishing the post only it was decided not to fill the post and therefore there was no need to give the notice u/s 9 of the I.D. Act. Even otherwise it cannot be said that abolition of post would attract provisions of Section 9 in the circumstances of this case. It may be mentioned here that it is not urged by the workman that a person junior to him was ever promoted to this post of Asstt. Head Cashier.

8. In view of my discussions above, it is awarded that the action of the Management of Central Bank of India in denying the promotion and special allowance of Asst. Head Cashier to Shri R. S. Kapoor at Naya Ganj Branch of Central Bank of India w.e.f. 9th October, 1973 is justified and that the workman is not entitled to any relief what-so-ever. Parties are however left to bear their own costs, in this matter.

Further Ordered :

That requisite number of copies of this award may be sent to the appropriate Govt. for necessary action at their end.

Dated : the 26th July, 1980

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer
[No. L-12012/90/74-D. II(A)]
S. K. BISWAS, Desk Officer

आरंभ संकलन

प्रारंभ

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 1980

का० प्रा० 2972.—मैसर्स वि स्टेडसमैन लिमिटेड, स्टेडसमैन हाउस, कनाट सर्कस नई दिल्ली के प्रबन्धतंत्र और उनके कर्मचारियों ने, जिनका प्रतिनिधित्व स्टेडसमैन कर्मचारी यूनियन, स्टेडसमैन हाउस, कनाट सर्कस, न दिल्ली ने किया, दिल्ली प्रशासन के सुलह अधिकारी, श्री एस पी० जोशी के समक्ष 3 जनवरी, 1971 को एक समझौता किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इन बातों की व्यवस्था है :

(i) तारीख 3 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित राष्ट्रीय अधिकरण, कलकत्ता के पंचाट को लागू करना

(ii) वर्ष 1970, 1971 और 1972 के लिए बोनस का भुगतान करना और (iii) कर्मचारों के ऐसे वर्गों के लिए वेतनमान आरंभ करना, जिन्हें राष्ट्रीय अधिकरण के पूर्वोक्त पंचाट में स्थान प्राप्त नहीं हुआ है।

और अब कर्मचारों के कतिपय वर्गों के समुचित स्थानान्तरण और सहवर्ती मंहगाई भत्ते की अवधि के संबंध में संदेह उत्पन्न हो गया है और प्रबन्धतंत्र का दावा है कि ये कर्मकार समुचित समूहों/श्रेणियों में रखे गए हैं, जिनके हकदार हैं, जैसा कि उपाबन्ध के स्तंभ 2 में प्रत्येक के सामने दर्शित किया गया है, जबकि यूनियन का यह तर्क है कि ये कर्मकार उपाबन्ध 'क' के स्तंभ 1 में उन कर्मचारों के सामने उल्लिखित समूहों/श्रेणियों में रखे जाने और उसमें यथादर्शित सहवर्ती मंहगाई भत्ते की अवधि के हकदार हैं;

इससे उपाबन्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवादों की राष्ट्रीय अधिकरण को भेजा गया था जिसके पीठासीन अधिकारी न्यायमूर्ति श्री एस० के० मुखर्जी थे जिनका मुख्यालय कलकत्ता में था।

और उपर्युक्त न्यायमूर्ति श्री एस० के० मुखर्जी की सेवा अब उपलब्ध नहीं रही है।

धनः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 7-ख, धारा 33-ख की उपधारा (1) और धारा 36-ख द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक राष्ट्रीय अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी न्यायमूर्ति श्री आर० एन० भट्टाचार्य होंगे, जिनका मुख्यालय कलकत्ता में होगा और उक्त विवाद से संबंध कार्यवाही को न्यायमूर्ति श्री एस० के० मुखर्जी, पीठासीन अधिकारी, राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता से वापस लेती है और उसे न्यायनिर्णयन के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण कलकत्ता को स्थानान्तरित करती है, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री आर० भट्टाचार्य होंगे।

अनुसूची

(i) क्या मैसर्स वि स्टेडसमैन लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र और स्टेडसमैन कर्मचारी यूनियन द्वारा उठाए गए उपाबन्ध 'क' में उल्लिखित वर्गों को ध्यान में रखते हुए उसमें विनिर्दिष्ट कर्मकारों के पंचाट और सुलह अधिकारी, श्री एस० पी० जोशी के समक्ष 3 जनवरी 1971 को हुए समझौते के अनुसार समुचित समूहों/श्रेणियों में रखे गए हैं, और यदि नहीं, तो ये कर्मकार कितने समूहों/श्रेणियों में रखे जाने चाहिए और किस तारीख से ?

(ii) क्या सहवर्ती मंहगाई भत्ता, जो वर्तमान में दिया जा रहा है, ऊपर विनिर्दिष्ट पंचाट और समझौते के अनुसार है, यदि नहीं तो क्या किसी उपाबन्ध की आवश्यकता है

[सं० ए०-51011/33/74-आई० एंड ई० (आई०)]

आर० पी० नरुणा, प्रवर सचिव

उपाबन्ध 'क'

स्टेडसमैन कर्मचारी यूनियन का तर्क स्टेडसमैन के नियोजकों का तर्क 1 (क) दोषपूर्ण रूप से फिट करना—

तीन यांत्रिक सर्वश्री भगवान ये मशीनमैन नौकरी विभाग में काम, नामक चंद और किशन को ओडिल यंत्र का प्रचालन कर रहे थे। 190-8-238-15-328- द० रो०-20-388-६०, समूह-III (कारखाना) में समूह-4 (कारखाना) में समूह-4 के वेतनमान के स्थान पर 175-7-217-12-301-६० रो० 20-341 ६० के वेतनमान में गलत ढंग से फिट किया गया।

1-1-1971 से, गलत फिट किए जाने की बात को सुधारा गया और उन्हें समूह II (कारखाना) 210-8-258-15-348 द० रो०-20-408 ६० में रखा गया। 1-7-67 से 30-12-70 तक कर्मचारों को समूह III (कारखाना) में फिट किया जाना चाहिए और तदनुसार बकाया संवत् की जानी चाहिए।

(ii) ज्येष्ठतम होने पर भी श्री नेकराम को प्रोसेस विभाग में नेकराम, मशीनमैन चालक को नियोजित किया गया है, न कि समूह II (कारखाना) में श्रेणी उन्नयन नहीं किया गया।

श्री नेकराम को प्रोसेस विभाग में नियोजित किया गया है, न कि वाणिज्यिक मूद्रण विभाग में मशीनमैन के रूप में फिट किए जाने के समय उसके वास्तविक कार्य को ध्यान में रखा गया था।

(ख) आठ कर्मकार सर्वश्री ई० दत्त, एन० आर० बरुआ, एन० के० बरुआ, बाबूबा, एस० बी०, गुरुआ, के० ए० बरुआ, बी० के० बरुआ और बी० सी० डे को जिनको 1-7-1967 से स्टीरियो कास्टर के कृत्यों का निर्वहन किया और जो समूह II (कारखाना) में, 210-8-258-15-343-६० रो० 20-408

इन आठ कर्मकारों का पदावधि पंचाट के अधीन समूह III (कारखाना) के अंतर्गत आता है। काम की प्रकृति स्टीरियो कास्टर की है, स्टीरियो कास्टर का कार्य अनुभाग का है।

६० के वेतनमान में फिट किए जाने के हकदार हैं, दोषपूर्ण रूप से समूह III (कारखाना) में 190-388 ६० के वेतनमान में फिट किया गया है।

प्रोसेस विभाग

(ग) श्री पी० एन० खन्ना उत्कीर्ण हाफटोन निक्षारक को 210-408 ६० (समूह II कारखाना) के स्थान पर 110-160 ६० (समूह IV कारखाना) वेतनमान दिया गया है। उन्हें 1-7-1967 से यह वेतनमान मिलना चाहिए।

(घ) प्रोसेस विभाग के श्री सतपाल को जो दोषपूर्ण रूप से समूह II (कारखाना) में फिट किए गए हैं समूह (कारखाना) में 250-670 ६० के वेतनमान में 1-7-67 से फिट किया जाना चाहिए।

(ङ) श्री दयाचंद जैन और श्री पी० एन० खन्ना दोनों 'क' श्रेणी के टंकक हैं। 'क' श्रेणी के लिपिक और 'क' श्रेणी के टंकक को समूह IV (प्रशासन) (वेतनमान 190-374 ६०) के स्थान पर 1-7-67 से समूह V (प्रशासन) में जिसका वेतनमान 250-660 ६० है, फिट किया जाना चाहिए। उन्हें ठीक जगह फिट किया जाना चाहिए और सही वेतन दिया जाना चाहिए।

(च) श्री राम फल और श्री इमैनमुल सुखलाल जिल्दसाजी को समूह VII (प्रशासन) के स्थान पर जिल्दसाजी के समूह (कारखाना) V में 150-292 ६० के वेतनमान में 1-7-67 से फिट किया जाना चाहिए और बकाया का संदाय किया जाना चाहिए।

(छ) श्री राम समुज सिंह को समूह VI (क) (190-374) की उसकी सही श्रेणी के स्थान पर समूह VIII (क) (110-160 ६०) में दोषपूर्ण रूप से फिट किया गया है।

(ज) सभी लेखा-लिपिकों को 196-374 ६० समूह VII (क) के स्थान पर 1967 से भूतलभी प्रभाव से 250-600 ६० समूह (क) का वेतन दिया जाना चाहिए।

श्री खन्ना का प्रोसेस विभाग में पदनाम मददगार के रूप में पदामिहित है। रजिस्टर पर 9 हाफ टोन निक्षारकों के नाम दर्ज हैं। वह केवल मात्र उनकी सहायता करता है।

श्री सतपाल को केमरा प्रचालक के रूप में नियोजित किया गया है और उन्हें समूह II (कारखाना) के अधीन ठीक ही फिट किया गया है। फोटो ट्रान्स्फरेंसी का काम नग्न है और उसके लिए पूर्ण कालिक आदमी रखने की आवश्यकता नहीं है।

श्री दयाचंद और श्री पी० एन० खन्ना समूह VI (क) में टंकक के रूप में ठीक ही फिट किए गए हैं। उनका कार्य मात्र टंकण है और उसमें किसी भी प्रकार का आधुनिकीय कार्य शामिल नहीं है। नमस्ती के साथ प्राप्त पत्राट के प्रधान उचित वर्गीकरण किया गया है।

श्री राम फल और इमैनमुल सुखलाल दफ्तरी के रूप में नियोजित हैं और उसी रूप में पदामिहित हैं। अनुभाग में कागजपट्टों या प्रलेखों की समुचित जिल्दसाजी की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री राम समुज सिंह प्रेषण लिपिक के साथ लगा अपरासी है। क्रेकिंग यंत्र इस लिए लगाया गया है कि प्रेषण लिपिक डाक का द्रुत गति से निपटारा कर सके। वह यंत्र का प्रचालन नहीं करता है। उसका प्रचालक तो लिपिक ही है। लेखा लिपिकों को कम्पनी के वेतनमानों के अधीन तीन समूहों (क, ख और ग) में विभाजित किया गया था। ख और ग समूहों के लिपिकों को कनिष्ठ लिपिक माना गया और उन्हें समूह 4(क) के अधीन फिट किया गया और क समूह के लिपिकों को कुशल माना गया और उन्हें समूह (क) के अधीन रखा गया।

(झ) दिल्ली के समाचार/विज्ञापन अनुभागों के प्रूफ शोधक पंचाट के गलत क्रियान्वयन से पीड़ित हो गए। दिल्ली में जाब अनुभाग के प्रूफ शोधक और कलकत्ता के जाब और विज्ञापन रीडर आरंभ में 1-7-67 को समूह (iii) कारखाना में फिट किए गए थे और 1-1-71 को समझौते के अनुसार पुनः ठीक ढंग से रख दिए गए थे। किन्तु दिल्ली के समाचार/विज्ञापन अनुभाग के प्रूफ शोधकों को इस फायदे से हंकार कर दिया गया और इस प्रकार उन्हें मजदूरी में हानि हुई।

II सेवा वेतन वृद्धि

कुछ कर्मकार/प्रोसेस कर्मचारि-वृन्द और लिपिकों को अब तक उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी गई है। पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर वे एक सेवा वेतन-वृद्धि के हकदार हैं और 10 वर्ष या इससे अधिक की सेवा पर दो वेतन वृद्धियों के हकदार हैं।

(क) लिपिक—जो वयों से समरूप कार्य करते रहे हैं, उन्हें 'क' 'ख' और 'ग' श्रेणी लिपिकों के रूप में कम्पनी की कृत्रिम नाम पद्धति में उनकी सेवा के असाम्य आधार पर वेतन-वृद्धियां नहीं दी गईं। लिपिकों की सेवा को सेवा वेतन-वृद्धियां देने के लिए विचार-गत किया जाना चाहिए, न कि कम्पनी की नाम पद्धति 'क' 'ख' और 'ग' में उनकी सेवाओं को।

(ख) प्रोसेस कर्मचारिवृन्द

इसी प्रकार, प्रोसेस विभाग के कई कर्मकारों को सेवा वेतन-वृद्धियां देने से हंकार किया गया है। साइन निरक्षक और हाफ टोन निक्षारक के रूप में उनके काम की प्रकृति/टिंड समान होते हुए भी, कम्पनी ने 'क' श्रेणी कर्मकार, 'ख' श्रेणी कर्मकार और 'ग' श्रेणी कर्मकार के रूप में नामपद्धति सलग्न कर दी है।

(ग) श्री रतन लाल और श्री पुरी से प्रबंधक वर्ग ने ए० पी० एल० प्रचालक और कनिष्ठ/करेक्टर दोनों के कर्तव्यों के पालन की अपेक्षा की थी। चूंकि उनकी सेवा केवल ए० पी० एल० प्रचालक के रूप में ही हिसाब से ली गई, अतः उन्हें सेवा वेतन-वृद्धियां देने से हंकार किया गया है। उनकी कुल सेवा को हिसाब में लिया जाए।

प्रूफ-शोधक समझौते के अन्तर्गत विनिश्चित रूप से उपाबन्ध 'ख' खण्ड (2) के अधीन आ गए और यह सहमति हुई थी कि उन्हें पंचाट के समूह 5 (कारखाना) में रखा जाएगा। पूर्विक फिटमैन पर न तो विचार विमर्श किया गया था और न ही समझौते के अधीन यह आता है।

सेवा वेतन-वृद्धि के लिए लेखों में ली जाने वाली सेवा अवधि उसी प्रवर्ग में, जिसमें कर्मकार फिट किए जाने के समय नियोजित किया गया था, कार्य पर आधारित है।

प्रत्येक कर्मचारी को सभी सेवा वेतन-वृद्धियां दी गई हैं।

ORDER

New Delhi, the 13th October, 1980

(घ) श्री शिब बरन मिहिर को इसलिए सेवा वेतन-वृद्धि से इंकार किया गया है क्योंकि उसे हेडमैन के रूप में परामर्शित किया गया है, यद्यपि उसे समूह III (कारखाना) में फिट किया गया है।

इसी प्रकार, श्री स्वल्पा का पदनाम हेड-स्वीपर रखा गया है जिसका वेतन उसके अधीन काम कर रहे स्वीपरों से कम है।

(ख) वक्षता रोधः—समझौते के क्रियान्वयन के प्रथम वर्ष में वक्षता रोध लागू नहीं किया जाना चाहिए। विस्ली कार्यालय में दो कर्मकार श्री एन्थोनी जेकब, मेकनप सैन पर्यवेक्षक और प्रोसेस विभाग के श्री सरत राम को 1971 में वक्षता रोधक के आधार पर, वृद्धात्मक रूप से वेतन-वृद्धियां देने से इंकार कर दिया गया।

वक्षता रोध अधिरोपित करने के लिए प्रबंधक वर्ग को, पंचाट के अनुसार, प्रक्रिया अपनानी चाहिए, किन्तु इसमें उसका अनुसरण नहीं किया गया है।

श्री जेकब और सरत राम को वेतन-वृद्धियां देने पर विचार किया गया था। विभागीय रिपोर्टें यह बतित करती हैं कि वे उच्चतर वेतनमान में दक्ष कर्तव्यों पर लिए जाने के योग्य नहीं समझे गए।

यदि यह मान भी लिया जाए कि वक्षता रोध को प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना लागू किया गया है तो भी समझौते या पंचाट के किसी उल्लंघन का अभियोजन नहीं किया जा सकता।

III सहवर्ती मंहगाई भत्ताः—

मंहगाई भत्ते पर प्रति वर्ष पुनरीक्षा होनी चाहिए। जनवरी, 1971 में प्रबंधक वर्ग ने 10 प्वाइंट का मंहगाई भत्ता संवत्त किया जबकि अंतर 15 प्वाइंट का था और कर्मकारों को शेष पाँच प्वाइंट के लाभ से वंचित रखा गया।

मंहगाई भत्ते को पूर्ववर्ती 12 मास के औसत के आधार पर प्रत्येक वर्ष के प्रथम दिन पर आधारित, श्रमिक वर्ग के वर्ष 1965 के उपभोक्ता कीमत सूचकांक के अखिल भारतीय औसत के साथ सहमत किया जाता होता है, यदि किसी विशिष्ट वर्ष के औसत में पूर्ववर्ती वर्ष से 10 प्वाइंट या अधिक की उपरिमुखी या अधोमुखी भिन्नता होती है : निम्नलिखित वर्षों के लिए औसत

1965—166
1966—184
1967—209
1968—215
1969—213
1970—224

प्रथम पुनरीक्षण 1968 में हुआ था। 19 में सूचकांक 1967 की तुलना में 6 प्वाइंट बढ़ा, इसलिए पुनरीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं थी ; 1971 में पुनरीक्षण किया गया।

S.O. 2972.—Whereas the management of Messers The Statesman Limited, Statesman House, Connaught Circus, New Delhi, and its workmen represented by the Statesman Employees' Union, Statesman House, Connaught Circus, New Delhi, had entered into a settlement before the Conciliation Officer, Delhi Administration, Shri S. P. Joshi, on 8th January, 1971 which inter-alia provided for : (i) implementation of the award of the National Tribunal, Calcutta Published in the Gazette of India Extraordinary (Part II-Section 3-Sub-Section (ii) dated the 3rd August, 1970), (ii) payment of bonus for the year 1970, 1971 and 1972 and (iii) introduction of scales of pay for such categories of workmen which do not find place in the aforesaid award of the National Tribunal.

And, whereas, a doubt has now arisen with regard to the proper placement of certain categories of workmen and payment of linkage Dearness Allowance, the management maintaining that these workmen have been placed in proper groups/grades to which they are entitled as shown against each in column 2 of Annexure 'A', the Union, however, contending that these workmen are entitled to be placed in groups/grades mentioned against these workmen in column 1 of Annexure 'A' and paid linkage Dearness Allowance as shown therein ;

Whereas the industrial disputes specified in the Schedule hereto annexed were referred to the National Industrial Tribunal of which Justice Shri S. K. Mukherjee was the Presiding Officer with headquarters at Calcutta,

And whereas the services of the said Justice Shri S. K. Mukherjee are no longer available.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7B, Sub-Section (1) of section 33B and section 36A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes a National Industrial Tribunal of which Justice Shri R. N. Bhattacharya shall be the Presiding Officer with headquarters at Calcutta and withdraws the proceedings in relation to the said disputes from Justice Shri S. K. Mukherjee, Presiding Officer, National Industrial Tribunal, Calcutta, and transfers the same for adjudication to the National Industrial Tribunal, Calcutta, presided over by Justice Shri R. N. Bhattacharya.

SCHEDULE

(i) whether in view of the contention raised by the management of Messers The Statesman Limited and the Statesman Employees' Union as stated in Annexure 'A', the workmen detailed therein have been placed in proper groups/grades in pursuance of the award of the National Industrial Tribunal, referred to in para 1 above and settlement dated 8th January, 1971, before the Conciliation Officer, Shri S. P. Joshi, and if not, in which groups/grades these workmen should be placed and from which date ?

(ii) whether the linkage Dearness Allowance which is being paid at present is in accordance with the award and settlement referred to above, and if not whether any modification is required ?

[No. L-51011/33/74-I&E(I)]
R. P. NARULA, Under Secy.

ANNEXURE 'A'

Statesman Employees Union's Contention	Statesman Employers' Contention
--	---------------------------------

1 (A) Wrongful fitment

Three mechanics Sarva Shri Bhaagwan Das, Nanak Chand and Kishan were wrongly fitted in the pay scale of Rs. 175-7-217-12-	These Machinememen were operating Threadle Machines in Job Department. These mechanics are grouped in Group IV (Factory) under
---	--

301-EB-20-341 awarded for group IV (Factory) instead of pay scale of Rs. 190-8-238-15-328-EB-20-388 group III (Factory).

From 1-1-1971 misfitment was rectified and they were placed in group II (Factory) Rs. 210-8-258-15-348-EB-20-408. From 1-7-67 to 30-12-70 the workmen should be fitted in Group III (Factory) and paid arrears accordingly.

(ii) Shri Nek Ram, Machine-man has not been upgraded to group II (Factory) being senior most.

(B) Eight workmen Sarvashri E. Dutt, N.R. Barua, N.K. Barua, Babu Khan, S.B. Barua, K.A. Walker, B.K. Barua & B.C. Dey who discharged functions of Stereo Caster and are entitled to be fitted in Group II (Factory) in the Pay scale of Rs. 210-8-258-15-348-EB-20-408 w.e.f. 1-7-67 have been wrongly fitted in Group III (Factory) in the pay scale of Rs. 190-388.

Process Deptt.

(C) Shri P.N. Khanna engraver/half tone etcher has been given pay scale Rs. 110-160 (Group IV Factory) instead of Rs. 210-408 (Group II Factory). Should be given scale w.e.f. 1-7-1967.

(D) Shri Sat Pal of the Process Department should be fitted in Group I (Factory) in the scale of Rs. 250-670 w.e.f. 1-7-67 who is wrongly fitted in Group II (Factory).

(E) Shri Daya Chand Jam and Shri P.N. Khanna both are 'A' grade typist. 'A' grade clerk and 'A' grade typist should be fitted in Group V (Adm.) carrying pay scale of Rs. 250-660 instead of Group VI (Adm.) (Pay scale Rs.

the award.

Shri Nek Ram is employed in the Process Department and not as a Machine-man in the Commercial Printing Department. At the time of fitment, his actual work was taken into account.

The designation of these eight workmen fall within Group III (Factory) under the Award. Nature of work is that of Stereo Blockmen, work of Stereo Caster is performed by Headmen in the section.

Mr. Khanna is designated as helper in the Process Deptt. 9 Half Tone Etchers are on roll. He only helps them.

Shri Sat Pal is employed as a Camera Operator, who is given Correct fitment under Group II (Factory). Work of photo transparency is of negligible order and a whole-time man is not required.

Shri Daya Chand & Shri P.N. Khanna have been correctly fitted as typist in Group VI(A). Their work is of typing only and does not involve any element of stenography. Proper classification has been made under the Award received with

190-374) w.e.f. 1-7-67. They should be correctly fitted and paid.

(F) Shri Ram Phael and Shri Emanuel Sukhlal-Binders should be fitted in Binders Grade of Factory V in pay scale Rs. 150-297 instead of Group VII (Adm.) w.e.f. 1-7-67 and paid arrears.

G) Shri Ram Samuj Singh is wrongly fitted in Group VIII (A) (Rs. 110-5-160) instead of his rightful grade of Group VI (A) (Rs. 190-374).

(H) All accounts clerks should be given the pay scale of Rs. 250-660 Group V (A) instead of Rs. 190-374 Group VII (i) with retrospective effect from 1967.

(I) Proof Readers of the News/Advt. Section of D.Lhi are victims of mis-implementation of Award. Job Section Proof Readers in Delhi and Job and Advertisement readers in Calcutta were initially fitted in Group (III) Factory on 1-7-67 and refitted accordingly to settlement on 1-1-71 but Proof Readers of News/Advt. Section of Delhi have been denied the benefit and thus have suffered loss in wages.

settlement.

Shri Ram Phael and Shri Emanuel Sukhlal are employed as Daftries and designated as such. There is no arrangement for proper binding of papers or documents set up in the section.

Shri Ram Samuj Singh is a peon attached to the despatch clerk. The franking machine has been placed to help the Despatch Clerk for quick disposal of dak. He is not operating the machine. The clerk is operator of it.

Accounts clerks were divided into three groups under the Company's pay scale (A, B & C). Clerks of B & C groups were considered junior clerks and were given fitment under Group VI (A) and clerks of A scale were considered skilled and placed under Group V

Proof Readers were covered in the settlement specifically under Annexure 'B' Clause 2 and it was agreed that they would be placed in Group V (Factory) of the Award. Prior fitment was neither discussed nor covered under the settlement.

II. Service Increment:

Some workers Process Staff and Clerks have not been granted their annual increment so far. They are entitled to one service increment for 5 years completed service and two increments for 10 years of service and above.

(a) Clerks-Have been performing similar duties for years have been denied increments on the untenable ground of their service in the Company's artificial

The service period to be taken into account for service increment is based upon the work in the same category in which the workman was employed at the time of fitment.

Correct service increment have been given to each of the employees.

nomenclatures as 'A', 'B' and 'C' grade clerks. The service of the clerks should be taken for giving service increments and not their services in company's nomenclature 'A', 'B' and 'C'.

(b) *Process Staff*—Similarly several workmen of the Process Department have been denied service increments. Their nature of duties/trade such as Line Etcher and Half tone etcher being the same company had appended its nomenclature such as 'A' grade worker 'B' grade worker and 'C' grade worker.

(c) Shri Rattan Lal and Shri Puri were required by the management to perform the duties of both A.P.I. Operator and Junior Corrector. They have been denied service increments since their service as A.P.I. Operator only was taken into account. Their total service should be taken into account.

(d) Shri Shivan Missir has been denied his service increment because he has been designated Headman though fitted in Group III (Factory).

Similarly Shri Swaroopa has been designated as Head Sweeper who draws less than sweepers under him.

(B) Efficiency Bar

E.B. should not be applied in the first year of the implementation of the Agreement. In Delhi Office the Two workmen, Mr. Anthony Jacob, Make up man Supervisor and Shri Bharat Ram of the process Department have been vindictively singled out for the denial of increments in 1971 on grounds of E.B.

The procedure should be adopted by the management for imposition of E.B. according to award, but the same has not been followed.

Mr. Jacob & Bharat Ram were considered for increment. Departmental reports showed they were not considered fit for taking on efficient duties in the higher scale. Even if it is held that the E.B. has been applied without observing the procedure no violation of the Agreement or the award can be alleged.

III. Linkage D.A.

The D.A. should be revised every year. In January, 1971 management paid dearness allowance of 10 points when the difference was 15 points and deprived workers benefit of rest 5 points.

D.A. is to be linked up with All India Average for Consumer Price Index Number for the working class for the year 1965 based on 1st of each year on the basis of previous 12 months average; if the average of any particular year differs by 10 points or more upward or down ward of the previous year.

Average for 1965—166
1966—184
1967—209
1968—215
1969—213
1970—224

The first revision took place in 1968. In 1969 index number rose by 6 points compared to 1967, therefore; revision was necessary; in 1971 revision was given effect.

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 1980

का० प्रा० 2973.—मैसर्स सेशागार्ह पेपर एण्ड बोर्ड्स लि०, पल्लापालायम, कावेरी आर० एस० पी० ओ० इरीड, तमिलनाडु (जिसे इससे इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी अधिव्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, कोई पुष्क अभिदाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप में सम्बन्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) अधीन उन्हें अनुशेष है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपा बद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 1 अप्रैल, 1978 से 31 मार्च 1982 तक उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेगित अधिव्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा, ऐसे लेखा रखेगा और निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निविष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास को समाप्ति से 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन निविष्ट करें।

3. समूह बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुत नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित समूह बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की एक प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले से सदस्य है, उक्त स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, समूह बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वास्तव आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्न करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक, समूह बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए समूह बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक शान्कूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुमोदित हैं।

7. समूह बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवत्न रकम उस रकम से कम है जो उस कर्मचारी की वंशा में देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशनी को प्रतिकूल के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सदाय करेगा।

8. समूह बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति युक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस समूह बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द कर दी जाएगी।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें प्रीमियम का सदाय करने में असमर्थ रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द कर दी जाएगी।

11. यदि नियोजक, प्रीमियम के सदाय, प्रादि में कोई व्यतिक्रम करता है तो, उन मूल सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों के, जो वह छूट न दी जाने की वंशा में उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक वंशा में भारतीय जीवन निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

व्याख्यात्मक स्थापन

इस मामले में पूर्णतः प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है, क्योंकि छूट के लिए प्राप्त आवश्यक पत्र की कार्यवाही पर समय लगा। तथापि यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्ववर्ती प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[संख्या एम०-35014/107/80-पी० एफ-II]

New Delhi, the 14th October, 1980

S.O. 2973.—Whereas Messrs Seshasayee Paper and Boards Limited, Pallipalayam Cauvery, RSPO, Erode, Tamil Nadu, (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts with effect from 1st April, 1978 and upto 31st March, 1982, the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India already adopted by the establishment, or the benefits to the em-

employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium etc., the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, will be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S-35014(107)/80-P.F. II.]

क.० आ० 2974.—मैसर्स दि भारत विजय मिल्स लिमिटेड, कलोल गुजरात (जिसे हमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे हमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम, कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, कोई पृथक् अधिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप से सम्बन्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे हमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभूत हैं।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपावृद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 1 मार्च, 1980 से 28 फरवरी, 1982 तक उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा, ऐसे लेखा रखेगा और निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निश्चित करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभागों का प्रत्येक मास की समाप्ति से 15 दिन के भीतर संदाय करेगा, जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन निश्चित करे।

3. समूह बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभागों का संदाय याचि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुत नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित समूह बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की एक प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की

भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो तीन री भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किया स्थापन की भविष्य निधि का पहले से सदस्य है, उक्त स्थापन में निर्गोष्ठित किया जाता है तो, नियोजक, समूह बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक, समूह बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों का उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने का व्यवस्था करेगा जिसे कि कर्मचारियों के लिए समूह बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभूत हैं।

7. समूह बीमा स्कीम में किसी बात के होने हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदाय रकम उस रकम से कम है तो उस कर्मचारी की वशा में देय होगी जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता था, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/ नाम निर्देशकों को प्रत्येक के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. समूह बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना व्यक्तिगत स्वप्न करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस समूह बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द कर दी जायगी।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियम तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में अमफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द कर दी जायगी।

11. यदि नियोजक, प्रीमियम के संदाय आदि में कोई व्यतिक्रम करता है तो, उन मूल समस्याओं के नाम निर्देशनियों या विधिक वारिसों के, जो वह छूट न दी जाने की वशा में उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन होने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, उसके हकदार नाम निर्देशनियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

व्याख्यात्मक भाषण

इस मामले में पूर्वपेशी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है, क्योंकि छूट के लिए प्राप्त आवेदन पत्र की फररार्ड पर समय लगा। तथापि यह प्रामाणित किया जाता है कि पूर्वपेशी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[संख्या एम० 35014/105/80-पी०एफ०2]

S.O. 2974.—Whereas Messers The Bharat Vijay Mills Limited, Kalol Gujarat (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-sec.

tion (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Scheduled annexed hereto, the Central Government hereby exempts with effect from 1st March, 1980 and upto 28th February, 1982 the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features, thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding any thing contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, the exemption shall be liable to be cancelled.

Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium etc., the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, will be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S-35014(105)/80-PF. II]

का० प्रा० 2975 --मैसर्स देवास टेक्सटाइल मिल्स (प्राइवेट)

लिमिटेड देवास, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी कल्याण निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, कोई पृथक् अधिदाय या प्रीमियम का भुगतान किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निधि से सम्बद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभूत है;

अतः, अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उदात्त अनुसूची में शिर्नामिक अर्थात् के अधीन रहने हुए उक्त स्थापन को, 1 मई, 1978 से 30 अप्रैल, 1981 तक उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रयत्न से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संक्षेप में नियोजक प्रादेशिक कल्याण निधि प्रायुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा, ऐसे लेखा रखेगा और निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निरीक्षण करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रसारों का प्रत्येक माम की समाप्ति से 15 दिन के भीतर भुगतान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खण्ड (क) के अधीन निरीक्षण करें।

3. समूह बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके सम्बन्धित लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवय लेखाओं का अनुरण, निरीक्षण प्रसारों का संवय प्राप्ति भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित समूह बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की एक प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

6. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पत्रने से सबस्य है, उक्त स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, समूह बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी भावन आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक, समूह बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सम्बन्धित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए समूह बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उस फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुमोदित हैं।

7. समूह बीमा स्कीम में किसी बात के होने हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदय रकम उस रकम से कम है जो उस कर्मचारी की वंश में देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विभिन्न वारिस/नामनिर्देशनी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. समूह बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, माय प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का अधिकार प्रदान करेगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा नियम की उस समूह बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पत्रने अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द कर दी जाएगी।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द कर दी जाएगी।

11. यदि नियोजक, प्रीमियम के संदाय, आदि में कोई व्यतिकर करता है तो, उन मूल सदस्यों के नाम निर्देशनियों या विधिक वारिसों के, जो वह छूट न दी जाने की वंश में उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, कोसा फायदों के संदाय का उमरदायिष्ठ नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशनियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक वंश में भारतीय जीवन बीमा नियम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के तत्पश्चात् के भीतर सुनिश्चित करेगा।

व्यावसायिक स्थापन

इन मामलों में पूर्ववर्ती प्रभाव से छूट देना आवश्यक हो गई है क्योंकि छूट के लिये प्राप्त आवेदन-पत्र का कार्रवाई पर समय लगा। तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्ववर्ती प्रभाव से छूट देना किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० एम०-35014/95/80-वी०एफ० 2]

S.O. 2975.—Whereas Messrs Dewas Textiles Mills (Private) Limited, Dewas, (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making

any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Scheduled annexed hereto, the Central Government hereby exempts with effect from 1st May, 1978 and upto 30th April, 1981 the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium etc., the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of deceased members, who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, will be that of the employer.

12 Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

Explanatory Memorandum

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application or exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S. 35014(95)/80-PF. II]

कां०आ० 2976—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स निर्मला इस्टेट, पोस्ट बॉक्स नं० 31, सिहापुर, दक्षिण कोर्ग, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारों भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 30 अप्रैल, 1979 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एम-35019/42/80-पी० एफ-2]

S.O. 2976.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Nirmala state, Post Box No. 31, Siddapur, South Coorg, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of April, 1979.

[No. S. 35019(42)/80-PF. II]

कां०आ० 2977—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हाटल प्रान्ति, बैंक स्ट्रीट हैदराबाद नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारों भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 नवम्बर, 1979 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एम-35019(41)/80-पी० एफ-2]

S.O. 2977.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Hotel Pranti, Bank Street, Hyderabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1979.

[No. S. 35019(41)/80-PF. II]

कां०आ० 2978—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मौलिस एडवर्टाइजिंग सर्विस (प्राइवेट) लिमिटेड, 42, व्हाइट्स रोड, मद्रास 14, जिसके अन्तर्गत 6, ट्राफोर्ड हाउस, फ्रेस्कॉट रोड, फोर्ट मुम्बई, स्थित उसकी शाखा भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारों भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 मार्च 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एम-35019/39/80-पी० एफ-2]

S.O. 2978.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Moulis Advertising Service (Private) Limited, 42, Whites Road, Madras-14 including its branch at 6, Trafford House, Frescot Road, Fort, Bombay, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March, 1978.

[No. S. 35019(39)/80-PF. II]

कां०आ० 2979—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स भार के एस पेज डेकोरेशंस (प्राइवेट) लिमिटेड, 15, पुष्पा विहार नं० 3, गीतरा पत्थर, कोलाबा इलाका घर के सामने, कोलाबा मुम्बई 5, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारों भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1979 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एम-35018/150/79-पी० एफ-2]

S.O. 2979.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs RKS Page Decorations (Private) Limited, 15, Pushpa Vihar No. 3, 3rd Floor, Opposite Colaba Post Office, Colaba, Bombay-5, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1979.

[No. S. 35018(150)/79-PF. II]

कां०आ० 2980—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स चित्रलेखा फिल्म कोप्यारेटिंग लिमिटेड, एन० 17, जिसके अन्तर्गत कालीकट स्थित उनका प्रादेशिक कार्यालय भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर

सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ;

यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 1979 को प्रदत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं. एस-35019(291)/79-पी. एफ.-II]

S.O. 2980.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Chithralekha Film Cooperative Limited, Akkulam, Trivandrum-17, including its Regional Office at Calicut have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1979.

[No. S. 35019(291)/79-PF. II]

कां. सं. 2981.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स स्टील इंडस्ट्रियल्स केरल लिमिटेड (केरल सरकार का उपक्रम) "श्री हरी", टी. सी. नं. 9/1720, त्रिवेन्द्रम 10, जिसके अंतर्गत (1) त्रिचुर और (2) शेरथाल, स्थित उसकी शाखाएँ हैं, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 फरवरी, 1979 को प्रदत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं. एस-35019/183/79-पी. एफ.-2]

ए. पूनन, उप सचिव

S.O. 2981.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Steel Industries Kerala Limited (A Government of Kerala undertaking) "Sri Hari", T. C. No. 9/1720, Trivandrum-10 including its branches at (1) Trichur and (2) Sherthalay, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of February, 1979.

[No. F. 35019(183)/79-PF. II]

A. POONEN, Dy. Secy.

S.O. 2982.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of United Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th October, 1980.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

Reference No. 87 of 1978

PARTIES :

Employers in relation to the management of United Bank of India

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

On behalf of Employers.—Mr. Dipak Dey, Advocate.

On behalf of Workmen.—Mr. S. Sen Gupta, Secretary, Assam State Committee, United Bank of India Employees Association.

STATE : Assam

INDUSTRY : Banking.

AWARD

This reference under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 was referred to this Tribunal for adjudication by the Central Government vide Order No. L-12011/16/77-D.I.A. dated 27/30th October, 1978. The dispute referred to in the Schedule to the Order of Reference reads :

"Whether he proposed action of the management of United Bank of India in discontinuing payment of Special house rent allowance to their workmen employed in North Eastern Region including Assam w.e.f. 1-11-1976 is legal and justified ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?"

2. When the matter is taken up, I find joint petition of compromise filed by both the parties, namely the management of United Bank of India and Assam State Committee of United Bank of India Employees Association, Gauhati. I have heard the parties and I have gone through the contents of the petition as well as Annexures thereto of which Annexure "A" is a copy of memorandum of settlement dated 21st April, 1980 between the Indian Banks Association and All India Bank Employees Association and National Confederation of Bank Employees. The petition is signed by the Secretary of the State Committee of the Union and also by the constituted attorney, namely the Assistant General Manager, Personnel Department for and on behalf of United Bank of India. It is prayed by both the parties that an award may be passed in terms of the relevant portion of the Annexure "A" particularly in terms of Assam allowance mentioned in the said Annexure "A", the memorandum of settlement dated 21st April, 1980. It is stated that the workmen according to the terms of compromise are entitled to the allowance as mentioned under the heading "Assam Allowance".

3. As prayed for, the parties will get an award and the petition of compromise with Annexure "A" alone attached thereto shall form part of the award. It appears that Annexure B to the petition contains the same terms regarding Assam allowance. Therefore it is needless to mention Annexure B in the award. Mr. Sengupta for the Union and Mr. Dipak Dey, learned Advocate for the Bank also submit that Annexure "B" to the petition need not be made part of the award.

4. I find that the Secretary, Mr. Sen Gupta has signed on behalf of the Union and his presence today is essential. Therefore I direct that the Bank shall allow special leave to Mr. Sen Gupta with pay for attending this tribunal today. I understand that he will be staying here for to-morrow in connexion with other matters and therefore the question of leave for return journey does not arise in my view.

Thus I pass the award.

Dated, Calcutta,

The 23rd September, 1980.

R. BHATTACHARYA, Presiding Officer.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL
GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

Reference No. 87 of 1978

Employers in relation to the Management of United Bank
of IndiaVs.
their workmenThe humble joint petition of the Management and Union,
the petitioners above named—

Most respectfully sheweth—

1. Your petitioners state and contend that the hearing of
the above matter was held at Gauhati on September 10, 1979.2. Your petitioners further state and contend that the dis-
pute with regard to the Assam Allowance has been amicably
settled by and between the Indian Banks Association, repre-
senting the Management and All India Banks Employees As-
sociation, the National Confederation of the Banks Employees
and Indian National Bank Employees Congress representing
the Workmen outside the Tribunal.3. The terms and conditions of the said settlement are re-
corded in the Memorandum of Settlements dated April 21,
1980 and 15-7-1980. Your petitioner crave leave to refer
to the said original Memorandum of Settlements at the time
of hearing of this application, if necessary.4. Your petitioners submit that an Award should be passed
disposing of the reference pending before the Learned Tribunal
on the Terms and conditions recorded in the said Memoran-
dum of Settlements. A copy each of the said Memorandum
of Settlements are annexed hereto and marked with the letter
'A' & 'B'.5. Your petitioners further state and submit that an award
be passed in accordance with the Memorandum of Settlements.Your petitioners, therefore, humbly pray your Honour for
an order that—(a) An order be made awarding the term. of settlements
made by and between the parties as recorded in
annexures 'A' & 'B' to the petition.(b) Such further or other orders be made and or direc-
tions be given as your Honour may deem fit and
proper;And for this act of kindness your petitioners as in duty
bound shall ever pray.

ANNEXURE 'A'

Memorandum of Settlement dated 21st April, 1980 between
India Banks Association and All India Bank Employees' Asso-
ciation and National Confederation of Bank Employees

Name of the parties:—58 Banks.

Representing the Employers :

1. Shri K. Venkatachari
2. Shri N. Vaghul.

On behalf of the India Bank Association.

Representing the Workmen :

1. Shri D. P. Chadha.
2. Shri K. K. Mandul
3. Shri Prabhat Kar.
4. Shri Tarakeswar Chakraborti
5. Shri N. Sampath

On behalf of All India Bank Employees' Association.

1. Shri D. P. Gupta.
2. Shri C. L. Rajaratnam.
3. Shri C. R. Chandrasekaran.
4. Shri N. C. Choudhury

On behalf of National Confederation of Bank Employees.

Preamble :

Whereas the Goa Allowance and Assam Allowances paid/
payable to the workmen were under discussion between the
parties during the Bipartite negotiations.And whereas there are cases also pending before Tribunals
in respect of these allowances.

It is now agreed by and between the parties as under:—

(1) Goa Allowances :

- (a) Till 31-8-1978 Goa allowance will be payable to all
employees in all banks which were paying Goa
Allowance at the rates obtaining in the respective
Banks.
- (b) From 1-9-1978—
 - (i) CCA would be payable in the urban agglomeration
of Panaji and Marmugao.
 - (ii) HRA will be payable in accordance with Bipartite
Settlement at the places in Goa eligible for the
same.
 - (iii) In respect of employees covered by (a) above and who
continue to be in Goa as on the date of this Settle-
ment, if the aggregate of the HRA and CCA falls
short of the Goa Allowance payable to them, such
shortfall will be continued to be paid to them from
time to time as Goa Allowance

Assam Allowance :

- (a) All employees who were working prior to 31-3-1980 in
the Banks where Assam Allowance (by any name)
was being paid, the Assam Allowance will be paid
till 31-3-1980 at the respective rates.
- (b) From 1-4-1980 those employees will continue to draw
the allowance at the same rates.
- (c) In all other cases, in all Banks, the allowance will be
paid at a flat rate of Rs. 10 from 1-4-1980.
- (d) It is understood that Assam Allowance shall be paid
as per clauses (a), (b) & (c) above in other States,
viz. Manipur, Tripura, Nagaland, Meghalaya, Aruna-
chal Pradesh & Mizoram where the said allowance (by
any name) was being paid till special area Allow-
ances payable in these areas settled in respect of
workmen in these areas.

In respect of the proceedings now pending before Tribunals
in respect of 'Goa Allowance' and 'Assam Allowance' this
agreement will be submitted to the respective Tribunals with
the request for a 'Consent Award' on these terms.

[No. L-12011/61/77.D.II.A]

For Indian Banks' Association

K. VENKATACHARI, N. VAGHUL

S.O. 2983.—In pursuance of section 17 of the Industrial
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government
hereby publishes the following award of the Central Govern-
ment Industrial Tribunal New Delhi, in the industrial dispute
between the employers in relation to the management of Vijaya
Bank, Bangalore and their workmen, which was received by
the Central Government on the 4th October, 1980.BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING
OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

I.D. No. 5 of 1978

In re :

The Secretary, Rajasthan (State) Bank Workers Organisa-
tion, Dev Bhavan, Near Public Park, Udaimandir,
Jodhpur.

—Petitioner

Versus

The Chairman, Vijaya Bank Ltd., No. 2, Residency Road,
Bangalore

—Respondent.

AWARD

The Central Government as appropriate Government vide
its order No. L-12012/118/77-D.II.A dated the 28th Decem-
ber, 1977 referred an Industrial Dispute u/s 10 of the I.D.
Act, 1947 to this Tribunal in the following terms :"Whether the action of the management of Vijaya Bank
Ltd. Bangalore in terminating the services of Shri

S. N. Sharma, Clerk of Jodhpur Branch of the Bank with effect from 12-4-1977 is justified? If not, to what relief is the workman entitled?

2. On receipt of the reference it was ordered to be registered and usual notices were sent to the parties. In pursuance whereof a statement of claim was filed by the workman side. A written statement was later filed by the Bank and finally a replication was also got filed. Following two issues were framed vide my order dated the 25th October, 1979:

1. Whether any demand was raised. If not, its effect?

2. As in order of reference.

3. After the workman had filed the affidavits talks for compromise started between the parties and ultimately the matter has been settled between the parties vide settlement Ex. S/1. Thereafter statement of Shri C. L. Bhardwaj and Shri Jagat Arora, the representatives of the workman and Bank respectively were recorded which reads as under:

'The parties have settled the dispute vide S/1. read with Annexure A & B. An award in terms of settlement S/1 be made leaving the parties to bear costs.

4. In pursuance of the statements recorded above dispute stands settled amicably and accordingly an award in accordance with the settlement S/1 read with Annexure A & B is hereby made S/1 & annexure would form part of award. The parties would bear their own costs.

Further Ordered:

Requisite number of copies of this award with copies of S/1 & Annexure may be sent to the appropriate Government for necessary action at their end.
Dated: the 22nd September, 1980.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer.

FORM 'H'

(See Rule 58)

MEMORANDUM OF SETTLEMENT

NAME OF THE PARTIES:

1. Representing Employers—Mr. P. K. Handa, Regional Manager, Vijaya Bank, New Delhi.
2. Representing Workmen—Mr. C. L. Bhardwaj & Mr. S. N. Sharma, Workman in person.

SHORT RECITAL OF THE CASE

I. Mr. S. N. Sharma was appointed on probation with effect from 12-10-1976 in the service of the Bank vide letter dated 13-10-1976 as a Probationer. His services and performance was not upto the mark and he was not found suitable for absorption in the Bank's service. As such, his services were rightly and legally terminated on 11-4-1977. Subsequently, the order of termination of service of Shri S. N. Sharma was referred by the Central Government to the Central Government Industrial Tribunal presided over by Shri Mahesh Chandra for adjudication.

II. That it is the contention of the management that the non-confirmation of Shri S. N. Sharma in the Bank's service was perfectly in order and in accordance with the Bank's award and his contract of employment was terminated after having assessed his suitability for the job.

III. That Shri S. N. Sharma made an application dated June 5, 1980, which is annexed as Annexure 'A' requesting the management that he was prepared to withdraw the above said case provided he is given a fresh appointment as a clerk in any branch and further agreed that he is prepared to tender an unconditional apology for all his past acts against the Bank.

That in view of the same, a settlement has been arrived at between the parties which is without prejudice to the various contention as raised by the management in their written statement:—

TERMS OF SETTLEMENT:

1. That this settlement is in full and final settlement of all his claims including his claim for back wages,

retrenchment compensation, gratuity, provident fund, leave salary, bonus or any other benefits of whatsoever nature.

2. That Shri S. N. Sharma has tendered an unconditional apology for all his lapses in the past, vide his letter which is annexed as Annexure 'B' to this settlement.

3. That it has been agreed to by the Bank that within two months from the Publication of the award, the management will appoint him afresh as a Probationary Clerk and the appointment letter appointing him on probation for a period of six months will be issued.

4. It has also been agreed to by Shri S. N. Sharma that he may be posted in any branch or office of the Bank where the Bank has a vacancy.

This settlement is signed at Delhi, this 22nd Day of September, 1980.

Signature of the parties:

C. L. Bhardwaj

For & on behalf of workman

For & on behalf of the
Employers/Management.

For VIJAYA BANK

Sd/-

Illegible

Regional Manager,
New Delhi.

Dated: the 22nd September, 1980

WITNESS:

1. S. RAMANNA, Vijaya Bank, Regional Office, New Delhi.

2. S. N. SHARMA, Vyas Sadan Vijayachowk Jodhpur (Rajasthan).

The Personnel Manager,

Personnel Deptt.

Vijaya Bank,

H. O. Bangalore.

Dear Sir,

You may kindly refer to the industrial dispute before the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, regarding my termination on 11-4-1977 from the services of the Bank.

In the above connection, I am prepared to withdraw the above said case, provided I am given a fresh appointment as a clerk, not necessarily in Jodhpur branch. If this proposal is acceptable, I shall be prepared to tender an unconditional apology for all my past acts against the Bank.

Kindly let me know your decision in the matter, at your earliest.

Thanking you,

Your faithfully,

(S. N. SHARMA)

Vyas Sadan,

Vijaya Chowk,

Jodhpur (Rajasthan)

New Delhi

June 5, 1980.

ANNEXURE 'B'

The Regional Manager/Personnel Manager,

Vijaya Bank,

Kasturba Gandhi Marg/

New Delhi/H/O/Bangalore.

Dear Sir,

Reg: I. D. No. L-12012/118/77-D II-A/5/77 between the management of Vijaya Bank and its workmen relating to termination of my service.

With reference to the above I have to submit that my services were terminated on 11-4-77. I agitated against my termination and the dispute was referred for adjudication to the Hon'ble Presiding Officer, Central Govt. Industrial Tribunal, New Delhi.

M, services were terminated on the ground that my behaviour with my colleagues and customers was not proper. As regards my work there was no complaint at all. As far as I feel I never gave any chance of complaint about my behaviour with my colleagues and customers and as such there appears to be some misunderstanding on this score. However, if the authorities feel that my behaviour with the staff and customer was not proper I feel sorry for that in case I am taken back in Bank services.

I am ready to be posted as a Probationer as fresh entrant to be confirmed as per rules after six months. For my this apology I request that I be given employment with immediate effect.

September 22, 1980

Yours faithfully,

S. N. SHARMA, Yyas Sadan, Vijaya Chowk, Jodhpur.

[No L-12012/118/77-D II A]

S.O. 2984.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Grindlays Bank Limited, New Delhi and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th October, 1980.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

ID. No 23 of 1980

The Assistant Secretary,

National & Grindlays Bank Employees Union,
N-Block, Connaught Circus, New Delhi,

Petitioner

Versus

The Manager, Northern India Office of the
General Manager, Northern India,
Grindlays Bank Ltd., Connaught Circus,
New Delhi

Respondent

AWARD

The Central Govt as appropriate Govt referred an Industrial Dispute u/s 10 of the ID Act, 1947 vide its order L-12012/140/78-D.II A dated the 23rd April, 1980 in the following terms:

"Whether the action of the Management of the Grindlays Bank Limited, Connaught Circus, New Delhi in calling upon Shri Mohan Lal, Jamadar to operate Cyclostyling Machine in the office of the General Manager of the Bank at Connaught Circus, New Delhi is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

2. On receipt of the reference it was ordered to be registered and usual notices were sent to the parties. Whereupon parties representatives appeared and requested that parties may be given sometime to enable them to compromise and in course of time the matter was compromised between the parties and the said compromise was filed which is Ex S/1. The statement of parties representatives was recorded on 4th of September, 1980 which reads as follows:

"Parties have settled vide S/1, A no dispute award be made."

3. In view of the statement recorded above, a no dispute award is hereby made in this reference leaving the parties to bear their own costs.

Further Ordered :

That requisite number of copies of this award may be sent to the appropriate Govt for necessary action at their end.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

[No L-12012/140/78-D II A]

Dated the 19th September, 1980.

S.O. 2985.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, in the industrial dispute

between the employers in relation to the management of Central Bank of India, Jaipur and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th October, 1980.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

ID. No 18 of 1980

In re

The General Secretary,
Rajasthan Bank Employees' Union,
Parvana Bhavan, Madho Bagh.

Jodhpur

.. Petitioner

Versus

The Divisional Manager,
Central Bank of India, Divisional Office,
Sansar Chandra Road,
Jaipur (Rajasthan).

Respondent

AWARD

The Central Govt, as appropriate Govt, referred an Industrial Dispute to this Tribunal vide its order No. L-12012/132/79-D, II(A) dated the 10th April, 1980 u/s 10 in the following terms,

"Whether the action of the management of the Central Bank of India, Jaipur in withholding two increments of Shri Kushal Singh, Armed Guard at Bikaner Branch of the Bank with cumulative effect by way of punishment as per Appellate Authority's order dated August 17, 1978 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

2. On receipt of the reference usual notices were sent to the parties and in pursuance whereof a statement of claim was filed. None appeared for the workman while Shri B N Kak appeared for the Management. In so far as none had been appearing for the workman ex parte proceedings were ordered against the workman side and the Management was directed to file a statement of claim. A statement of claim was in fact filed. From the perusal whereof following one issue was framed:

As in the order of reference.

3. The case was then adjourned for evidence of the Bank. The evidence of the Bank has been recorded which consists of M-1, Presenting Officer on behalf of the Bank before the Enquiry Officer and the statement of Shri B N Kak. The enquiry proceedings and the various orders have been filed, in consequence thereof has also been filed as Annexure R-1 with the affidavit. From the perusal of statement of claim filed on behalf of the Bank I find that the contention of the Bank is that the alleged punishment of withholding to increments of Shri Khushal Singh, Armed Guard at Bikaner Branch of the Bank with cumulative effect was passed as a result of an enquiry held into the charges levelled against the workman. From the perusal of the enquiry proceedings and various orders filed as Annexure R-1 I find that the contention of the Bank substantiated by the enquiry proceedings and various other orders passed in pursuance thereof. The claim of the Management is supported by M-1 and after perusal of the enquiry proceedings and other documents I find that the enquiry in any manner was vitiated. The enquiry was held in provisions of the law laid down by various courts in this behalf. From the perusal of enquiry proceedings I do not find that the workman was not afforded full opportunity to present his case. The enquiry proceedings even do not remotely suggest that the Enquiry Officer has mis-directed himself or the enquiry or that he has unduly favoured the Management. There is absolutely nothing which goes to show that the enquiry is liable to be set aside. That being the position I do not think that the workman is entitled to any relief in this reference.

4. It may also be mentioned here that the conclusion arrived at by the Enquiry Officer are not capably wrong and are based upon the evidence led before the Enquiry Officer. The punishment also is not too harsh keeping in view the charges levelled against the workman. For my discussions and findings above, it is awarded that the action of the

Management of the Central Bank of India (a) in withholding two increments of Shri Kushal Singh, Armed Guard at Bikaner Branch of the Bank with cumulative effect by way of punishment as per appellate authority's orders is justified and that the workman is not entitled to any relief. Parties are however left to bear their own costs.

Further Ordered :

That requisite number of copies of this award may be sent to the appropriate Govt. for necessary action at their end.

Dated : the 27th August, 1980.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer.

[No. L-12012/132/79-D.II.A]

S.O. 2986.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Reserve Bank of India, Nagpur and their workmen, which was received by the Central Government on the 1st October, 1980.

BEFORE SHRI A.G. QURESHI, M.A.L.L.B., PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/L.C(R)(17)/1979

PARTIES:

Employers in relation to the Management of Reserve Bank of India, Nagpur and their workmen represented through the Chief Secretary, Reserve Bank Workers' Union C/o Reserve Bank of India Office, Nagpur-440001.

APPEARANCES:

For Union ...Shri G.C. Deshpande, Chief Secretary.

For Bank ...Shri G.G. Modak, Advocate.

INDUSTRY : Bank ...DISTRICT : Nagpur (M.P.)

AWARD

Dated September 20, 1980

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred by Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide Order No. L-12011/102/78-D.II.A Dated 5th July, 1979:—

"Whether the action of the management in not paying pay and allowances for periods ranging from 15 to 30 minutes to the workers shown in the annexure, on the alleged ground of their not attending to their work on 18-2-1978 for the said periods is justified? If not, to what relief are the workmen entitled?"

ANNEXURE

Sl. No.	Name	Designation
1	2	3
1.	Shri G.G. Deshpande	Daftary
2.	Shri V.B. Gadway	"
3.	Shri P.D. Panda	"
4.	Shri B.L. Wagh	Record Clerk
5.	Shri Y.B. Mohite	Peon
6.	Shri P.O. Kalu	"
7.	Shri B.H. Kame	"
8.	Shri S.S. Tonpe	"
9.	Shri N.G. Choubhe	"

1	2	3
10.	Shri N.K. Parsedk	Peon
11.	Shri R.P. Hiwase	"
12.	Shri D.N. Ukey	Peon (Temp.)
13.	Shri Pritam Singh	Peon
14.	Shri S.S. Hete	Peon (Temp.)
15.	Shri D.B. Pendem	Liftman
16.	Shri D.K. Chaturkar	Durwan
17.	Shri B.J. Gawande	Mazdoor
18.	Shri S.V. Thul	"
19.	Shri Dharampal Yadva	"
20.	Shri J.H. Hire	Mazdoor (Temp.)
21.	Shri Daniel Methes	Peon
22.	Shri B.H. Daf	Peon

2. The case of the Union is that on 18th February 1978 about 200 Class IV employees working in the Reserve Bank of India Nagpur, who are the members of the Union met the Manager in connection with certain important issues. As the Manager had refused to meet the Chief Secretary of the Union and the other office bearers of the Union on 17th February 1978, the deputation on 18-2-1978 consisted of 200 members. The deputation met the Manager at the start of the office. The Manager assured the deputation of his best cooperation. Thereafter within few minutes all the workmen went back to their respective desks. As a result of the assurance by the Manager the members ensured that no dislocation of work was to be caused and the work of the entire bank was carried out with utmost normalcy and without any hindrance. As the matter was resolved amicably there was no reason to allow the matter to be precipitated any further. Still the management issued an order deducting the wages of 22 employees for 15 minutes on proportionate basis. Actually 200 employees had joined the deputation still the management isolated only 22 workmen for wage cut.

It has further been averred that normal office hours start at 10.15 a.m. and banking hours from 10.30 a.m. The deputation met the Manager at 10 a.m. and the negotiations had concluded within a few minutes. No work was dislocated and banking work started as usual at 10.30 a.m. As the management had entertained the deputation it was unreasonable to deduct the wages for the period when the deputation met the Manager. The deputation was peaceful and disciplined; no objectionable slogans were raised by any of the deputationists.

3. The management resisted the claim of the workmen on the grounds that according to the practice, the Manager of each office holds regular conciliation meetings with the office bearers of the Union, with a view to sort out all local issues. Whenever the office bearers of the Union desire to discuss any matter with the Manager, they are required to do so with prior appointment, unless the matter requires immediate attention. But no prior intimation was given by the Union office bearers for meeting the Manager on 17th February 1978. Had the Chief Secretary of the Union given prior notice, the Manager would have adjusted his work and spared sometime for discussion with the Chief Secretary and the other office bearers. But as the Chief Secretary wanted to meet the Manager without any prior intimation, the Manager being preoccupied with some other, he could not meet the Chief Secretary. It is not the practice that any number of workmen may come and meet the Manager. On 18th February 1978, about 70 employees of the Bank resorted to mass demonstration during office hours suspending their normal duties. The call for mass demonstration was already issued on 16th February, 1978 and as a result of the call the workmen staged a mass demonstration during office hours after signing in the muster of attendance to voice their grievances. The workmen were addressed by the Chief Secretary of the Union for about 15 minutes and the employees then dispersed and went to their respective departments. They also shouted slogans against the bank management and against one of the officers of the Bank by name. The mass deputation commenced at 10 a.m. and

continued till 10.30 a.m. Although 70 employees did in fact participate in the mass demonstration, the wage deduction could be made only in respect of 22 employees, who could be identified and about whom the reports were received that they were absent from duties for the period of demonstration. The demands of the Union were already heard and the Personnel Officer of the Bank on the evening previous to the mass demonstration, had informed the Union representatives that arrangements have already been finalised for appointment of 24 daily wage mazdoors. Therefore, the mass deputation of Union on 18-2-1978 was totally unwarranted.

4. The Bank denied all the allegations made by the Union in its statement of claim and has further averred that the absenteeism from work amounts to a strike and the strike was an illegal strike as it was commenced in contravention of Sec. 22 of the Industrial Disputes Act. Therefore the management was justified in deducting the wages of the Class IV staff whose duties commence at 10 a.m. except the Daftaries; Gestetner Operators, Record Clerks and P.D.O. Press employees who are also Class IV staff and who attend office at 10.15 a.m. The management also raised certain legal objections to the competency of this reference but the legal objections were not pressed at the time of arguments by the management.

5. The parties have not led any evidence in support of their respective claims. The Union even did not send a rejoinder denying the allegations made by the management. In spite of intimation of the dates of hearing the Union remained absent on the dates fixed for filing of the documents, evidence and arguments.

6. The management has denied the allegations made by the Union but the Union has not cared to deny any of the allegations made by the management by filing the rejoinder. The Union did not care to appear before the Tribunal to rebut the allegations by filing any documents or leading any evidence. As such although the allegations made by the Union have been denied by the management, the allegations of the management remain undenied and thus unchallenged. In view of the fact, that the Union has not denied the allegations made by the management the management was not required to prove its allegations because the facts which are not disputed need not be proved. According to the management, there was no practice of staging a mass demonstration or taking a mass deputation during the office hours. The office hours of Class IV employees commence at 10 a.m. and of some other Class IV employees at 10.15 a.m. The workmen entered the office building, signed the attendance muster and then instead of working in the office, staged a demonstration and the slogans were shouted against the management and against a particular officer by name.

7. From the above undenied allegations of the Bank it is proved that the members of the Union including the concerned 22 workmen joined the mass demonstration during the office hours and that in the demonstration slogans were shouted against the management. It is also proved that the demonstration was staged as a result of a call from the union on 16-2-1978. As such, there was cessation of work and it was by a body of workmen acting in combination. Therefore, the action of the workmen is clearly a "strike" as defined in Sec. 2(q) of the Industrial Disputes Act, 1947. It has come on record that the Personnel Officer of the Reserve Bank of India Nagpur had already informed the Union that their demands were considered and being dealt with sympathetically. Therefore, there was no justification in staging a demonstration or making a joint deputation during office hours. The Union has tried to justify its action on the allegations that one day earlier to the mass deputation, the Manager had refused to meet the office bearers of the Union. But in this respect the management has averred that as the office bearers wanted to meet without any prior appointment and as the Manager was busy with some other urgent work, he could not meet them. Therefore, only this reason cannot justify the mass deputation. Further, the notice for mass deputation was issued on 16th February by the Union, which clearly shows that refusal by the Manager of the Bank to meet the office bearers of the Union on 17th February was not the main cause for staging a mass demonstration. Hence I find no justification in the cessation of work by the workmen during office hours, which amounted to a strike. The workmen cannot be held to be justified

in using the weapon of strike, without exhausting the reasonable avenues for a peaceful achievement of their objectives. The strike was not peaceful and the slogans were raised in the office building against the management and against a particular officer by name.

The management was therefore justified in deducting the wages of the workmen for the strike period, as the strike was not provoked by any high handed action of the employer and was thus not a justified strike. If the workmen instead of resorting to the conciliatory methods used the weapon of the strike without any provocation by the management to press their demands then the management cannot be held responsible for the loss of wages of the strike period. I am fortified in my view by the judgment of the Supreme Court in Candra-malai Estate, Ernakulam Vs. Its workmen and another (1960-II-LJ p. 243).

8. It has further been averred by the workmen union that 200 workmen had participated in the strike, whereas only 22 workmen were sorted out for deduction of wages. On this point, the management has clearly averred that the management could identify and locate only 22 workmen out of about 70 workmen who participated in the strike. Therefore the wages of only 22 workmen could be deducted. The Union has not shown that the management has isolated these 22 workmen with some ulterior motive and has favoured the other workmen who participated in the strike. The action of the management therefore cannot be held to be discriminatory also.

9. In the result, I hold that the action of the management of Reserve Bank of India Nagpur Branch in not paying the pay and allowances to the 22 workmen shown in the annexure is justified. The workmen are, therefore, not entitled to any relief. Parties shall bear their own costs as incurred.

A. G. QURESHI, Presiding Officer,
[No. L-12011/102/78-D.II.A]

S.O. 2987.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Punjab National Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th October, 1980.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 88 of 1978

PARTIES :

Employers in relation to the management of Punjab National Bank.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

On behalf of Employers.—Mr. Dipak Dey, Advocate.

On behalf of Workmen.—Mr. P. K. Biswas, General Secretary, Punjab National Bank Shramik Union.

STATE : Assam

INDUSTRY : Banking

AWARD

This reference under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has been referred to this Tribunal for adjudication by the Government of India by Order No. L-12011/57/77-D.II.A dated 27/30th October, 1978. The dispute referred for adjudication reads :

"Whether the proposed action of the management of Punjab National Bank in discontinuing payment of House rent allowance to their employees employed in North Eastern Sector including Assam w.e.f. 5-11-1976 is legal and justified? If not, to what relief are the workmen concerned entitled?"

2. In this case both the parties, namely the employers in relation to the management of Punjab National Bank and its workmen represented by Punjab National Bank

Shramik Union have filed a joint petition of compromise praying for an award in terms of settlement appearing in Annexure 'A' & 'B' to the petition. Annexure 'A' is a Memorandum of Settlement dated 21st April, 1980 between the Indian Banks Association on the one hand and All India Bank Employees Association and National Confederation of Bank Employees on the other. Annexure 'B' is a Memorandum of Settlement dated 15th July, 1980 between the Indian Banks Association on the one hand and Indian National Bank Employees Congress on the other. Both the Annexures contain terms including the term for Assam allowance. In the present case we are concerned with Assam allowance which according to the terms between the parties the workmen are entitled to.

3. I have heard Mr. P. K. Biswas, General Secretary of Punjab National Bank Shramik Union and Mr. Dipak Dey, Advocate appearing on behalf of the Bank. It is submitted by both the parties before me that if an award be passed on the basis of the terms in respect of Assam allowance mentioned in Annexure 'A' it will be sufficient and the parties will be satisfied. The terms appearing in Annexure 'B' are the same as I find in Annexure 'A' in respect of Assam allowance.

4. In the circumstances, I find that the settlement is reasonable and legal and as prayed for by the parties I pass an award in terms of the petition of compromise with reference to the term in respect of Assam allowance appearing in Annexure 'A'. The joint petition of compromise and Annexure 'A' shall form part of this award.

R. BHATTACHARYA, Presiding Officer.

Dated, Calcutta,

The 29th September, 1980.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

Reference No. 88 of 1978

Employers in relation to the Management of Punjab National Bank.

Vs.

Its Workmen.

The humble joint petition of the Management and Union, the petitioners abovenamed.
Most respectfully sheweth—

1. Your petitioners state and contend that the hearing of the above matter was held at Gauhati on September 10, 1979.

2. Your petitioners further state and contend that the dispute with regard to the Assam Allowance has been amicably settled by and between the Indian Banks Association, representing the Management and All India Banks Employees Association, the National Confederation of the Banks Employees and Indian National Bank Employees Congress representing the workmen outside the Tribunal.

3. The terms and conditions of the said settlement are recorded in the Memorandum of Settlements dated April 21, 1980 and 15-7-1980. Your petitioners crave leave to refer to the said original Memorandum of Settlements at the time of hearing of this application, if necessary.

4. Your petitioners submit that an Award should be passed disposing of the reference pending before the Learned Tribunal on the terms and conditions recorded in the said Memorandum of Settlements. A copy of the Memorandum of Settlement are annexed hereto and marked with the latter 'A' and 'B'.

5. Your petitioners further state and submit that an award be passed in accordance with the Memorandum of Settlements.

Your petitioners, therefore, humbly pray your Honour for an order that—

- (a) An order be made awarding the terms of settlements made by and between the parties as recorded in annexure 'A' & 'B' to the petition.
- (b) Such further or other orders be made and or directions to be given as your Honour may deem fit and proper.

And for this act of kindness your petitioners as in duty bound shall ever pray.

ANNEXURE 'A'

Memorandum of Settlement dated 21st April, 1980 between Indian Banks Association and All India Bank Employees' Association and National Confederation of Bank Employees

Name of the parties :

58 Banks.

Representing the Employers :

1. Shri K. Venkatachari.
2. Shri N. Vaghul.

On behalf of the Indian Banks Association.
Representing the Workmen :

1. Shri D. P. Chadha.
2. Shri K. K. Mandul.
3. Shri Prabhat Kar.
4. Shri Tarakeswar Charabort.
5. Shri N. Sampath.

On behalf of All India Bank Employees' Association.

1. Shri O. P. Gupta.
2. Shri C. L. Rajaratnam.
3. Shri C. R. Chandrasekaran.
4. Shri N. C. Choudhury.

On behalf of National Confederation of Bank Employees.
Preamble :

Whereas the Goa Allowance and Assam Allowances paid/payable to the workmen were under discussion between the parties during the Bipartite negotiations.

And whereas there are cases also pending before Tribunals in respect of these allowance.

It is now agreed by and between the parties as under :—

(1) Goa Allowance :

- (a) Till 31-8-1978 Goa Allowance will be payable to all employees in all banks which were paying Goa Allowance at the rates obtaining in the respective Banks.
- (b) From 1-9-1978—
 - (i) CCA would be payable in the urban agglomeration of Panaji and Marmugao.
 - (ii) HRA will be payable in accordance with Bipartite Settlement at the places in Goa eligible for the same.
 - (iii) In respect of employees covered by (a) above and who continue to be in Goa as on the date of this Settlement, if the aggregate of the HRA and CCA falls short of the Goa Allowance payable to them, such shortfall will be continued to be paid to them for time to time as Goa Allowance.

(2) Assam Allowance :

- (a) All employees who were working prior to 31-3-1980 in the Banks where Assam Allowance (by any name) was being paid, the Assam Allowance will be paid till 31-3-1980 at the respective rates.
- (b) From 1-4-1980 those employees will continue to draw the allowance at the same rates.
- (c) In all other cases, in all banks, the allowance will be paid at a flat rate of Rs. 10/- from 1-4-1980
- (d) It is understood that Assam Allowance shall be paid as per clauses (a), (b) & (c) above in other states,

viz. Manipur, Tripura, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh & Mizoram where the said allowance (by any name) was being paid till special area Allowances payable in these areas.

In respect of the proceedings now pending before Tribunals in respect of 'Goa Allowance' and 'Assam Allowance', this agreement will be submitted to the respective Tribunals with the request for a 'Constant Award' on these terms.

FOR INDIAN BANKS' ASSOCIATION

Sd/-
K. Venkatecheri
Sd/-
N. Vaghul

FOR ALL INDIA BANK EMPLOYEES ASSOCIATION

Sd/-
D.P. Chadha

Sd/-
Tarakeswar Chakraborty

FOR NATIONAL CONFEDERATION OF BANK EMPLOYEES

Sd/-
C.L. Rajaratnam

Sd/-
C.R. Chandrasekaran

Witness :

- Sd/-
1. M. Ram Mohan Rao
Sd/-
2. N. Sampath
Sd/-
3. R. Sivagyanam

Date : April 21, 1980

Place : Madras

Copy to :

1. Conciliation Officer (Central), Madras.
2. Regional Labour Commissioner (Central), Madras.
3. Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi.
4. The Secretary to the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi.

[No. L-12011/57/77-D.IIA]

S. H. S. IYER, Desk Officer

New Delhi, the 14th October, 1980

S.O. 2988.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby by publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Kuju Colliery of Central Coalfields Limited, Post Office Kuju, District Hazaribagh and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th October, 1980.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) DHANBAD

Reference No. 77 of 1979

In the matter of an industrial dispute under S. 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

PARTIES : Employers in relation to the management of Kuju colliery of Messrs Central Coalfields Limited, Post Office Kuju, District Hazaribagh

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers : Shri T. P. Choudhury, Advocate.

On behalf of the workmen : Shri B. Joshi Advocate.

State : Bihar Industry : Coal.

Dhanbad, 30th September, 1980

AWARD

This is a reference under S. 10 of the I.D. Act, 1947. The Central Government by its notification No. L-20012/217A/76-

D.IIA dated 3rd September, 1977 has referred this dispute to this Tribunal for adjudication on the following points :

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Kuju colliery of Central Coalfields Limited, Post Office Kuju, District Hazaribagh, in stopping Sri Lala Satyanarayan Prasad, Sinha, Munshi-cum-attendance clerk, from work with effect from 11th May, 1973, is justified. If not, to what relief is the said workman entitled ?"

2. The case of the concerned workman, Shri Lala Satnarayan Sinha is that he was appointed in Kuju Colliery as Munshi-cum-attendance clerk on 18-2-72 at incline No. 6C and quarry No. 6C. The colliery then was worked by a contractor Shri J. K. Sayal under the owner Shri Jiwan Lal Sunda. The management of this colliery was taken over by the Central Government w.e.f. 31-1-1973. The same contractor continued to operate the mine till 31-3-73 whereafter it was departmentally operated. All the persons employed in the different mine under the contractor were allowed to continue in the employment and became the employee of the Government company w.e.f. 1-3-73 and were paid monthly wages from 1-3-73. From 1-5-73 nationalisation came and the right, title and interest of the previous owners of the colliery vested in the National Coal Development Corporation Ltd. which was subsequently designated as M/s. Central Coalfields Ltd. The case of the concerned workman is that he continued in the employment under the Government company after abolition of the contract system, and even after nationalisation. According to him although he was employed in the year 1972, his service was confirmed with effect from 11-1-73 and his name was duly entered in the form B register. His attendance was marked in the Form C and D registers and his salary was paid on form Y register. His case is that all of a sudden the management stopped the concerned workman from duty w.e.f. 11-5-73 without assigning any reason. When he approached the manager of the colliery he was informed that he was considered to be a inductee by the screening committee although the manager had forwarded his name in the list of the genuine workers of the colliery. He was also informed that some political decision was followed by the screening committee at the instance of the union representatives. The concerned workman realised that the union representatives did not help him because he was unable to pay to the union funds the demand of money made by the union leader. He therefore approached the Assistant Labour Commissioner (C) Hazaribagh and raised an industrial dispute before him. According to him the management representative agreed before the conciliation Officer (C) to consider the case of the concerned workman in order to reinstate him in the job and got the proceeding stayed. But sometime after it was realised that the management was simply avoiding the issue and was unnecessarily protracting the conciliation proceeding on one pretext or another. The Assistant Labour Commissioner (C) therefore submitted a failure report to the Ministry of Labour, Government of India as a result of which this reference has been made.

3. The case of the management is that Kuju colliery, a noncoking coal mine was taken over by the Central Government under the ordinance on 31-1-73. The Central Government constituted an authority known as Coal Mines Authority which became the Custodian of the taken over non-coking coal mines. Later on Government company named as Coal Mines Authority was incorporated and on further re-organisation, M/s. N.C.D.C. Ltd. now known as Central Coalfields Limited came in the management of Kuju colliery. Kuju colliery was being worked by the owners mostly through the contractors. While some records were available about the employees appointed directly by the ex-owners, there was no record maintained by the contractor. Since hundreds of persons were claiming to be employed in the mine, the management was compelled to allow every one to work till the screening was done by the Government company. Accordingly Shri Sinha, the concerned workman was allowed to work in the colliery for sometime claiming to be an employee of the contractor Shri J. K. Sayal. The screening committee consisted of the responsible officers of the Coal Mines Authority and worked in close co-operation with the local secretary of Rastriya Colliery Mazdoor Sangh,

Kuju Branch. His case was carefully examined by the committee. The concerned workman was found to be not genuine workman of the contractor—Shri J. K. Sayal. The concerned workman along with others preferred appeals against the decision of the screening committee which was heard by the Dy. Custodian General on 10-7-73 and 11-7-73. The trade union representatives submitted an agreed list of 19 monthly rated employees which should have been included in the screening list and the Dy. Custodian General issued orders for absorption those 19 persons. In the appeal also the concerned workman was not considered to be a genuine employee even by the representatives of the trade unions. According to the management, therefore, there is no question of reinstatement.

4. The management also took the plea that since the concerned workman was an inductee this was virtually a case of seeking employment and so it is not an industrial dispute under S. 2A of the I. D. Act, 1947.

5. It will appear from the case of the parties that from the papers produced before the management by the contractor such as Form B register, attendance register and wage register that the concerned workman was the Munshi-cum-attendance clerk of the contractor Shri Sayal. All those papers were produced at the conciliation stage. Form B register, which is a record of employment was produced before the Conciliation Officer and returned to the management. While other registers have been produced here by the management, Form B register could not be produced and the plea in the written statement is that this register has mysteriously disappeared. In short, we can say even from the documents produced by the management, the concerned workman was an employee of the contractor at the time when the take over of the colliery took place. Since he was stopped from 11-5-73, the concerned workman worked for 10 days even after the nationalisation of the colliery which took place on 1-5-73. It has been argued on behalf of the concerned workman that the concerned workman has given ample proof of the fact that he was a workman of the colliery at the time of take over, continued to be a workman till the date of nationalisation and thereafter and so his interest is protected as workman under the scheme of Nationalisation Act. Now this is a position which could be normally accepted but for the fact that according to the management the concerned workman was not employee of the contractor and the contractor manufactured documents in order to show that he is a workman in the colliery so that he could be absorbed at the time of take over and subsequent nationalisation. For taking this stand the management relied upon the decisions taken by the screening committee and the Appellate Committee. The screening committee consisted of higher officers and the different unions presented before the screening committee the names of genuine workmen. The screening committee considered them and prepared a screening list of genuine workmen. The concerned workman was screened out. He thereafter preferred an appeal and at that stage the union leaders presented the names of 19 workmen who were screened out by the screening committee. The appellate authority reinstated them on the basis of the agreed list of the union representatives. The concerned workman was again not supported by the unions and he was left out. The management, therefore, has to say that as the union representatives had not supported the case of the concerned workman, he was screened out by the screening committee and his appeal was rejected. The Assistant Labour Commissioner (C) Hazaribagh considered this aspect when the management representatives put such an argument and according to him this was a curious argument and not acceptable to him.

6. The screening list is Ext. M1. This only shows that he was a workman of the colliery and was screened out. This document does not give any reason why he was screened out. The learned Advocate appearing for the management has not given a single good reason why the concerned workman should have been regarded as an inductee or an imposter. Ext. M7 contains the names of 6C incline workmen in which the name of Shri Lala Satnarayan Prasad Sinha appears in the end. It has been contended by him that the name of the concerned workman is an addition because his name is at the end. This is not sound argument. Then again in Ext. M6 it has been pointed out that 11-1-73 was a Sunday but his attendance had been marked even on that date. It is stated to be an interpolation. I do not see why :—because

even on sundays a workman can be called upon to work. Ext. M5 is said to contain most of the writings by this concerned workman. On behalf of the workmen it has been argued that Shri Lala Satnarayan Prasad Sinha being a B.Sc. was utilised by the contractors in writing out papers concerning the workings of the colliery. It further appears that the other munshies were less qualified. For instance Shri Rajendra Prasad shown as S. No. 67 in the screening list was B. Sc Part I. The qualification of Shri Deo Kishan Thakur at sl. No. 68 has not been mentioned. Another munshi Shri Ram Kumar Prasad at sl. no. 69 happens to be a non-matric. It is an admitted case that 4 munshies were employed by the contractor although there were three shifts as admitted by MW-1 and the concerned workman. The learned Advocate for the workmen tells me that there should have been at least 8 munshies and attendance clerks. The contractor with the idea of minimising the expenditure had not employed persons but that could not be a fault of the workmen and no adverse inference could be taken against him. The only document upon which the management relied is Ext. M-11 a list submitted by the contractor prior to 31-1-73. The name of Shri Lala Satnarayan Prasad Sinha does not occur there. But according to the management all the documents and papers were filed by the contractor in the month of March, 1973, i.e. after the take over. Now if Ext. M-11 was a correct document, how should the name of the concerned workman occur in the workers list when the Custodian took charge of the colliery. It is an admitted position that all the workmen of the contractor included in the Form B register showed that the concerned workman was a workman of the colliery. It was on that basis that he continued to work in the colliery till he was stopped from work. It cannot be therefore, said that the contractor excluded Shri Lala Satnarayan Prasad Sinha from the list of workers.

7. I have tried to pick out the necessary documents referred to by the management out of the list of exhibits which is a large one and has no direct bearing in our discussions. 2 witnesses were examined on behalf of the concerned workman. The management examined Shri S. K. Maity the manager of the colliery. They have all given the history of the case and proved documents, MW-1 is the manager of the colliery. His evidence is that he never saw Shri Lala Satnarayan Prasad Sinha prior to the take over. Then we have before us certain papers of the conciliation stage which are Exts. W.2 to W.6. In Ext. W.2, the Asstt. Labour Commissioner (C) Hazaribagh wrote to Shri S. K. Singh, Sub-Area Manager that the exclusion of Shri Sinha from the screening list and his stoppage from work did not appear to be justified. Ext. W.4 is a letter addressed to the Regional Labour Commissioner (C) Dhanbad by Shri S. N. Sahay, Secretary of Colliery Mazdoor Sangh requesting him to absorb Shri Lala Satnarayan Prasad Sinha in the job in the interest of justice. Ext. W.6 is a letter addressed to Shri P. C. Rai, Dy. Chief Labour Commissioner (C) New Delhi by Shri J. N. Das, Regional Labour Commissioner (C) Dhanbad on 28-1-77 in which the case of the concerned workman has been fully presented and it has been stated that in view of the hard attitude adopted by the management he had no other alternative but to refer the dispute for adjudication.

8. From the above it will be evidently clear that Shri Lala Satnarayan Prasad Sinha the concerned workman was chucked out as an inductee without any apparent reason as to how he could be called as inductee. The only reason shown is that at the time of screening and at the appellate stage the union representatives did not support him. In the written statement and in his evidence the concerned workman has made it clear that the union representatives did not favour him because he could not meet their monetary demands. It has been argued on behalf of the workmen that at the time of screening even the union representatives were anxious to put the case of their own men and Shri Lala Satnarayan Prasad Sinha did not find favour from them. Similarly 26 persons had appealed from the decisions of the screening committee and the union representatives combined to support the case of 19 persons and they were all taken in. From the screening list itself it will appear that in the screening list Shri Lala Satnarayan Prasad Sinha was shown to be a workman from 1-1-73. The other munshi Shri Ram Kumar Prasad was shown to have been appointed on 4-1-73 having a non-matric qualification. Another munshi Shri Deo Kumar Thakur was appointed on 14-1-73 and Shri Rajendra Prasad another munshi was appointed on 16-2-73. Obviously Shri Lala Satnarayan Prasad Sinha was the senior most among all the other munshies. But unfortunately the screening committee and the appellate committee chucked him

out and approved all others. Naturally they were taken into the jobs on the basis of the contractor's papers. How could the same papers be held to be forged in the case of the concerned workmen when the management on the basis of the said papers held the other munshies to be genuine. This considering all aspects of the case I have to hold that the management had no reason to consider Shri Lala Satnarayan Prasad Sinha as inductee in order to screen him out. The management has taken the plea that in this reference the union has not raised this dispute and therefore this dispute should be considered to be under S. 2A of the I.D. Act. According to the management Shri Lala Satnarayan Prasad Sinha was not a genuine worker and therefore the demand of the workmen would amount to seeking a job.

I have no reason to agree with this argument. Shri Lala Satnarayan Prasad Sinha was admittedly a workman and he was stopped from work by the management on the ground that he was not a genuine workman. I have already held that the management has shown no justification for holding that the concerned workman was an inductee. The stoppage of work, therefore, would amount to retrenchment and therefore, this case should be deemed to be an industrial dispute under S. 2A of the I.D. Act, 1947.

9. Thus having considered all aspects of the case I have to hold that the action of the management of Kuju colliery of Central Coalfields Limited, Post Office Kuju District Hazaribagh, in stopping Shri Lala Satnarayan Prasad Sinha, Munshi-cum-attendance clerk, from work with effect from 11th May, 1973 is not justified. Consequently, the workman is entitled to be reinstated in his job with effect from 11th May, 1973 with all back wages and other emoluments.

This is my award.

J. P. SINGH, Presiding Officer
[No. L-20012/217-A/76-D. III A]

New Delhi, the 15th October, 1980

S.O. 2989.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Arbitrator, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Stores, Central Coalfields Limited, Barkakana and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th October, 1980.

OFFICE OF SRI R. S. MURTHY, ARBITRATOR C/O
CHIEF PERSONNEL OFFICER, CENTRAL COALFIELDS
LIMITED, DARBHANGA HOUSE, RANCHI

In the matter of an industrial dispute

BETWEEN

(1) Employers in relation to the management of Central Stores of Central Coalfields Limited, Barkakana

AND

(2) Their workmen as represented by Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Barkakana Area, Post Office Barkakana, New Township, Distt. Hazaribagh.

APPEARANCES :

For the management : (1) Col. K. C. Sharma, Materials Manager (Stores) Central Coalfields Ltd., Darbhanga House Ranchi. (2) Sri A. K. Sen, Dy. Materials Manager, Central Coalfields Ltd., Darbhanga House, Ranchi. (3) Sri T. P. S. Sodhi, Dy. Personnel Manager, Central Workshop, Central Coalfields Ltd., P.O. Barkakana, New Township, Distt. Hazaribagh.

For the workman : (1) Sri Badri Singh, Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh Central Workshop, P.O. Barkakana Distt. Hazaribagh.

AWARD

Ranchi, the 27th September, 1980

An industrial dispute with the following terms of reference between the above parties was referred to me for arbitration under Section 10-A of the Industrial Disputes Act vide notification No. L-20013(4)/80-D.III(A) dated 11-4-1980 of the Ministry of Labour, Govt. of India, New Delhi :—

"Whether action of Management of Central Coalfields Ltd., in stopping two increments with cumulative

effect in respect of Sri S. N. Rai, Cashier, Central Stores, Barkakana in the pay scale of the post held by him is justified? If not, to what relief Sri S. N. Rai is entitled?"

After notices were issued by me to the parties and they submitted their written statements indicating their respective stands and rejoinders to the written statements of each other, I heard the parties in the officer's Rest House, CCL, Ranchi on 30-8-1980.

2. In terms of the aforesaid notification, I was required to give my award within a period of 3 months or within such further time as is extended by mutual agreement between the parties in writing. In case the award is not given within the period aforementioned the reference to arbitration would stand automatically cancelled and the parties will be free to negotiate for fresh arbitration. The parties agreed to extend time to enable me to give my award upto 30-9-1980.

3. The case of the Management is as follows :—

(a) The workman concerned Sri S. N. Rai, Cashier Central Stores, Barkakana was issued with a charge-sheet No. COS/Conf/S. N. Rai/77/3467 dated 7-10-1977. The charge related to the train fare bill amounting to Rs. 66.80 prepared in the name of Sri Neur Ram, Tyndal, Central Stores, Barkakana not having actually been paid to him by Sri S. N. Rai and the acquittance roll of Sri Neur Ram showing that the payment had been made by him to Sri Neur Ram. In this manner Sri S. N. Rai indulged in falsehood with a view to secure financial gains for himself by pocketing the amount of the bill.

(b) After the workman had submitted his explanation an enquiry was ordered which was conducted by Sri P. B. K. Rao, Asstt. Chief Personnel Officer, Barkakana Area and the Enquiry Officer also submitted his findings on the basis of the enquiry held by him as he was required to do.

(c) The Enquiry Officer held Sri S. N. Rai, Cashier, Central Stores, Barkakana guilty of the charge framed against him regarding embezzlement of the train fare bill amounting to Rs. 66.80 and on the basis of the evidence on record and the findings of the Enquiry Officer Sri S. N. Rai was punished with stoppage of two increments with cumulative effect and also the amount of Rs. 66.80 embezzled by him was also ordered to be recovered from him. The order was issued on 1-9-1979.

(d) The action of the management imposing the punishment in question against him was quite lenient, reasonable and justified. Sri S. N. Rai actually deserved to be dismissed from service under the circumstances, but the management took a lenient view of the charge established against him in awarding a lighter punishment.

4. As against the above stand of the Management, the case of the union is as follows :—

(a) While there was no controversy in regard to the charge framed against Sri Rai, the enquiry ordered by the management after he submitted his explanation and the enquiry held by Sri P. B. K. Rao and the submission of findings by him, the union contended that the Enquiry Officer actually recommended that the ends of justice will be met if Sri Rai is censured and the whole amount of Rs. 66.80 representing pecuniary loss caused to the Company is recovered from his wages and paid to the complainant Sri Neur Ram. However, the Materials Manager(S) awarded him with punishment of stoppage of two annual increments with cumulative effect.

(b) While the Enquiry Officer submitted his recommendations as per the directions of the management along with his findings and enquiry report, the management should have constituted another enquiry, if they did not agree with the findings and recommendations of the Enquiry Officer. They also stated that the Materials Manager(S) did not differ from the findings and recommendations of the Enquiry Officer.

- (c) The union claimed in view of their contentions that the order of the management of withholding two annual increments with cumulative effect is null and void and relief should be given accordingly.

5. I have heard the parties at length who repeated their respective contentions as advanced both in the written statements and rejoinders. I have also interrogated the workman concerned to find out the facts of the case and he stated that he did not make any wrong payment to any person earlier after working for 8 years or more and that the charge framed against him is not correct. He reiterated that he had paid the amount to Sri Neur Ram himself. The additional contentions advanced by Sri Badri Singh on behalf of the workman are as follows :—

- (a) At the relevant time when the payment was made to Sri Neur Ram Sri Rai was an Upper Division Clerk and he was not formally appointed as cashier and it was only later that he was appointed as a cashier. This was confirmed by the management representatives.
- (b) In the order dated 1-9-1979 issued by the Materials Manager(S) imposing the punishment to Sri S. N. Rai, it was not stated that the Materials Manager(S) had disagreed with the findings and recommendations of the Enquiry Officer.

6. The stand of the management is that the order issued by the Materials Manager(S) imposing the punishment dated 1-9-1979 was very clear. It stated inter-alia as follows :—

"I have carefully considered the report of the Enquiry Officer and the connected documents. The Enquiry Officer came to the conclusion that there is overwhelming evidence to show that Sri S. N. Rai has committed the misconduct with which he was charged and that he was trying to take different pleas with a view to save himself. Subsequently he came to the conclusion that Shri S. N. Rai is guilty of the charge that the train fare bill amounting to Rs. 66.80 was paid to someone else other than the actual payee. The charge whether Shri Rai has pocketed the amount and indulged in falsehood for securing pecuniary gain is not proved according to the Enquiry Officer.

On the basis of the study of the case and all the relevant documents as made by me including the evidence the charge framed against Sri S. N. Rai that the train fare bill amounting to Rs. 66.80 in the name of Shri Neur Ram. Tyndal, Central Stores, Barkakana was not paid to him although in the acquittance roll it was shown that the payment had been made to him. There is no evidence to show that the payment was made to someone else as stated by the Enquiry Officer. In fact, Sri S. N. Rai also did not take such a stand in his written explanation dated 18-10-77 to the charge-sheet nor has he produced any evidence to that effect. The irresistible conclusion, therefore, is that Sri S. N. Rai has pocketed the amount of Rs. 66.80 and indulged in falsehood with a view to securing a financial gain for himself. Thus I reiterate the conclusion that the charge in question has been thoroughly established against Shri Rai and that he is guilty of the same.

I have also considered the matter as regards the punishment to be awarded to Shri Rai. Considering the gravity of the misconduct committed by Shri Rai there is a strong case for dismissing him from service. However, I have decided to take a lenient view and to impose the punishment of withholding of two increments of Shri S. N. Rai in the pay scale of the post held by him. That is to say the two increments that may fall due to him hereafter in the said pay scale will be withheld and such withholding of increments will have cumulative effect i.e. effect of postponing future increments. I further

order that the amount of Rs. 66.80 should be recovered from the salary of Shri Rai and paid to Shri Neur Ram in case the Management has not otherwise made such payment to Shri Ram."

7. The above order is self-explanatory and there was no substance in the contention of the union.

8. The union has not found any fault with the charge-sheet or the enquiry and their case is confined only to the point relating to the imposing of the punishment by the Materials Manager(S). The disciplinary authority it is well stated, is quite competent to disagree with the findings and recommendations of the Enquiry Officer and he may come to his own conclusion on the basis of the evidence. The aforesaid order of the Materials Manager(S) confirms that he proceeds on that basis. Having done so, he was also entitled to come to his own conclusion about the quantum of punishment to be awarded to the charge-sheeted employee.

9. It is not even the case of Sri Rai that he did not know Sri Neur Ram. The enquiry report also reveals that the payment was not made to Sri Neur Ram or anyone else or the natural inference is that Sri Rai himself pocketed this amount in question. The opinion of the handwriting expert was also taken by the Enquiry Officer which confirms that the signature on the receipt was not that of Sri Neur Ram himself. In the circumstances, there is no strong case in favour of Sri Rai for interfering with the decision taken by the management.

10. However, it is also admitted during the course of oral submissions of the parties that Sri Rai put in long years of service in the organisation and that his previous records were clean. During the relevant period he was not formally appointed as cashier, but this contention is not quite tenable as Sri Rai had accepted the responsibilities of the Cashier and the pay scale of post of Cashier and UDC is the same. For the purpose of this particular case, I feel however some consideration to this contention of the union should be given. Having thus considered the matter and also keeping in view the totality of the circumstances of the case, the long and clean past records of service of Sri Rai, I feel that there will be justification for reducing the punishment from stoppage of two increments with cumulative effect to stoppage of one increment for six months without cumulative effect. That is to say that the next increment after 1-9-1979 which falls due to Sri Rai in the pay scale of post held by him would be postponed by six months without cumulative effect from the date it falls due in the ordinary course according to the rules of the management. To illustrate if the next increment falls due on 1-3-1980 it will be given from 1-9-1980. This is being indicated only by way of illustration. The actual date will have to be determined with reference to the next date of increment of Sri Rai after 1-9-1979. There will be no charge in regard to recovery of the amount in question from Sri Rai. I give my award accordingly.

11. In the circumstances of the case, each party will bear their costs.

R. S. MURTHY, Arbitrator

[No. L-20013(4)/80-D. III(A)]

S.O. 2990.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Punjab National Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th October, 1980.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING
OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL

TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
NEW DELHI

I.D. No. 35 of 1980

In re :

The State Vice President, Punjab National Bank Employees' Union, 295/387, Deen Dayal Road, Asharfa-
bad, Lucknow. ...Petitioner

Versus

The Regional Manager, Punjab National Bank, Bibhab Nagar, Agra.—Respondent.

AWARD

The Central Government as appropriate Government referred an Industrial Dispute u/s 10 of the I.D. Act, 1947 vide its order No. L-12012/121/79-D.II.A dated the 20th May, 1980 in the following terms :

'Whether the action of the management of Punjab National Bank in relation to their Jhansi Branch in not treating Shri Mumtaz Khan, Peon-cum-Driver, as Bank's employee and also terminating his services from April, 1977 was justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?'

2. On receipt of the reference it was ordered to be registered and usual notices were sent to the parties. Whereupon the workman side filed its statement of claim and thereafter the case was fixed for filing of written statement. But before any written statement could be filed the parties have come forward before me stating that they have compromised the dispute, whereafter I pass an order for the recording of settlement. The statement of representatives of the parties was recorded which is as under :

'Vide the settlement S/1 the matter is compromised. An award be passed accordingly.'

3. In view of the statement recorded above I pursued the settlement Ex. S/1 and find that it is for the benefit of the workman and a no dispute award is hereby made in this reference leaving the parties to bear their own costs. The settlement Ex. S/1 would form part of this award.

Further Ordered :

That requisite number of copies of this award may be sent to the appropriate Government for necessary action at their end.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

Dated, the 1st October, 1980

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

Case No. I.D. 35 of 1980

In the matter of Industrial Dispute

BETWEEN

The Management of Punjab National Bank through their Regional Manager, Agra

AND

their workmen represented by Punjab National Bank Employees' Union, 19, Garbhajhala, Aminabad, Lucknow.

JOINT MEMO FILED BY THE PARTIES

Most Respectfully Showeth :

THAT :

1. The above matter is pending adjudication before the Hon'ble Tribunal and the parties have arrived at the following settlement :—

(a) that without prejudice to its contention that Shri Mumtaz Khan was a personal driver of the Development Manager, the Bank agrees to appoint Shri Mumtaz Khan in the sub. cadre as a confirmed Peon at any of the office of the Bank at Jhansi. He will be given starting salary of the scale of the sub. staff. He shall be appointed within 30 days of signing this joint memo.

(b) that Shri Mumtaz Khan and his union on his behalf agree and hereby give up all the claims, monetary or otherwise, in respect of the services put in by Shri Mumtaz Khan as a private driver or otherwise in the form of arrears, seniority etc. etc.

(c) that the above settlement has been arrived at having regard to the peculiar circumstances of the cases and would not be cited as a precedent by any of the parties anywhere.

2. The parties pray that the Hon'ble Tribunal may be pleased to pass an Award in terms of the above.

For & on behalf of PNB Employees' Union & All India PNB Staff Federation

(O P GUPTA)
General Secretary

(A. ROY CHOUDHARY)
Manager

Personnel Division HQ : NEW DELHI

Dated : 23-9-1980.

WITNESSES :

(1) Shri Mumtaz Khan (2) Shri C. K. D. Gowda

Workman concerned Sr. Personnel Officer

[No L-12012/121/79-D.II.A]

New Delhi, the 16th October, 1980

S.O. 2991.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bank of Baroda and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th October, 1980.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CALCUTTA

Reference No. 22 of 1978

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bank of Baroda, Calcutta.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

On behalf of Employers.—Mr. Abhijit Mukherjee, Advocate.

On behalf of Workmen.—Mr. T. B. Chhetri, President, Bank of Baroda Employees Association, Gauhati.

STATE : Assam

INDUSTRY : Banking.

AWARD

This reference under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, was referred to this Tribunal for adjudication by the Government of India, Ministry of Labour, vide Order No. L-12011/52/77-D-II.A dated 13th February, 1978. The dispute mentioned in the Schedule to the Order of Reference reads :

"Whether the proposed action of the management of Bank of Baroda in discontinuing payment of temporary additional allowance in respect of their workmen employed in their Gauhati and Shillong branches with effect from 1-11-1976 is legal and justified? If not, to what relief are these workmen entitled?"

2. A joint petition of compromise is filed today by Mr. M. R. Doshi, Regional Manager of Bank of Baroda and Mr. T. B. Chhetri, President of Bank of Baroda Employees Association, Gauhati. I have heard Mr. Abhijit Mukherjee, learned Advocate appearing on behalf of the Bank who has duly filed the power of authority granted by the Bank and also the President of the Union representing the workmen of the Bank. I have also perused the contents of the joint petition of compromise with a copy of settlement attached to it showing a Memorandum of Settlement dated 21st April, 1980 between the Indian Banks Association on the one hand and All India Bank Employees Association and National Confederation of Bank Employees on the other. It is submitted by the parties before me that an award may be passed on the basis of the joint petition of compromise in terms of the Memorandum of Settlement marked Annexure "A" in respect of Assam Allowance payable to the workmen. I find that the petition of compromise is legal and the terms are reasonable.

3. As prayed for by the parties, I pass an award in terms of the joint petition of compromise and the Memorandum of Settlement dated 21st April, 1980, already referred to and marked Annexure "A". Both the joint petition of compromise and Annexure "A" shall form part of this award.

4. I understand that Mr. Chhetri, President of the Union has come from Gauhati by Train in connection with this case and will return tomorrow by Air. Mr. Doshi also, appearing on behalf of the Bank, has agreed to it. In the circumstances, the Bank is directed to sanction special leave with pay to Mr. Chhetri for the period from 29th September, 1980 to 1st October, 1980 inclusive of both the days.

Thus I pass my award.

Calcutta,

The 30th September, 1980.

R. BHATTACHARYA, Presiding Officer.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL
GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

Reference No. 22 of 1978

Employers in relation to the Management of Bank of
Baroda

Vs.

Workmen.

The humble joint petition of the Management and Union,
the petitioners above named—

Most respectfully sheweth—

1. Your petitioners state and contend that the hearing of the above matter was held at Gauhati on September 10, 1979.

2. Your petitioners further state and contend that the dispute with regard to the Assam Allowance has been amicably settled by and between the Indian Banks Association, representing the Management and All India Banks Employees Association, the National Confederation of the Banks Employees and Indian National Bank Employees Congress representing the Workmen outside the Tribunal.

3. The terms and conditions of the said settlement are recorded in the Memorandum of Settlements dated April 21, 1980. Your petitioners crave leave to refer to the said original Memorandum of Settlements at the time of hearing of this application, if necessary.

4. Your petitioners submit that an Award should be passed disposing of the reference pending before the Learned Tribunal on the Terms and Conditions recorded in the said Memorandum of Settlements. A copy of the said Memorandum of Settlement are annexed hereto and marked with the letter "A".

5. Your petitioners further state and submit that an Award be passed in accordance with the Memorandum of Settlements.

Your petitioners, therefore, humbly pray your Honour for an order that :—

(a) An order be made awarding the terms of settlements made by and between the parties as recorded in annexure "A" to the petition.

(b) Such further or other orders be made and or directions be given as your Honour may deem fit and proper.

And for this act of kindness your petitioners as in duty bound shall ever pray.

ANNEXURE 'A'

Memorandum of Settlement dated 21st April, 1980 between
Indian Banks' Association and All India Bank Employees'
Association and National Confederation of Bank Employees.

Name of the parties—58 Banks.

Representing the Employers :

1. Shri K. Venkatachari.
2. Shri N. Vaghul

On behalf of the Indian Banks Association.

Representing the workmen :

1. Shri D. P. Chadha
2. Shri K. K. Mandul
3. Shri Prabhat Kar
4. Shri Tarakeswar Chakraborty
5. Shri N. Sampath.

On behalf of All India Bank Employees' Association.

1. Shri D. P. Gupta
2. Shri C. L. Rajaratnam
3. Shri C. R. Chandrasekaran
4. Shri N. C. Choudhury

On behalf of National Confederation of Bank Employees.

Preamble :

Whereas the Goa Allowance and Assam Allowances paid/payable to the workmen were under discussion between the parties during the Bipartite negotiations.

And whereas there are cases also pending before Tribunals in respect of these allowances.

It is now agreed by and between the parties as under :—

(i) Goa Allowances :

(a) Till 31-8-1978 Goa allowance will be payable to all employees in all banks which were paying Goa Allowance at the rates obtaining in the respective Banks.

(b) From 1-9-1978—

(i) CCA would be payable in the urban agglomeration of Panaji and Matmugao.

(ii) HRA will be payable in accordance with Bipartite Settlement at the places in Goa eligible for the same.

(iii) In respect of employees' covered by (a) above and who continue to be in Goa as on the date of this Settlement, if the aggregate of the HRA and CCA falls short of the Goa Allowance payable to them, such shortfall will be continued to be paid to them from time to time as Goa Allowance.

ASSAM ALLOWANCE :

(a) All employees who were working prior to 31-3-1980 in the Banks where Assam Allowance (by any name) was being paid, the Assam Allowance will be paid till 31-3-1980 at the respective rate.

(b) From 1-4-1980 those employees will continue to draw the allowance at the same rates.

(c) In all other cases, in all banks, the allowance will be paid at a flat rate of Rs. 10 from 1-4-1980.

(d) It is understood that Assam Allowance shall be paid as per clauses (a), (b) & (c) above in other States, Viz., Manipur, Tripura, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh & Mizoram where the said allowance (by any name) was being paid till special area allowances payable in these areas are settled in respect of workmen in these areas.

In respect of the proceedings now pending before the Tribunals in respect of 'Goa Allowance' and 'Assam Allowance' this agreement will be submitted to the respective

Tribunals with the request for a 'Consent Award' those terms.

For Indian Banks' Association

Sd/- K. Venkatachari

Sd/- N. Veghul

For All India Bank Employees Association

Sd/-

D. P. Chadha

Sd/-

Tarakeswar Chakraborty

For National Confederation of Bank Employees

Sd/-

C. L. Rajaratham

Sd./- C. R. Chandrasekaran

Witnesses :

1. M. Ram Mohan Rao

2. N. Sampath

3. R. Sivagyanam

Date : April 21, 1980.

Place : Madras

1. Conciliation Officer (Central) Madras
2. Regional Labour Commissioner (Central), Madras
3. Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi
4. The Secretary to the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi.

[No. L-12011/52/77-D.II-A]

S.O. 2992.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Chartered Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th October, 1980.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

I.D. No. 108 of 1977

In re :

The President, U.P. Bank Employees Federation, 26/104, Birhana Road, Kanpur. —Petitioner.

Versus

The Manager, Chartered Bank, The Mall, Kanpur —Respondent.

AWARD

The Central Government as appropriate Government referred an Industrial Dispute u/s 10 of the I.D. Act, 1947 vide its order No. L-12012/87/73/IR.III dated the 26th December, 1973 to Industrial Tribunal, Kanpur in the following terms:

"Whether the action of the management of Chartered Bank was justified in superseding Shri Jogeshwar Iha, Clerk in the Kanpur office of the said Bank, for promotion to the post of Special Assistant? If not, to what relief is he entitled and from what date?

2. It was registered at No. 16/74 and usual notices were sent to the parties. Whereupon statement of claims were filed by the parties representatives and thereafter written statements were also filed and in course of time before issues could be framed the reference was transferred to Industrial Tribunal, Delhi in the year 1976. Thereafter this reference 827 GI/80—9

was transferred to this Tribunal in 1977. On receipt of the reference it was ordered to be registered and usual notices were sent to the parties. After issues had been framed evidence of the parties was recorded and the case was fixed for arguments. Before arguments could be heard the parties representatives have come forward with the following statement today before me :

"In view of the fact that major relief has already been delivered to the workman, a no dispute award vide documents Ext. M/30, may be made in this reference. Parties to bear costs."

3. In view of the fact that major relief has already been delivered to the workman vide documents Ext. M/20, a no dispute award was delivered to the workman and in view of the statement of the parties representatives re-produced above, a no dispute award is hereby made in this matter laying the parties to bear their own costs.

Further Ordered :

That requisite number of copies of this award may be sent to the appropriate Government for necessary action at their end.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer,

19th September, 1980.

[No. L-12012/87/73-LR.III/D.IIIA]

New Delhi, the 21st October, 1980

S.O. 2993.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of United Commercial Bank, Calcutta and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th October, 1980.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

Reference No. 21 of 1978

PARTIES :

Employers in relation to the management of United Commercial Bank, Calcutta.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

On behalf of Employers.—Mr. Dipak Dey, Advocate.

On behalf of Workmen.—Mr. Subhan Bhakial Phukan, Secretary, United Commercial Bank Employees Association, Assam State Committee.

Mr. Ashoke Ghosh, Vice President, United Commercial Bank Employees' Association, Calcutta.

STATE : Assam

INDUSTRY : Banking.

AWARD

By Order No. L-12011/56/77-D.II.A, dated 13th February, 1978, the Government of India, Ministry of Labour, sent an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of United Commercial Bank, Calcutta and their workmen, to this tribunal for adjudication. The dispute mentioned in the Schedule to the order of Reference reads :

"Whether the proposed action of the management of United Commercial Bank in discontinuing payment of temporary Assam Allowance in respect of their workmen employed in the North Eastern Region with effect from 1-11-1976 is proper and justified? If not, to what relief are these workmen entitled?"

2. In this case both the parties, namely, United Commercial Bank, Calcutta and its workmen represented by the United Commercial Bank Employees Association, Assam State Committee, Gauhati have filed a joint petition of compromise praying for an award in terms of the settlement appearing in Annexures "A" and "B" to the petition. The joint petition of compromise is signed by the Deputy General Manager on behalf of the United Commercial Bank and Santi Ranjan Bal, General Secretary of the United Commercial Bank Employees Association and also Subhan Bhakial Phukan, Secretary of

the United Commercial Bank Employees Association, Assam State Committee, Gauhati. Annexure "A" to the petition is a Memorandum of Settlement dated 21st April, 1980 between the Indian Banks Association on the one hand and All India Bank Employees Association and National Confederation of Bank Employees on the other. Annexure "B" is a Memorandum of Settlement dated 15th July, 1980 between Indian Banks Association and Indian National Bank Employees Congress. There are certain terms in both the Annexures in respect of Goa allowance and Assam allowance. In the present case the parties pray for an award in terms of Assam allowance appearing in the Annexures. The term about Assam allowance in both the Annexures is the same.

3 I have heard Mr. Dipak Dev, learned Advocate appearing on behalf of the Bank and Mr. Subhan Dhekial Phukan, Secretary of the Assam State Unit of the Employees Association. They have prayed that it would be sufficient if an Award is passed in terms of Annexure "A" relating to Assam Allowance and there is no use mentioning about Annexure "B" which includes the same terms.

4 I find that the petition of compromise is reasonable and legal. As prayed for by the parties, I pass an Award on the basis of the joint petition of compromise and the Annexure "A" referred to therein, both of which shall form part of this award.

5 Mr. Phukan has come from Assam for the purpose of this case. He is certainly entitled to leave for his journey from Assam to Calcutta and from Calcutta to Assam again. For this purpose the Bank shall sanction special leave on pay from 29th September to 1st October, 1980, inclusive of both the days.

Dated, Calcutta,

Tue 29th September, 1980

R. BHATTACHARYA, Presiding Officer

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL
GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL
CALCUTTA

Reference No. 21 of 1978

Employers in relation to the Management of United
Commercial Bank,

Vs.

Its workmen.

The humble joint petition of the Management and Union, the petitioners abovenamed—

Most respectfully sheweth—

1. Your petitioners state and contend that the hearing of the above matter was held at Gauhati on September 10, 1979.

2. Your petitioners further state and contend that the dispute with regard to the Assam Allowance has been amicably settled by and between the Indian Banks' Association, representing the Management and All India Banks Employees' Association, the National Confederation of the Banks Employees and Indian National Bank Employees Congress representing the workmen outside the Tribunal.

3. The terms and conditions of the said settlements are recorded in the Memorandum of Settlements dt. April 21, 1980 and 15-7-1980. Your petitioners crave leave to refer to the said original Memorandum of Settlement at the time of hearing of this application, if necessary.

4. Your petitioners submit that an Award should be passed disposing of the reference pending before the learned Tribunal on the terms and conditions recorded in the said Memorandum of Settlements. A copy of the said Memorandum of Settlements are annexed hereto and marked with the letter "A", and "B".

5. Your petitioners further state and submit that an award be passed in accordance with the Memorandum of Settlements. Your petitioners, therefore, humbly pray your honour for an order that—

- (a) An order be made awarding the terms of settlements made by and between the parties as recorded in annexure "A" and "B" to the petition.
- (b) Such further or other orders be made and or directions be given as your Honour may deem fit and proper;

And for this act of kindness your petitioners as in duty bound shall ever pray

ANNEXURE A

Memorandum of Settlement dated 21st April, 1980 between Indian Banks' Association and All India Bank Employees' Association and National Confederation of Bank Employees

Name of the parties : 58 Banks

Representing the Employers : 1. Shri K. Venkatachari

2. Shri N. Veghul

On behalf of the Indian Banks' Association

Representing the workmen :

1. Shri D. P. Chadha

2. Shri K. K. Mandul

3. Shri Prabhat Kar

4. Shri Tarakeswer Chakraborty

5. Shri N. Sampath

On behalf of All India Bank Employees' Association

1. Shri O. P. Gupta

2. Shri C. L. Rajaratnam

3. Shri C. R. Chandrasekaran

4. Shri N. C. Choudhury

On behalf of National Confederation of Bank Employees.

Preamble Whereas the Goa Allowance and Assam Allowances paid/payable to the workmen were under discussion between the parties during the Bipartite negotiations

And whereas there are cases also pending before Tribunals in respect of these allowances.

It is now agreed by and between the parties as under :—

(1) Goa Allowance .

(a) Till 31-8-1978 Goa Allowance will be payable to all employees in all banks which were paying Goa Allowance at the rates obtaining in the respective Banks.

(b) From 1-9-1978—

(i) CCA would be payable in the urban agglomeration of Panaji and Marmugao.

(ii) HRA will be payable in accordance with Bipartite Settlement at the places in Goa eligible for the same.

(iii) In respect of employees covered by (a) above and who continue to be in Goa as on the date of this Settlement, if the aggregate of the HRA and CCA falls short of the Goa Allowance payable to them, such shortfall will be continued to be paid to them from time to time as Goa Allowance.

(2) Assam Allowance :

(a) All employees who were working prior to 31-3-1980 in the Banks where Assam Allowance (by any name) was being paid, the Assam Allowance will be paid till 31-3-1980 at the respective rates.

(b) From 1-4-1980 those employees will continue to draw the allowance at the same rates.

(c) In all other cases, in all banks, the allowance will be paid at a flat rate of Rs. 10 from 1-4-1980.

(d) It is understood that Assam Allowance shall be paid as per clauses (a) (b) and (c) above in other States, viz. Manipur, Tripura, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram where the said allowance (by any name) was being paid till special area Allowances payable in these areas are settled in respect of workmen in these areas.

In respect of the proceedings now pending before the Tribunals in respect of 'Goa Allowance' and 'Assam Allowance', this agreement will be submitted to the respective Tribunals with the request for a 'Consent Award' on these terms.

For Indian Banks' Association

K. Venkatachari Sd/-

N. Vaghul Sd/-

For All India Bank Employees' Association

D. P. Chadha Sd/-

Tarakeswar Chakraborty Sd/-

For National Confederation of Bank Employees

C. J. Rajarathnam Sd/-

C. R. Chandrasekharan Sd/-

Witnesses.

1. M. Ram Mohan Rao Sd/-

2. N. Sampath Sd/-

3. R. Sivagyanam Sd/-

Dated : April 21, 1980
Place : Madras

(No. L-12011/56/77-D.II-A)

S. H. S. IYER, Desk Officer

New Delhi, the 16th October, 1980

S.O. 2994—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Bombay in the matter of an

Application under Section 33A of the Industrial Disputes Act, 1947 filed by **Shri Arvind Ratilal Vora** against the management of New India Assurance Company Limited, Bombay which was received by the Central Government on the 10th October, 1980.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, BOMBAY

Complaint No. CGIT-2 of 1977

(Arising out of Reference No. CGIT-1 of 1977)

PARTIES :

Arvind Ratilal Vora, Irla Bldg.,

Block No. A/12, Society Rd.,

Bombay-56.

Complainant.

V/s.

The New India Assurance Co. Ltd.,

87, M.G. Road,

BOMBAY-400023.

: Opp. Party

APPEARANCES :—

For the Complainant—Mr. C.L. Dudhia, Advocate

For the Opposite Party—Mr. G.V. Pavaskar, Advocate

INDUSTRY : Insurance

STATE : Maharashtra

Bombay, dated the 22nd September, 1980.

AWARD

This is a complaint under Section 33A of the Industrial Disputes Act, 1947 (in the matter of Reference No. CGIT-1 of 1977) complaining the order of discharge passed against him.

2. The complainant wants to withdraw the complaint. He says that he is trying for Reference on that point. That could be done to the best of the advice he receives. The Tribunal given no directions. The Complainant is allowed to be withdrawn.

3. No order as to costs.

C. T. DIGHE, Presiding Officer

[No. L-31014/1/80-D IV(A)]

NAND LAL, Desk Officer

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the existence of a solution of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β . It is shown that the system of equations (1) has a solution for arbitrary values of the parameters α and β if and only if the condition

is satisfied.